राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

शास्त्री के लिए कोहली ने तोड़ा प्रोटोकॉल
>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 53

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

जंगल बनाने में जुटे चंबल के चार डॉक्टर

ग्वालियर : चंबल के ये चार डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाने

की नौबत आए। वे भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। नहीं चाहते कि आने वाले समय में लोगों को बोतलबंद ऑक्सीजन का मोहताज होना पड़े। लिहाजा, जल्द से जल्द घना जंगल बसा देने में जुटे हुए हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

ये है गौरांग महाप्रभु का बैंक, जिसे जरूरत हो ले ले पैसे

धनबाद : न गारंटर की जरूरत, न ब्याज देने की बाध्यता। और ना ही पैसे लौटाने का

दबाव। हां, दहेज लिया तो दंड के रूप में ली जाती है रकम। धनबाद के ओझाडीह गांव में चलता है सौ साल पुराना अनोखा बैंक। सारा खेल आस्था पर टिका है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

राज्यसभा ने नए एनएमसी में राज्यों को दी तरजीह

नई दिल्ली : प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने राज्यसभा में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला पारित किया है। लोकसभा से पारित एनएमसी बिल में राज्यसभा ने तीन संशोधन किए हैं। इससे 25 सदस्यीय एनएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़कर 33 होना शामिल है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

ईडी ने आजम खां के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

लखनऊ : सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम खां के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

क्रिसिल ने भी जीडीपी विकास दर अनुमान घटाया

नई दिल्ली : देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए आर्थिक विकास दर अनुमान घटा दिया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर अनुमान 20 आधार अंक कम करते हुए 6.9 फीसद रखा है। इस कटौती के लिए क्रिसिल ने मानसून के पर्याप्त नहीं होने और वैश्विक मंदी को सबसे प्रमुख कारण बताया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

मारा गया ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा

वाशिंगटन : अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा (30) भी मारा गया। हमजा ने अपने पिता की मौत का बदला देने के लिए कई बार अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। यह हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि अलकायदा के उत्तराधिकारी माने जा रहे हमजा को कब और कहां ढेर किया गया। उसके पिता ओसामा को अमेरिका ने मई, 2011 में पाक के एबटाबाद में मार गिराया था।

दिल्ली में चलेंगे सारे केस, 45 दिन में इंसाफ

उन्नाव कांड ▶ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को रायबरेली सड़क हादसे की जांच सात दिन में पूरी करने को कहा

पीड़िता की चिट्ठी और उसकी मां की याचिका पर दिए आदेश, आज फिर सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म कांड में जल्द और पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पीड़िता की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे लखनऊ की सीबीआइ अदालत से दिल्ली की अदालत स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को हुई दुर्घटना मामले की जांच सीबीआइ को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि बहुत जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी सात दिन और ले सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद समझा जाए।

कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीड़िता की मां को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। इसके बाद देर रात लखनऊ के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा और एसएसपी कलानिधि

- पीड़िता और उसके परिजनों को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का निर्देश
- यूपी सरकार ने पीड़िता की मां को सौंपा 25 लाख रुपये का चेक
- सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर आज भी होगी सुनवाई

नैथानी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और 25 लाख रुपये का चेक पीड़िता की मां को सौंप दिया। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा भी प्रदान कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई अभियुक्त हैं। गत रविवार को सड़क दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना से पहले पीड़िता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी भेजकर अभियुक्तों पर धमकी देने और सुलह के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी। इसी चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी किए।

तीसहजारी में जिला जज धर्मेश की अदालत में स्थानांतरित : कोर्ट ने पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमों का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने की मांग स्वीकारते हुए दुर्घटना सहित मामले से जुड़े सभी पांचों मुकदमे दिल्ली की तीसहजारी में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में स्थानांतरित कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एकतरफा सुनवाई में ये आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अभियुक्तों को आदेश में बदलाव कराने की मांग कोर्ट के सामने रखने की छूट होगी।

यह क्या हो रहा है, हम अपनी ड्यूटी में फेल हैं : सीजेआइ

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) ने पूरी घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह क्या हो रहा है। हम अपनी ड्यूटी में फेल हैं। कोर्ट रजिस्ट्री के विधायी व्यवस्था का जिक्र करने पर कहा, यह क्या घटित हो रहा है और आप कोर्ट से कानून के चौखाने में फिट मुआवजे का आदेश देने की बात कर रहे हैं।

परिवार चाहे तो पीड़िता व वकील को इलाज के लिए दिल्ली भेज सकते हैं : कोर्ट ने दुर्घटना में घायल पीड़िता और वकील का इलाज कर रहे लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पूछा था कि क्या दोनों की हालत ऐसी है कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया जा सके। कोर्ट को बताया गया कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें एयर लिफ्ट करके स्थानांतरित करने की स्थिति है। कोर्ट ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए स्थानांतरित करने पर पीड़िता व घायल वकील के परिवार की राय पूछी है। इसके बाद कोर्ट इस पर आदेश देगा।

आज दाखिल होगी सीआरपीएफ सुरक्षा पर अनुपालन रिपोर्ट : कोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि वह पीड़िता, उसकी मां और भाई-बहनों के अलावा चाचा के परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा दे। सुरक्षा तत्काल दी जाए और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट को दी जाए।

पीड़िता के चाचा को दिल्ली जेल स्थानांतरित करने पर जवाब आज : प्रदेश सरकार शुक्रवार को कोर्ट को बताएगी कि क्या सुरक्षा कारणों से पीड़िता के चाचा को रायबरेली की जेल से दिल्ली जेल स्थानांतरित किया जा सकता है। पीड़िता के चाचा को अभियुक्तों के साथ मारपीट से जुड़े 2001 के विवाद में हत्या के प्रयास के आरोप में सजा हुई है। उसकी पत्नी की भी रविवार को हुई दुर्घटना में मौत हो गई है और उसके अंतिम संस्कार के लिए वह फिलहाल पैरोल पर है।

पीड़िता की चिट्ठी सीजेआइ के सामने पेश करने में हुई देरी की जांच का आदेश पेज>>6

भाजपा से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर

लखनऊ : उन्नाव दुष्कर्म कांड व रायबरेली हादसे के आरोपों से घिरे विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने गुरुवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार देर शाम कहा कि पहले से ही निलंबित चल रहे विधायक को अब पार्टी से निकाल दिया गया है।

कश्मीर में 280 और कंपनियों को तैनात किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की 280 और कंपनियां (28000 जवान और अधिकारी) तैनात की जा रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य में सौ अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने की घोषणा की गई थी।

जम्मू संभाग में ही नहीं, घाटी में भी कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से सीआरपीएफ (सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल) को मुक्त कर उसके स्थान पर एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) और बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ को पूरी तरह आतंकरोधी अभियानों और कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी में लगाया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर समेत पूरी घाटी में सभी संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात किया जा रहा है। हालांकि राज्य पुलिस या गृह विभाग ने इस विषय में किसी तरह की कोई जानकारी या बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक ही अर्धसैनिक बलों की 280 कंपनियों की तैनाती से हलचल और अफवाहों का दौर फिर तेज हो गया है। श्रीनगर शहर के साथ घाटी के अन्य प्रमुख शहरों व कस्बों में आने-जाने के सभी रास्तों पर केंद्रीय अर्धसैनिकबलों को तैनात कर दिया गया है। हाईवे पर अस्थायी नाकों और चौकियों की संख्या बढ़ गई है। कुछ कंपनियों को कठुआ के उच्चपर्वतीय इलाकों में और मुगल रोड पर स्थित राजौरी-पुंछ में भी तैनात किया गया है। इसके अलावा आइटीबीपी की कुछ टुकड़ियों को जवाहर सुरंग के आसपास के इलाके में भी तैनात करने की चर्चा है।

दिल्लीवालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा एलान
- नई घोषणा पर 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी सरकार

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्रंप कार्ड खेलते हुए दिल्ली में प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने का एलान किया है। यही नहीं, अगर आप 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो भी आपको आधा बिल ही भरना होगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला तुरंत लागू भी कर दिया है। इस घोषणा से करीब 33 लाख घरों को फायदा पहुंचेगा। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केजरीवाल ने यह घोषणा की। इस नई घोषणा पर दिल्ली सरकार लगभग 600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी।

केजरीवाल ने बताया कि मुफ्त बिजली को लेकर सब्सिडी करीब-करीब उतनी ही है, जितनी पिछले सालों में दी जाती रही है। हर साल हमारा सब्सिडी का बिल 1,800 से 2,000 करोड़ के बीच होता है। इसलिए सब्सिडी बिल में खास वृद्धि की उम्मीद नहीं है। उसी सब्सिडी को हमने इस साल रिस्ट्रक्चर किया है।

मंत्रियों, सांसदों की तरह आम आदमी को भी मुफ्त बिजली: सीएम ने कहा कि हमारे देश के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के लिए बिजली मुफ्त है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर एक आम आदमी 24 घंटे मेहनत करके अपना परिवार चलाता है, उसको मैं वही सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं। एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा, इस समय करीब 35 फीसद उपभोक्ता हैं जो प्रतिमाह 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। सर्दियों में यह फीसद लगभग 70 तक पहुंच जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पहले हर साल बिजली की दरों में इजाफा कर दिया जाता था।

200 यूनिट से ज्यादा होने पर यह है नियम : सरकार के फैसले के बाद काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर 200 से एक यूनिट भी ज्यादा खपत हुई तो क्या होगा? ऐसे में आपको बता दें कि यहां 2015 में बना नियम ही काम करेगा कि 200 से ऊपर यूनिट होने पर पूरे बिल का आधा आपको देना होगा। उदाहरण के तौर पर 300 यूनिट होने पर 150 यूनिट का बिल भरना होगा।

भाजपा ने सरकार की घोषणा को बताया चुनावी स्टंट

दिल्ली सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त करने की घोषणा को भाजपा ने चुनावी स्टंट करार दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, वह सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को स्थायी शुल्क के नाम पर दिल्लीवालों से वसूले गए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये भी वापस करने होंगे। पैसे वापस दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, आप सरकार ने दिल्लीवासियों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अब नाकामी छिपाने के लिए चुनाव से पहले मुफ्त का पिटारा खोल रहे हैं। वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने बजट में इसके लिए पहले से कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि किस मद से यह राशि खर्च करेंगे? (संबंधित खबरें पेज-2 पर)

जाधव को भारतीय राजनयिक से मिलाने पर पाक राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पाकिस्तान के सशर्त प्रस्ताव पर भारत कर रहा है विचार, आज पाक राजनयिक की मौजूदगी में मुलाकात की पेशकश की

कुलभूषण जाधव

पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) देने का फैसला तो कर लिया है लेकिन इसमें पेंच लगाने से बाज नहीं आया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले के दो हफ्ते बाद पाक ने सशर्त प्रस्ताव भेजा है। आइसीजे के फैसले के मुताबिक पाक को जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने की इजाजत देनी है। माना जा रहा है कि पाक ने शुक्रवार (2 अगस्त, 2019) को ही इस मुलाकात का प्रस्तावित समय भेजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। जल्द ही जवाब दे दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक पाक के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम राजनयिक चैनल पर इसका जवाब उचित समय पर देंगे।' कुमार ने स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने जिन शर्तों के साथ 49 वर्षीय जाधव को भारतीय राजनयिकों से मिलने का प्रस्ताव रखा है, उसको लेकर भारत की अपनी आपत्तियां हैं। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक वहां की सरकार ने यह शर्त रखी है कि मुलाकात में भारत की तरफ से दो राजनयिक रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान का एक राजनयिक भी मौजूद रहेगा। चूंकि आइसीजे के आदेश में किस तरह से मुलाकात करवाई जाएगी, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए पाकिस्तान सरकार ऐसा प्रस्ताव कर सकती है। अब देखना है कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। सनद रहे कि आइसीजे ने 17 जुलाई को अपने आदेश में यह कहा था कि पाकिस्तान सरकार फांसी की सजा पाये कुलभूषण जाधव को जेनेवा समझौते के तहत सारे अधिकार दे। इसके तहत उसे भारतीय राजनयिक की पहुंच देने का भी आदेश दिया गया था। वैसे इस आदेश से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से 16 दफे इस बात का आग्रह कर चुकी थी कि उसे जाधव से अपने राजनयिकों से मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनका जवाब तक नहीं दिया। जाधव की मां और पत्नी को मिलने की इजाजत जरूर दी लेकिन उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया। कैमरे के आगे मुलाकात कराई और जाधव की पत्नी और मां की बिंदी, मंगलसूत्र और चप्पलें तक उतरवा लीं।

आइसीजे के आदेश को भी पाक ने अपनी जीत के तौर पर दर्शाया था। जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा दे रखी है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव एक भारतीय खुफिया एजेंट है जो वहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत का कहना है कि जाधव पूर्व नौसेना अधिकारी है जो अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान में था और वहां से उसका अपहरण कर उसे पाकिस्तान ले जाया गया है।

पाक का एक और 'भारतीय जासूस' पकड़ने का दावा

लाहौर, प्रेट्र : पाक में पंजाब प्रांत की पुलिस ने डेरा गाजी खान कस्बे में कथित रूप से राजू लक्ष्मण नाम के 'भारतीय जासूस' को पकड़ने का दावा किया है। भारत ने इस बात का खंडन किया है। (पेज-11)

बिना दस्तावेज आए मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति से पूछताछ

तूतीकोरिन, प्रेट्र : मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर गुरुवार को समुद्री मार्ग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचे। सूचना मिलने पर केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गईं और उन्होंने गफूर से पूछताछ शुरू की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गफूर बिना वैध दस्तावेजों के गलत तरीके से भारत में आए हैं। उनसे इस बाबत पूछताछ की गई है। उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

जिला स्तर के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जहाज से आए गफूर अभी बंदरगाह की धरती पर नहीं उतरे हैं। सूचना पर आए केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे भारत आने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारी के अनुसार गफूर के आने की कोई सूचना उनके पास नहीं थी। जो जहाज उन्हें लेकर आया है उसके नौ सदस्यीय चालक दल को भी रोक लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि देश में विदेशियों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग से गफूर भारत नहीं आए हैं। उनके इस तरह से भारत आने की अनुमति नहीं थी। पूछताछ में पता चला है कि उनके

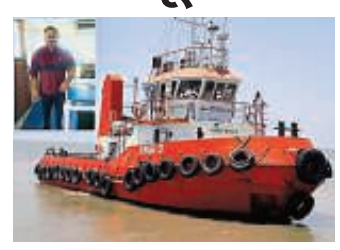

पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीबा को तूतीकोरिन में इसी नौका से पकड़ा गया था। एएनआइ

पास निर्धारित यात्रा दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए अब उन्हें भारत में रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें वापस कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मालदीव हिंद महासागर के बीच भारत का मित्र देश है। वहां पर चीन भी अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है। कई साल राजनीतिक उठापटक के बाद वहां पर इसी साल लोकतंत्र की बहाली हुई है। वहां की राजनीतिक स्थिति बहुत संवेदनशील है। इस लिहाज से भारत सरकार ने सोच-समझकर इस मामले में फैसला किया है।

अयोध्या विवाद के मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, आज होगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में गुरुवार को उत्तर प्रदेश सदन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर। प्रेट्र

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। कोर्ट मामले पर शुक्रवार को विचार करेगा और रिपोर्ट देखकर आगे की कार्यवाही पर फैसला लेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण व एस अब्दुल नजीर हैं।

तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रेजिस्ट्री को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिये सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से 31 जुलाई तक मध्यस्थता में हुई प्रगति पर एक अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की ओर से गुरुवार को दोपहर बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था। इसलिए रिपोर्ट के तथ्यों को रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा।

क्या है मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू, मुस्लिम सभी पक्षों ने अपील दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है। इस बीच गत 8 मार्च को कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए भेज दिया था और तीन सदस्यों का मध्यस्थता पैनल गठित किया था। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमई कलीफुल्ला हैं जबकि आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू सदस्य हैं।

कोर्ट ने शुरू में मध्यस्थता के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था जिसे बाद में पैनल के अनुरोध पर बढ़ा कर 15 अगस्त तक कर दिया था। इस बीच मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता में कुछ ठोस प्रगति नहीं हुई है और इससे विवाद का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर अपीलों पर जल्दी सुनवाई शुरू करे। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 11 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी थी और 18 जुलाई की रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय देते हुए एक अगस्त को फिर रिपोर्ट देने को कहा था।

आइबीसी बिल पर लगी मुहर

आइबीसी संशोधन विधेयक संसद से पारित, वित्त मंत्री बोलीं सरकार फ्लैट खरीदारों के सभी मामलों पर सक्रियता से कर रही विचार, सभी पक्षों को स्वीकार करनी होगी अनुमोदित योजना

330 दिनों में निपटानी ही होगी दिवालिया प्रक्रिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में चर्चा का जवाब देतीं निर्मला सीतारमण।

कंपनियों की दिवालियापन प्रक्रिया 330 दिनों में पूरी करने के प्रावधान के साथ संसद ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। लोकसभा में गुरुवार को सभी सात संशोधनों के साथ यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट कंपनियों में फंसे फ्लैट खरीदारों को भी भरोसा दिया कि यह कानून उनकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। सरकार फ्लैट खरीदारों से जुड़े सभी मामलों, जिनमें जेपी इन्फ्रा का मामला भी शामिल है, पर सक्रियता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फ्लैट खरीदारों के हित में जितना कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

राज्यसभा इसे सोमवार को ही पारित कर चुकी है। संशोधन विधेयक में डिफॉल्टिंग कंपनियों के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को समाधान योजना से मिलने वाली राशि के वितरण पर स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। साल 2016 में आइबीसी कानून बनने के बाद यह तीसरा मौका है जब सरकार ने इस कानून में संशोधन किए हैं। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपने शुरुआती ढाई साल में यह विधेयक काफी प्रभावी रहा है। इसका असर कॉरपोरेट जगत पर भी दिखा है। विधेयक में कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित समस्त प्रक्रिया को निपटाने के लिए 330 दिन का समय निश्चित किया गया है। इस समय सीमा में मुकदमेबाजी का चरण और न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल है। पहले इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए 270 दिनों की समय सीमा निर्धारित थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सरकार इस अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन लाई। पुराने कानून में कुल सात संशोधन किए गए हैं। मंत्री ने साथ ही कहा कि मंजूर होने वाली समाधान योजना केंद्र व राज्य सरकारों और विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब यह देश डिफॉल्टर्स का स्वर्ग नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष बकाया मामलों की अधिक संख्या के बारे में सीतारमण ने कहा कि इनमें से 73 फीसद मामले ऐसे हैं, जो पहले से बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआइएफआर) में थे और बीते कई वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे थे।

बढ़ेगी एनसीएलटी की क्षमता : उन्होंने कहा कि सरकार एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सरकार एनसीएलटी की बेंच की संख्या को 10 से बढ़ाकर 15 करना चाहती है। उन्होंने बताया कि 335 मामले ऐसे हैं, जो 330 दिनों की सीमा पार कर चुके हैं। 445 मामले ऐसे हैं, जिनमें 270 दिन से अधिक हो गए हैं। जिन 475 मामलों में कंपनियों को बिक्री के लिए भेजा गया है, उनकी कीमत 24,417 करोड़ रुपये है। जबकि इन मामलों में दावा 3,46,655 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने कहा कि आइबीसी में सीमा पार इन्सॉल्वेंसी को भी शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा जारी है। सरकार संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करने के बाद कोई फैसला करेगी।

अब यह होगा

- कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को समाधान प्रक्रिया से मिली रकम के बंटवारे का अधिकार होगा
- एनसीएलटी को बताना होगा कि किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार करने में देरी की वजह क्या रही
- केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी वैधानिक प्राधिकरणों को समाधान योजना स्वीकार्य होगी
- बोलीकर्ताओं के लिए समाधान योजना से पीछे हट जाना आसान नहीं होगा

22 तक चलेगी हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच चलने वाली कोटा सुपरफास्ट विशेष ट्रेन। यह ट्रेन सुबह सवा पांच बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होकर दोपहर सवा एक बजे कोटा पहुंचती है। वापसी में कोटा से रात 8.20 बजे चलकर सुबह सवा तीन बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 अगस्त 2019

बोले मुख्यमंत्री ▸ हमारी कड़ी मेहनत और साफ नीयत से ही बिजली बिलों में आई गिरावट, बिजली के क्षेत्र में ढांचागत स्तर पर भी हुआ है जबरदस्त सुधार

बिजली बिल न बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं : केजरीवाल

सीएम का दावा, बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत अच्छी है, कम हो रहे हैं घाटे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान बिजली का बिल बढ़ने की बजाय घटा है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारी कड़ी मेहनत और साफ नीयत से ही बिजली बिलों में गिरावट आई है। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बिजली के बिल न बढ़े हों और हर साल न बढ़ते हों। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत आज बहुत अच्छी है। उनके घाटे कम हो रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में ढांचागत स्तर पर भी जबरदस्त सुधार हुआ है। पूरी दिल्ली में बड़े स्तर पर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और तारें बदली गई हैं। हमने पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया है। बिजली कटौती बंद हो गई है।

दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब हमने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, तब ब्लैक आउट होने वाला था। अब बड़ी मेहनत और साफ नीयत से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त हो गई है। 201 से 400 यूनिट तक लगभग 50 फीसद सब्सिडी दी जा रही है। इससे ऊपर भी बिजली काफी सस्ती हो गई है। यह चमत्कार केवल और केवल दिल्ली के लोगों की वजह से हुआ है क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को वोट दिया था।

बिजली को लेकर 15 दिनों का किया था अनशन : केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी तो बिजली क्षेत्र का बहुत बुरा हाल था। गड़बड़ियों के खिलाफ हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। मार्च 2013 में मैंने 15 दिन का अनशन किया था। दिल्ली में हम जहां भी जाते थे, लोग हमें अपने बिजली के बिल दिखाते थे। 200 व 300 यूनिट के बिजली खपत पर हजारों रुपये के बिल आया करते थे। लोग कहते थे कि बच्चों को पढ़ाएं, रोटी खाएं या बिजली के बिल भरें।

बिजली खरीदने के लिए नहीं थे पैसे : केजरीवाल ने कहा कि जब हम पहली बार 49 दिन के लिए सत्ता में आए थे तब बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने फरवरी 2014 को बोल दिया था कि अगर आज दिल्ली सरकार ने इतने करोड़ नहीं दिए तो कल पूरी दिल्ली के अंदर ब्लैक आउट होने वाला है। कल की बिजली खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब हमने सत्ता संभाली तब मोटे तौर पर चार समस्याएं बहुत बड़ी थीं। पहली समस्या, हर साल बिजली के बिल अनाप-शनाप बढ़ाए जाते थे। दूसरी, बिजली कंपनियां कंगाली के कगार पर थीं। तीसरी, पूरी दिल्ली के अंदर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुका था। कई साल से ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले गए थे। चौथी समस्या, दिल्ली में भारी बिजली कटौती हो रही थी।

हम पैसे नहीं खाते, जो पैसे बचते हैं उसे आपको दे रहे हैं : अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली में मिल रही है। हमारा मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वह पानी नहीं पिएगा। क्या वह बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। हम पैसे नहीं खाते। जो पैसे बचते हैं, हम उनको ही आपको दे रहे हैं।

फ्री पानी की तरह बिजली भी बचाएंगे दिल्लीवाले : केजरीवाल ने कहा कि पानी के मामले में पहले कुछ लोग कहते थे कि अगर हम 20 हजार लीटर पानी फ्री कर देंगे तो लोग पानी बर्बाद करेंगे। लेकिन देखने में आया कि पानी की बचत होने लगी क्योंकि जो 21 या 22 हजार लीटर पानी खर्च करता था वह सोचने लगा कि अगर मैं 20 हजार तक ही खर्च करूं तो मेरी भी बचत हो जाएगी। उसी तरह से बिजली के मामले में होगा। जो लोग 210 यूनिट या 300 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं, वे भी सोचेंगे कि अगर बिजली खर्च 200 यूनिट से नीचे आ जाए तो मेरा भी बिल जीरो हो जाएगा। इससे बिजली की बचत को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली पर जो 6,400 से 7,400 मेगावाट लोड हो गया है, उस पर भी लगाम लगेगी।

जादूगर हैं केजरीवाल, उन्हें आता है गुमराह करना : हारून यूसुफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं, उन्हें जनता को गुमराह करना आता है। यह कहना है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ का। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से पिछले एक साल चार माह में फिक्स चार्ज और पेंशन फंड के नाम पर करीब 7400 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में हमने उसे वापस करने को कहा तो केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं की टैरिफ कैसे बढ़ गए? कहा कि दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज का भार छह गुना बढ़ा दिया। 3.8 फीसद पेंशन और आठ फीसद सरचार्ज लगा दिया है। हमने मांग रखी थी कि इसे जल्द वापस लिया जाए। वहीं सस्ती बिजली के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय भी यही दाम थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सस्ती बिजली खरीदती है। कांग्रेस सरकार की वजह से ही अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। हारून ने कहा कि केजरीवाल मीटर पर चढ़कर सत्ता तक आए थे। अब वह यह बताते नहीं कि कौन सा मीटर तेज भाग रहा है।

देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में

शहर	किसकी सरकार	2 केवी 200 यूनिट	2 केवी 400 यूनिट	प्रति यूनिट दर
मुंबई	भाजपा	1400	3310	3.08 रुपये
बेंगलुरु	भाजपा	1350	2910	2.71 रुपये
कोलकाता	टीएमसी	1380	3079	2.86 रुपये
हैदराबाद	टीआरएस	882	2307	2.15 रुपये
दिल्ली	आप	0	1075	--
गुरुग्राम	भाजपा	910	1820	1.69 रुपये
नोएडा	भाजपा	1310	2480	2.31 रुपये
पटना	जेडीयू-भाजपा	1310	2950	2.74 रुपये
भोपाल	कांग्रेस	1200	2430	2.26 रुपये
अमृतसर	कांग्रेस	1318	2697	2.51 रुपये
अजमेर	कांग्रेस	1588	3277	3.05 रुपये

इतनी बिजली की खपत करेंगे दिल्लीवासी तो अब आएगा जीरो बिल बिल (रुपये में)

लोड	यूनिट	बिल-2013	वर्तमान बिल	नया बिल
1 केवी	200 यूनिट	928	477	0
2 केवी	200 यूनिट	928	622	0
3 केवी	200 यूनिट	993	820	0
4 केवी	200 यूनिट	993	983	0
5 केवी	200 यूनिट	993	1146	0

आप के दांव से दिल्ली की सियासत में दौड़ा करंट

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ भाजपा और कांग्रेस नहीं रख पा रहे पुख्ता तर्क

बिजली हाफ, पानी माफ के नारे से आगे बढ़ते हुए अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पानी-बिजली दोनों माफ का जो दांव खेला है, उससे दिल्ली की सियासत में भी करंट दौड़ गया है। एक दिन पहले तक जहां आप के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस अलग-अलग बिंदुओं पर सरकार को घेर रहे थे, वहीं अब कोई पुख्ता तर्क नहीं रख पा रहे हैं। और तो और इन दोनों दलों को दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति बदलने पर भी सोचना पड़ रहा है।

लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही हौसले बुलंद थे। इस चुनाव में भाजपा को 56.6, कांग्रेस को 22.4 और आप को 18.2 फीसद वोट मिले। 2014 के मुकाबले आप का वोट फीसद 32 से घटकर 18 पर आ गया, जबकि कांग्रेस का वोट फीसद 15 से बढ़कर 22.4 पर और भाजपा का 46 से बढ़कर 56.6 फीसद पर पहुंच गया। आलम यह रहा कि सात लोकसभा क्षेत्रों की 70 विधानसभाओं में से भाजपा सभी 70 जगहों पर नंबर एक रही ही, जबकि 65 विधानसभाओं में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही यानी आम आदमी पार्टी अधिकांश जगह नंबर तीन पर पहुंच गई। इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने जहां 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी कर ली, वहीं कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के लिए शीला दीक्षित के 15 साल लंबे कार्यकाल में हुए विकास का तानाबाना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन आप के इस नए दांव से दोनों पार्टियों को रणनीति पर विचार करने को मजबूर होना पड़ जाएगा। दिल्ली के सियासी इतिहास में इस तरह की बिल माफ करने की योजना पहली बार सामने आई है। आम आदमी पार्टी का यह प्रयोग सीधे मतदाता को आकर्षित कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुकाबला टक्कर का ही रहेगा।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो बिजली और पानी का मुद्दा कमोबेश हर दिल्लीवासी से जुड़ा है। स्कूल और अस्पताल तो फिर भी हर घर से जुड़े नहीं हो सकते, लेकिन बिजली-पानी का बिल सभी भरते हैं इसीलिए दिल्ली सरकार की इस नई घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब भाजपा और कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। बीते समय में क्या किया, क्या नहीं, इससे अधिक मायने रखेगा वर्तमान और भविष्य।

न्यूज गैलरी

मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ समन जारी

नई दिल्ली : भाजपा नेताओं के खिलाफ विवादित ट्वीट करने के मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। विशेष अदालत ने अरविंद केजरीवाल को सात अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। पिछले साल सितंबर में केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, जिसमें दुष्कर्म के मामलों को भाजपा नेताओं से जोड़ा गया था। इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट से भाजपा के सभी नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की है। अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। (जासं)

क्लास में क्यों न लगे सीसीटीवी : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : कक्षा में सीसीटीवी लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर क्लास के अंदर क्या विशेष गोपनीयता उपलब्ध है कि वहां पर सीसीटीवी लगाने से रोका जाए। पीठ ने याचिकाकर्ता को इस टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करने को कहा और अगली सुनवाई के दिन अपना पक्ष रखने को कहा। हालांकि पीठ ने क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे के लगाने पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा था कि कैमरे की फुटेज किसी के भी हाथ लग सकती है जिससे छात्रों के साथ आपराधिक घटनाएं होने की आशंका है। (जासं)

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली : शुक्रवार से दिल्ली का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और बारिश का दौर दोबारा शुरू होगा। यह दौर पूरे एक सप्ताह तक बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के बाद अगस्त में बारिश कुछ बढ़ने की संभावना है। इसी सिलसिले में शुक्रवार और शनिवार के लिए मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसमें हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होती है। इसके बाद भी मंगलवार तक हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान भी 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। इसके बाद फिर से मौसम शुष्क हो सकता है। (जासं)

यमुना प्राधिकरण लेगा जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा लेने के लिए यमुना प्राधिकरण ने अधिकारियों की टीम गठित की है। जिला प्रशासन से जमीन का स्थलीय कब्जा लेने के बाद उस पर पिलर बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन साढ़े छह सौ हेक्टेयर जमीन का मुआवजा बांट चुका है। 1334 परिवारों को मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए भी धनराशि वितरित हो चुकी है। 31 अगस्त तक एयरपोर्ट की पूरी जमीन का अधिग्रहण होना है।

जेवर एयरपोर्ट के लिए रोही, बनबारीवास, दयानतपुर, पारोही, रन्हेरा, किशोरपुर की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। करीब पचास फीसद जमीन का मुआवजा वितरित हो चुका है। यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की जमीन पर स्थलीय कब्जा लेने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन से प्राधिकरण को पत्र भेजकर जमीन पर स्थलीय कब्जा लेने के लिए अधिकारी अधिकृत करने का आग्रह किया गया था।

यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट की जमीन का स्थलीय कब्जा लेने के लिए ओएसडी नवनीत गोयल को नोडल अधिकारी बनाया है। संबंधित तहसीलदार समंवयक व नायब तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव स्थल पर्यवेक्षक होंगे। हर गांव के लिए एक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और प्रबंधक स्तर का अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एयरपोर्ट के लिए 1240 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें 648.37 हेक्टेयर जमीन का 1604. 62 करोड़ रुपये मुआवजा प्रशासन वितरित कर चुका है। 1334 परिवारों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की रकम भी वितरित कर दी गई है। 1667 परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषित करने के लिए मंडलायुक्त को प्रस्ताव भेजा गया है। एयरपोर्ट के लिए कुल 3167 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित होगा। जिला प्रशासन ने 31 अगस्त तक एयरपोर्ट प्रभावित सभी किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा वितरित करने का लक्ष्य तय किया है। इसी दिन तक एयरपोर्ट की बिड पर मिली क्वेरी का जबाव देने का कार्य पूरा हो जाएगा। प्री बिड कांफ्रेंस में शामिल हुई अधिकतर कंपनियों ने सौ फीसद जमीन पर कब्जा की बात कही है। नियाल ने बिड को लेकर मिली क्वेरी का जबाव तैयार कर लिया है। अभी कंसेशन एग्रीमेंट को लेकर जबाव तैयार किया जा रहा है।

एनएमसी बिल के खिलाफ हड़ताल से मरीज बेहाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) बिल के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) व एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को राजधानी में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम सहित तमाम सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की। इससे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक, जीटीबी सहित करीब 40 अस्पतालों में करीब 15 हजार रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इस वजह से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। रेजिडेंट डॉक्टरों की इस हड़ताल से करीब एक लाख मरीज प्रभावित हुए और 3300 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी टाल दी गई। सैकड़ों मरीजों की जांचे नहीं हो पाईं।

रेजिडेंड डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा के अलावा इमरजेंसी सेवा भी बंद रखने की घोषणा की थी। हालांकि ज्यादातर अस्पतालों की इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। इसलिए इमरजेंसी में कुछ गंभीर मरीजों का इलाज जरूर हुआ।

ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ठप रही ओपीडी : दिल्ली सरकार के करीब 34 अस्पताल हैं। इनमें से पांच स्वायत्तशासी अस्पतालों को छोड़कर सभी 29 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की। इन अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप रही। दिल्ली सरकार के इन अस्पतालों को प्रतिदिन ओपीडी में करीब 65 हजार मरीज पहुंचते हैं, जो हड़ताल के कारण वापस लौटने को मजबूर हुए। अस्पतालों में ओपीडी काउंटर नहीं खुले। फार्मेसी व ऑपरेशन थियेटर भी बंद रहे। यही हाल नगर निगम के अस्पतालों का रहा। कई अस्पतालों में पहले से भर्ती सैकड़ों मरीजों की छुट्टी कर दी गई।

लोकनायक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा मरीज एंबुलेंस में रहा। रेजिडेंट डॉक्टरों की इस हड़ताल से करीब एक लाख मरीज प्रभावित हुए। संजय

पांच बड़े अस्पतालों की ओपीडी में मौजूद रहे वरिष्ठ डॉक्टर : एम्स, सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के कलावती शरण व सुचेता कृपलानी अस्पताल की ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहे, लेकिन इन अस्पतालों में सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 50 फीसद कम मरीज देखे गए। एम्स में पहले से ऑनलाइन समय लेने वाले मरीजों का ही इलाज हुआ। एम्स में प्रतिदिन करीब 13 हजार मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें से करीब साढ़े सात हजार मरीज इलाज के बिना लौटे, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से डॉक्टर से मिलने का समय नहीं लिया था, उनके लिए ओपीडी कार्ड नहीं बनाए गए।

इमरजेंसी में भी मौजूद नहीं थे रेजिडेंट डॉक्टर : एम्स, सफदरजंग, आरएमएल सहित ज्यादातर अस्पतालों की इमरजेंसी में भी रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। इसलिए इमरजेंसी में भी व्यवस्था चरमराई रही। हालांकि इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टर तैनात किए गए थे। एम्स प्रशासन ने रोस्टर जारी कर इमरजेंसी में 24 घंटे के लिए सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी सहित अन्य विभागों के डॉक्टरों की तैनाती की। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसन विभाग के डॉक्टर भी ड्यूटी पर मौजूद रहे। फिर भी ज्यादातर मरीजों को इलाज के बाद गंभीर अवस्था में ही घर जाने के लिए कह दिया गया।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने एम्स व सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल के सामने की सड़क जाम कर दी। इस वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में एम्स फ्लाईओवर के नीचे रेजिडेंट डॉक्टरों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व एनएमसी बिल से आजादी के लिए भी नारे लगाए।

फर्जी आइपीएस व राजनेता बन ठगी कर रहे जीजा-साले गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

▸ खुद को पीएमओ में तैनात बताता था प्रयागराज निवासी शातिर गौरव मिश्रा, दो बार जा चुका है जेल

▸ फर्जी आइपीएस का साला खुद को उप्र भाजपा महासचिव (संगठन) बता कर बना रहा था दबाव

प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी तैनाती बता अधिकारियों पर दबाव बनाकर अनुचित कार्य कराने वाले फर्जी आइपीएस अधिकारी गौरव मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पश्चिम बंगाल कैडर का वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी बताकर अपना परिचय देता था। गौरव मूलरूप से शंकरगढ़, प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि वह अपनी पत्नी को भी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी बताता था। गौरव के साथ उसका साला आशुतोष राठी भी गिरफ्तार हुआ है। वह खुद को भाजपा, उत्तर प्रदेश का महासचिव (संगठन) बताकर अधिकारियों पर अनुचित काम कराने का दबाव बना रहा था। आशुतोष राठी मूलरूप से बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दोनों गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को सूरजपुर स्थित जिला अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश भाजपा महासचिव (संगठन) सुनील बंसल का नाम लेकर अधिकारियों को फोन कर दबाव बनाने के आरोप में कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने 26 जुलाई को एफआइआर दर्ज की थी। यह एफआइआर भाजपा नेता राजीव शर्मा ने दर्ज कराई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि सुनील बंसल का नाम लेकर आशुतोष राठी नामक व्यक्ति अधिकारियों को दबाव बना रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास होंडा अमेज कार में सवार आशुतोष राठी और उसके जीजा गौरव मिश्रा को हिरासत में ले लिया।

गौरव मिश्रा खुद को पश्चिम बंगाल कैडर का वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी बताकर पुलिस अधिकारियों को धमकाने लगा। उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात बताकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की धमकी दी। एक पल के लिए पुलिस अधिकारी भी उसकी धौंस में आकर डर गए। अधिकारियों ने उसके बारे में छानबीन की। उसके बताने के मुताबिक, वर्ष 2005 बैच के चयनित आइपीएस अधिकारियों की जानकारी जुटाई गई और इसमें वह फंस गया। पुलिस का दावा है कि गौरव मिश्रा खुद को आइपीएस और उसका साला आशुतोष राठी सुनील बंसल बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। पिछले पांच महीने में दोनों ने अधिकारियों पर दबाव बना कर कई काम कराए हैं। इससे उन्हें करीब 10 लाख रुपये मिले हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों से नकदी नहीं बरामद की है। सुनील बंसल के नाम से काम नहीं होने पर आशुतोष अपने जीजा गौरव की मदद लेता था।

अधिकारियों को मोहरा बनाते थे जीजा-साले : पुलिस ने पर्दाफाश किया है कि दोनों जीजा-साले ठगी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मोहरा बनाते थे। खुद को राजनेता बताने वाला आशुतोष राठी ने टू कॉलर पर अपना नाम पीके पोलिटिशियन लिखा था। इसलिए वह जिन अधिकारियों को फोन करता था, उनके मोबाइल पर यह नाम प्रदर्शित होता था। उस पर जब वह खुद को सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता सुनील बंसल बताकर फोन करता था, तब अधिकारी बिना कुछ कहे ही दबाव में आ जाते थे। वहीं, गौरव मिश्रा ने खुद को आइपीएस बताकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारियों से जान-पहचान बना ली थी। किसी अधिकारी से काम कराना होता था, तब वह पूर्व में परिचित अधिकारियों की मदद लेता था। उन अधिकारियों को उक्त अधिकारी से संपर्क कर काम कराने के लिए दबाव बनाता था। पीएमओ में तैनात वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी का नाम आते ही वे अधिकारी भी उसका काम कर देते थे। इसलिए किसी अधिकारी को उस पर संदेह नहीं होता था।

ट्रांसफर व पोस्टिंग के नाम पर भी ऐंठता था पैसे : गौरव मिश्रा इंस्पेक्टर, दारोगा और कांस्टेबल के साथ क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर व पोस्टिंग कराने के नाम पर भी ठगी करता था। उसने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में भी कुछ पुलिस कर्मियों व अधिकारियों से संपर्क किया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि वह यहां पर सफल नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे जिलों में उसने कई लोगों से पैसे लेकर ट्रांसफर कराया है। अभी तक आरोपित लाखों रुपये की ठगी कर चुका है।

कार में बैठे युवक-युवती से उगाही हेड कांस्टेबल सहित पांच निलंबित

जागरण संवाददाता, इंदिरापुरम

हैबिटेट सेंटर, इंदिरापुरम की पार्किंग में कार में बैठे युवक-युवती को ब्लैकमेल कर 20 हजार रुपये मांगने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद सुधीर सिंह ने दो हेड कांस्टेबल सहित पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नगर श्लोक कुमार की जांच के आधार पर एसएसपी ने बृहस्पतिवार को यह कार्रवाई की है।

डीजीपी से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई : इंदिरापुरम स्थित हैबिटेट सेंटर की पार्किंग में 22 जुलाई को सार्थक कार खड़ी कर एक युवती के साथ बैठे थे। आरोप है कि इस दौरान इंदिरापुरम थाना की नीति खंड पुलिस चौकी में तैनात सिपाहियों ने उनके साथ अभद्रता की। उन्हें ब्लैकमेल करते हुए 20 हजार रुपये की मांग की। मामले की शिकायत पर एसएसपी सुधीर सिंह ने एसपी सिटी श्लोक कुमार से मामले की जांच कराई। एसपी सिटी ने सप्ताह भर जांच की। उन्होंने जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एसएसपी ने बृहस्पतिवार को आरोपित हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह व केशव राम और कांस्टेबल अमित मिश्रा, अमित कुमार व सोमेश कुमार को निलंबित कर दिया।

> हैबिटेट सेंटर की पार्किंग में कार में बैठे युवक-युवती को ब्लैकमेल कर 20 हजार रुपये मांगने वाले पांचों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे पुलिस कर्मियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
> **-सुधीर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।**

डीजीपी को हुई थी शिकायत : बताया गया कि सार्थक ने डीजीपी व अन्य पुलिस के आलाधिकारियों को ट्विटर पर इसकी शिकायत की थी। इससे गाजियाबाद पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। एसएसपी ने एसपी सिटी को जांच सौंपी थी। चर्चा है कि आरोपित पुलिस कर्मियों ने युवक व युवती से चार हजार रुपये वसूल भी लिए थे।

जागरूकता

> दिल्ली पुलिस की ओर से शुरू किए गए हेल्प लाइन नंबर पर चार माह में करीब 325 कॉल आईं, जबकि 100 नंबर पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित करीब नौ हजार शिकायतें मिलीं

तेज शोर के खिलाफ राजधानी में बुलंद हो रही आवाज

लोकेश चौहान, नई दिल्ली

राजधानी में अब शोर के प्रति लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने के लिए शुरू किए गए हेल्प लाइन नंबर 155271 पर चार माह में करीब 325 कॉल आई हैं। जबकि पुलिस को 100 नंबर पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित करीब नौ हजार कॉल मिली हैं।

एडिशनल डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लोगों की शिकायत करने के लिए पांच अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 155271 हेल्प लाइन नंबर शुरू किया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की तरफ से मौके पर पीसीआर भेजने में पांच-सात मिनट का समय लगता है। मौके पर पहुंचकर शिकायत करने वाले से फोन पर संपर्क कर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए मौके पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस की मदद ली जाती है। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच तेज आवाज में डीजे, स्पीकर, लाउड स्पीकर, मार्बल घिसाई की मशीन या पांच केवी या इससे अधिक क्षमता के जनरेटर सेट चलाने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

50 डेसीबल से अधिक तीव्र ध्वनि नींद को करती है प्रभावित। प्रतीकात्मक

ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर पड़ता है बुरा असर

लगातार तीव्र ध्वनि के संपर्क में रहने से कई तरह की शारीरिक व मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण काम, नींद और अन्य क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हजार हर्ट्ज वाली ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। 85 डेसीबल से तेज ध्वनि को प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है। ध्वनि प्रदूषण से सबसे पहला असर सुनने की क्षमता पर पड़ता है। इससे धीरे-धीरे सुनने की क्षमता कम होती जाती है। आठ घंटे से अधिक 80 डेसीबल या इससे ज्यादा तीव्रता वाली ध्वनि के संपर्क में रहने पर कान खराब हो सकते हैं। सुनने में बाधा पैदा होने से दैनिक काम भी प्रभावित होते हैं। 50 डेसीबल से अधिक तीव्र ध्वनि नींद को प्रभावित करती है। 85 डेसीबल से तेज ध्वनि दिल की धड़कन व रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तेज ध्वनि के संपर्क में लगातार रहने से हार्टअटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।

ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने के लिए शुरू की वेबसाइट : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश के बाद लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के साथ ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए वेबसाइट भी शुरू की है। वेबसाइट के जरिये शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उस पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने के बाद शिकायत करने का प्लेटफार्म खुल जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता को अपना नाम, शिकायत का प्रकार, क्षेत्र और संबंधित थाने के साथ ध्वनि प्रदूषण के स्थान और प्रकार की जानकारी देने के साथ अपना ई-मेल भी देना होगा। इतनी जानकारी देने के बाद जिस भी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, वहां के थाना प्रभारी को सूचना मिलने के साथ ही शिकायत करने वाले के मोबाइल और ई-मेल पर शिकायत दर्ज किए जाने और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मिल जाएगी। वेबसाइट पर शिकायत किए जाने की स्थिति में पुलिस को मौके पर पहुंचने में करीब 30 मिनट का समय लगता है।

ध्वनि प्रदूषण जिनकी कर सकते हैं शिकायत

तेज आवाज, लाउड स्पीकर, प्रेशर हार्न, फैक्ट्री का शोर, निर्माण कार्य के दौरान होने वाला शोर, जेनरेटर का शोर, साइलेंसर बदलकर शोर फैलाना, मशीनों की तेज आवाज

ध्वनि प्रदूषण के मानक

क्षेत्र	दिन	रात
आवासीय	55	44
औद्योगिक	75	70
वाणिज्यक	65	55
शांत क्षेत्र	50	40

नोट : प्रदूषण का मानक डेसीबल में है।

सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आइएएस और समूह ए के सिविल सेवा अधिकारियों के साथ-साथ अब दिल्ली सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत 40 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य जांच करवानी होगी। इससे दिल्ली सरकार में काम कर रहे लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

कर्मचारियों की कार्यकुशलता और काम करने की क्षमता में सुधार के लिए गए इस फैसले के संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि एलजी ने अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य जांच कर्मचारियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट का हिस्सा होगी। अभी तक यह जांच आइएएस अधिकारी और समूह ए सिविल सेवा अधिकारियों के लिए उपलब्ध थी। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, दिल्ली को अलग से अनुरोध किया गया कि वह प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए नियम- कायदे तय करें।

31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सूचीबद्ध करने की समयसीमा। भारत के महापंजीयक के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि असम के नागरिकों की सूची 31 जुलाई तक की निर्धारित समयसीमा में तैयार नहीं की जा सकी।

नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु का नया राग, हिंदी की अनिवार्यता का विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मौजूदा नीति में बदलाव का दिया सुझाव कहा, हर राज्य को हो परिवर्तन की छूट
- मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ चर्चा में उठे सवाल

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता का विरोध करने वाले तमिलनाडु ने अब पूरी नीति के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इसे गैरजरूरी बताते हुए सुझाव दिया है, कि सभी राज्यों को अपनी नीति बनाने की छूट दी जाए। हालांकि इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने तुरंत ही आपत्ति जताई और कहा कि वह राज्यों को इस मामले पर पूरी स्वतंत्रता देंगे, लेकिन देश में शिक्षा की नीति एक ही रहेगी।

नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु की यह राय उस समय सामने आई है, जब मानव संसाधन विकास मंत्री गुरुवार को राज्य के सांसदों के साथ इस पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य शामिल थे। इस क्रम में वह अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के सांसदों के साथ चर्चा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी राज्यों के सांसदों के साथ उनकी इसी तरह की चर्चा की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सांसदों के सभी बेहतर सुझावों को नीति में शामिल करने का भी भरोसा दिया है। नीति पर सुझावों को देने की अंतिम तारीख 15 अगस्त की है।

रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी के सुझावों पर गौर करने का भरोसा दिया है। फाइल

खास बात यह है कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के सामने आने के बाद इसे लेकर सबसे पहला विरोध भी तमिलनाडु की ओर से आया था जिसमें हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का विरोध किया गया था। हालांकि तमिलनाडु के विरोध के बाद सरकार ने प्रस्तावित नीति से हिंदी की अनिवार्यता के सुझाव को हटा लिया था।

फिर उठा हिंदी का मुद्दा : प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के साथ चर्चा में फिर से हिंदी की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठा। हालांकि नीति तैयार करने वाली कमेटी में मंत्रालय की ओर से शामिल शकीला शम्सू ने तुरंत यह साफ किया कि यह मुद्दा अब खत्म हो चुका है, क्योंकि नीति से इसे हटा लिया गया है। इसके बावजूद सांसदों ने मंत्री से यह आश्वासन देने की मांग की कि भाषा अध्ययन की वैकल्पिक व्यवस्था में छात्रों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु से हिंदी की अनिवार्यता का विरोध पहले भी किया जाता रहा है।

राज्यसभा की दो सीटों पर 26 अगस्त को उपचुनाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा की दो सीटों पर 26 अगस्त को उपचुनाव कराया जाएगा। राजस्थान में भाजपा के मदनलाल सैनी के निधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर के इस्तीफे के चलते ये दोनों सीटें रिक्त हुई हैं। माना जा रहा है कि यूपी से नीरज शेखर ही भाजपा प्रत्याशी होंगे जबकि राजस्थान से कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर विचार कर रही है।

राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भाजपा की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष मदनलाल सैनी का 24 जून को निधन हो गया था। वहीं उत्तर प्रदेश से सपा के राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने 15 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इससे उनकी सीट रिक्त हो गई थी। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। दोनों सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक 26 अगस्त को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। अधिसूचना सात अगस्त को जारी की जाएगी। 14 अगस्त तक नामांकन किए जा सकेंगे। 16 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

तत्काल तलाक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तत्काल तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे अब यह कानून में तब्दील हो गया है। सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह कानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।

पत्नी को तत्काल तीन तलाक के जरिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक जेल की सजा के प्रावधान वाले इस विधेयक को मंगलवार को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। इससे पहले पिछले हफ्ते यह लोकसभा से पारित हुआ था। नया कानून 'मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019' मुस्लिम पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक ए बिद्दत यानी तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी बताता है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक रूप से, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य विधि से तलाक ए बिद्दत देता है तो यह अवैध माना जाएगा।

तलाक ए बिद्दत में कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तत्काल तीन बार 'तलाक' बोलकर उससे संबंध खत्म कर लेता है। नए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि 'तत्काल तीन तलाक' से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा। तीन तलाक से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना था कि कानून की मौजूदा संरचना में उसके प्रावधानों का मुस्लिमों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और संसदीय समिति को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

मतदान में गैरहाजिर सांसदों से कांग्रेस ने मांगी सफाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पार्टी व्हिप के बावजूद राज्यसभा में मंगलवार को तत्काल तीन तलाक विधेयक पर मतदान के दौरान गैरहाजिर रहने वाले अपने सांसदों से कांग्रेस ने स्पष्टीकरण मांगा है। विपक्षी खेमे में फूट और कुछ सांसदों की अनुपस्थिति के चलते सरकार ऐतिहासिक तत्काल तीन तलाक बिल पारित कराने में सफल रही थी। बिल पारित होने के साथ ही इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया था।

सियासी वाद-विवाद का केंद्र बने इस बिल पर विपक्ष के कमजोर प्रबंधन का आलम यह था कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खुद सदन में अपने सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करा पाई। कांग्रेस के चार सांसदों विवेक तन्खा, मुकुट मिथी, प्रताप सिंह बाजवा और रंजीत बिस्वाल के अलावा कांग्रेस से ही संबद्ध मनोनीत सदस्य केटीएस तुलसी तीन तलाक बिल पर मतदान के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे।

मतदान के दौरान कांग्रेस, सपा, बसपा, तेदेपा और वाइएसआर कांग्रेस के 22 सदस्य अनुपस्थित थे। यही वजह थी कि सरकार तत्काल तीन तलाक बिल को 84 के मुकाबले 99 वोटों से पारित कराकर विपक्ष को मात देने में कामयाब रही थी। विधेयक को लेकर विपक्षी खेमे का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के लिए अपने ही सांसदों के गैरहाजिर होने से असहज होना स्वाभाविक है। इसीलिए पार्टी ने इन सांसदों से मतदान के दौरान सदन में मौजूद नहीं होने की वजह बताते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा है।

राज्यसभा ने नए एनएमसी में राज्यों को दी तरजीह

बाधा पार ▶ अब परीक्षाओं के जंजाल से मुक्त होंगे मेडिकल छात्र, अहम बिल को राज्यसभा की भी मिली मंजूरी

विपक्ष बोला- निजी मेडिकल कालेजों व झोलाछाप डॉक्टरों की आएगी बाढ़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा ने प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला पारित किया है। लोकसभा से पारित एनएमसी विधेयक में राज्यसभा ने तीन संशोधन कर दिए हैं। इससे 25 सदस्यीय एनएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। राज्यों से छह वाइस चांसलर रखने की संख्या बढ़ाकर दस कर दी गई है। वहीं, राज्यों की मेडिकल काउंसिल का प्रतिनिधित्व पांच से बढ़ाकर नौ कर दिया है। राज्यसभा के इन संशोधनों के बाद विधेयक को दोबारा लोकसभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

राज्यसभा ने गुरुवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर दिया। यह विधेयक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) का स्थान लेगा, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। विधेयक में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस कदम को चिकित्सा शिक्षा तथा सुविधाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार बताया है। लोकसभा इस विधेयक को 29 जुलाई को पहले ही पास कर चुकी है, लेकिन संशोधनों पर मुहर के लिए इसे दोबारा पेश करना होगा।

बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने कहा कि विधेयक से झोलाछाप डॉक्टरों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। एक्जिट, नेक्स्ट तथा नीट परीक्षाओं के बारे में उठाए गए सवालों पर कहा कि बिल पास होने के बाद एक्जिट की व्यवस्था अगले तीन वर्षों में लागू होगी। नीट एक संस्थागत निकाय है जो 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करता है। नीट की काउंसिलिंग पूरी तरह पारदर्शी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की कुल 80,000 सीटों में से 40,000 सीटें सरकारी संस्थानों में हैं। इनमें बहुत कम फीस ली जाती है। एमसीआइ के पास निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इस विधेयक में इसकी व्यवस्था की गई है। शेष 50 फीसद सीटों को राज्य सरकारें नियंत्रित कर सकती हैं। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि मेडिकल काउंसिल की स्थापना 1956 में इसी नाम से बनाए गए कानून के माध्यम से हुई थी। अब नया राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कानून, 2019 उस कानून की जगह लेगा।

एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा, पीजी के लिए होगी प्रवेश परीक्षा : विधेयक में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक बनाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा को परास्नातक या पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा माना जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक देश में मेडिकल परीक्षाओं का जंजाल खत्म कर देगा। एमबीबीएस के लिए एम्स समेत सभी मेडिकल कालेजों में एक ही परीक्षा एनआइआइटी (नीट) देनी होगी। वहीं, पीजी के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। एग्जिट एग्जाम के आधार पर ही पीजी में एडमिशन होगा। जबकि विदेश से पढ़कर आने वाले मेडिकल छात्रों को भी एग्जिट की परीक्षा में ही बैठना होगा। यहां तक कि एग्जिट परीक्षा पास करने वालों को अब डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे प्रस्तावित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को बार-बार मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच नहीं करनी पड़ेगी। आयोग प्रक्रियाओं की जांच-पड़ताल में उलझने के बजाय परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।

चिकित्सा शिक्षा का हो जाएगा निगमीकरण: तृणमूल

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांतनु सेन ने कहा, बिल को लेकर चिकित्सा जगत से जुड़े लोग आंदोलित हैं। बिल के प्रावधानों से चिकित्सा शिक्षा का निगमीकरण हो जाएगा। इसमें संघीय ढांचे की उपेक्षा कर राज्यों की स्वायत्तता छीनने का प्रयास किया गया है। इससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भरमार हो जाएगी।

अन्नाद्रमुक बोली, नीट और नेक्स्ट लादे नहीं जाएं: जयराम रमेश ने राज्यों के अधिकार सीमित करने पर आपत्ति जताई। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा देश पहले ही झोलाछाप डॉक्टरों से परेशान है अब उन्हें और बढ़ावा मिलेगा। अन्नाद्रमुक के विजिला सत्यनाथ ने कहा कि देश पर नीट और नेक्स्ट लादे नहीं जाने चाहिए। बीजद के सस्मित पात्रा ने राष्ट्रीय मेडिकल शिक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापित करने की मांग की।

नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। राज्यसभा में उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पर विपक्ष की आपत्तियों का जवाब दिया। प्रेट्र

कांग्रेस ने अयोग्य लोगों को लाइसेंस देने का विरोध किया

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी बिल में साढ़े तीन लाख अयोग्य लोगों को मेडिकल की प्रैक्टिस का लाइसेंस देने का के प्रावधान का जोरदार विरोध किया। इसके अलावा, आप साढ़े तीन वर्ष का साइंस कोर्स करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जगह नर्स, कंपाउंडर व ब्लड सैंपल कलेक्टर जैसे मध्यम स्तर के स्वास्थ्य पेशेवरों को बढ़ावा देने जा रहे हैं। इससे 70 फीसद जनता 'गिनी पिग (प्रयोग का जरिया)' बन जाएगी। यदि कोई छात्र एक्जिट टेस्ट पास कर लेता है मगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए मेरिट में नहीं आता तो वो क्या करेगा। क्या उसे पीजी के लिए पुन: प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

गैरकानूनी गतिविधि कानून का संशोधन बिल राज्यसभा में पेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हाफिज सईद व अजहर मसूद को आतंकी करार देने का रास्ता होगा साफ
- विपक्ष ने दुरुपयोग की आशंका जताते हुए किया विरोध

हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ करने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश हो गया। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक में संशोधनों पर चर्चा के दौरान गृह राज्यमंत्री जी. कृष्णरेड्डी ने बताया कि किस तरह भारत अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए सभी देशों को राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून नहीं होने के कारण खुद भारत में उसे आतंकी घोषित नहीं किया जा सका था।

कपिल सिब्बल ने उठाया सवाल : लोकसभा में पहले ही पास हो चुके इन संशोधनों का विरोध करते हुए विपक्ष की ओर से इसके दुरुपयोग की आशंका जताई गई। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर किसी आतंकी घोषित करने का मापदंड क्या होगा। यह विधेयक में स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपने विरोधी विचारधारा के लोगों को आतंकी घोषित करने में इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। कपिल सिब्बल का कहना था कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास कराने से बचना चाहिए और इसे संसद की स्थायी समिति या प्रवर समिति किसी में भेज दिया जाना चाहिए, ताकि इसके प्रावधानों पर गहराई से विचार-विमर्श हो सके।

वाइको ने भी किया विरोध : एमडीएमके के वाइको ने भी इसका विरोध दुरुपयोग की आशंका जताते हुए किया। वाइको ने बताया कि किस तरह तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ पोटा कानून का दुरुपयोग किया था। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को विधेयक पास होने के पहले सरकार की ओर से विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया जाएगा।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना अजहर मसूद को आतंकी घोषित कराने के दौरान यूएपीए कानून में बड़ी कमजोरी का अहसास हुआ था। बातचीत के दौरान चीन बार-बार यही कहता था कि जब खुद भारत ने अजहर मसूद को आतंकी घोषित नहीं किया है, तो वह संयुक्त राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने पर क्यों अड़ा है।

खैर चीन को इसके लिए किसी तरह राजी कर लिया गया और अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में सफलता भी मिल गई। जाहिर यूएपीए में संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकेगा। अभी तक केवल संगठन को ही आतंकी घोषित किए जाने का प्रावधान है।

सत्र बढ़ाने के पीछे मुलायम को दिखी सरकार की साजिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने संसद के मौजूदा सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर गुरुवार को लोकसभा में सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सरकार की साजिश है। हालांकि, सरकार ने आरोप को खारिज करते हुए साफ किया कि तमाम विधायी कार्य होने के कारण सत्र को बढ़ाया गया।

- सरकार ने कहा, बहुत सारे विधायी कार्य होने के कारण सत्र को बढ़ाया गया
- मेघवाल बोले, मुलायम सिंह वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं

लोकसभा में दिवालिया कानून के संशोधन पर चर्चा के दौरान यादव ने सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'लोकसभा देश की विधानसभाओं के लिए आदर्श होती है, लेकिन सदन में बहुत सारे सदस्य मौजूद नहीं हैं... लोग शादी तक में नहीं जा पा रहे हैं... सदन के संचालन के पीछे सरकार की साजिश है। जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है...कोई वाजिब कारण हो तो मुझे बताएं।' कांग्रेस नेताओं और बगल में बैठे तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने यादव की बातों का समर्थन किया।

संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदन में पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा, 'मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं, जिनसे आम जनता को फायदा होगा... विपक्ष भी मांग करता रहा है कि संसद में कामकाज साल में कम से कम 100 दिन होने चाहिए।' 17वीं लोकसभा का पहला सत्र नए सदस्यों के शपथग्रहण के साथ 17 जून को शुरू हुआ था। इसे 26 जुलाई को समाप्त होना था, लेकिन इसकी अवधि सात अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

लोकसभा में गुरुवार को सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने संसद के मौजूदा सत्र की अवधि बढ़ाने पर सवाल उठाया। प्रेट्र

'वंदे भारत' का उत्पादन बंद होने का उठा सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन बंद होने की आशंकाओं को लेकर राज्यसभा में सवाल उठा। शिवसेना सदस्य संजय राउत ने शून्यकाल में इस मामले को उठाया।

उन्होंने कहा कि सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत (ट्रेन-18) को भारतीय रेल के लिए गेम चेंजर माना गया है और यह मेक इन इंडिया का सबसे सफल प्रयोग रहा है। इसकी पहली रेक का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-वाराणसी के बीच किया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या इस ट्रेन का उत्पादन बंद कराने के लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही हैं कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार ट्रेन की निविदा प्रक्रिया में बाधा खड़ी करने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली-वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। दूसरी वंदे भारत का दिल्ली-कटरा मार्ग पर ट्रायल भी पूरा हो चुका है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि इस तरह की 136 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार अगले तीन वर्षों में 40 ट्रेनों के उत्पादन की योजना है, जिनमें दस ट्रेनें अगले एक वर्ष के दौरान बनाई जानी हैं।

मोदी 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को करेंगे संबोधित

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र में दुनिया भर के नेताओं के संबोधन कार्यक्रम की सूची में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महासभा को पहली बार 2014 में संबोधित किया था। महासभा सत्र के इतर पीएम मोदी के कई उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने की भी उम्मीद है। न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले मोदी के ह्यूस्टन जाने की भी संभावना है, जहां वह 22 सितंबर को भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे।

मई में हुए आम चुनाव में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में वह सितंबर में पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के अनुसार मोदी 28 सितंबर की सुबह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सत्र 24 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महासभा को 24 सितंबर को संबोधित करेंगे। पारंपरिक रूप से सत्र के पहले दिन ब्राजील के बाद अमेरिका दूसरा वक्ता होता है। पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के अनुसार करीब 112 राष्ट्राध्यक्ष, करीब 48 शासनाध्यक्ष और 30 से अधिक विदेश मंत्री महासभा को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंचेंगे।

- ह्यूस्टन जाने की भी चर्चा, भारत-अमेरिकी समुदाय को करेंगे संबोधित

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

कई उच्चस्तरीय सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा संयुक्त राष्ट्र : महासभा के 74वें सत्र के इतर कई उच्चस्तरीय सम्मेलन भी होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस 23 सितंबर को 2019 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे जिसमें पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र 24 और 25 सितंबर को टिकाऊ विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए हो सकेगी मौत की सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने गुरुवार को 'लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019' (पॉक्सो) को मंजूरी दे दी। इसमें अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) को परिभाषित करने के अलावा बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। राज्यसभा इस विधेयक को 29 जुलाई को ही पारित कर चुकी है।

- संसद ने पॉक्सो संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस विषय को राजनीति के चश्मे से न देखा जाए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पहल है जो बच्चों और देश के भविष्य को सुरक्षित दिशा में ले जाने का प्रयास है। ईरानी की यह टिप्पणी कांग्रेस की रम्या हरिदास के बयान के परोक्ष संदर्भ में थी जिसमें उन्होंने उन्नाव दुष्कर्म मामले का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'उन्नाव दुष्कर्म मामले में कांग्रेस की एक सदस्य ने कुछ बातें कहीं और उनके आसपास बैठे चार-पांच सांसद मेज थपथपा रहे थे जैसे कोई मजे की बात हो।' उन्होंने कहा कि अगर जघन्य अपराध होगा तो संसद ने न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया है कि वे मौत की सजा दें।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने कानून में यह नहीं कहा कि इससे सांसद या विधायक अछूता रहेगा। मंत्री ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1,023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 18 राज्यों ने ऐसी अदालतों की स्थापना के लिए सहमति जताई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने यौन अपराधों का एक राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया है। ऐसे 6,20,000 अपराधी हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्तियों को रोजगार पर रखता है तो संबंधित व्यक्ति के बारे में इससे जानकारी लेने में मदद मिलेगी।

बढ़ता संकट

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में कार्यसमिति की बैठक बुलाने पर चर्चा तक नहीं हुई, अब संसद के बजट सत्र के बाद ही बैठक बुलाए जाने की संभावना

नए अध्यक्ष की तलाश पर जारी रहेगी कांग्रेस की कछुआ चाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अभी अगले 10 दिनों तक होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के उत्तराधिकारी की तलाश में दोराहे पर खड़ी पार्टी के कार्यकर्ता भले बेचैन हों मगर कांग्रेस अपना नया नेता चुनने की जल्दी में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक संसद के बजट सत्र के बाद ही बुलाने की योजना है।

कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कायम असमंजस की स्थिति साफ होगी। मगर दिलचस्प यह रहा कि इस बैठक में नेतृत्व संकट से रूबरू हो रही पार्टी की चुनौतियों पर पदाधिकारियों ने चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा कहा भी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों की बैठक में कार्यसमिति की बैठक बुलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कार्यसमिति की बैठक उचित समय पर होगी। सुरजेवाला ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संसद के बजट सत्र के बाद ही कार्यसमिति की बैठक बुलाने पर फैसला होगा।

लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के सवा दो महीने बाद भी उनका विकल्प तलाश रही पार्टी गांधी परिवार के बाहर के किसी दूसरे नेता पर अभी तक सहमति नहीं बना पाई है। नए अध्यक्ष की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, सुशील कुमार शिंदे, आनंद शर्मा, सचिन पायलट जैसे नेता शामिल हैं। मगर अभी तक किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही बीते दो हफ्ते से प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की कमान सौंपने की आवाज उठने लगी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रियंका के नाम की पैरोकारी करके पार्टी के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। इसके बाद से राहुल गांधी पर इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि वह नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को बनाने के अपने एलान को वापस ले लें। थरूर ने पिछले दिनों यह भी कहा कि पार्टी के सभी पदों के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। उनके मुताबिक नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता के कारण पार्टी का संकट बढ़ रहा है और इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिवों की बैठक हुई। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। प्रेट्र

सिद्धू पर नजर रखेगी कांग्रस, विधानसभा में दूसरी कतार में किया शिफ्ट

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब विधानसभा में दूसरी कतार के अंत में बैठेंगे। इस्तीफा देने के बाद उनकी वरिष्ठता कांग्रेस के छह बार के विधायक रहे राकेश पांडे के बाद बन गई है। इसके अलावा कांग्रेस उनके सदन में आने के दौरान उन पर निगाह बनाए रखेगी। क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं सिद्धू सेल्फ गोल न कर दें। वहीं, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मानसा के विधायक नाजर सिंह मानशाहिया, रूपनगर के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ और जैतो के विधायक मास्टर बलदेव सिंह के सिटिंग प्लान में भी बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को सबकी नजर नवजोत सिंह सिद्धू के सिटिंग प्लान पर थी। देर शाम तक कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू का सिटिंग प्लान स्पीकर राणा केपी सिंह को नहीं भेजा था। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों की कतार खत्म होने के बाद लुधियाना के विधायक राकेश पांडे बैठेंगे। जिसके बाद सिद्धू की सीट अलाट की गई है। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि सिद्धू को राणा गुरजीत सिंह के साथ बैठाया जा सकता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

30 नवंबर से पहले होंगे उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव। यह आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। अदालत ने यह भी साफ किया है कि तब तक पंचायतों में प्रशासक काम तो करेंगे मगर उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज रहेंगी।

विधायकों के दबाव में कांग्रेस हाईकमान से टकराने को तैयार हुए हुड्डा

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- महापरिवर्तन रैली के जरिये चुनाव लड़ने के दावेदार कार्यकर्ताओं को करेंगे सक्रिय
- प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही विधानसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथ में रखने की रणनीति

हरियाणा के दस साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान से सीधे टकराने को अचानक ही तैयार नहीं हुए। उन पर अपने समर्थक विधायकों का भारी दबाव है। हुड्डा खुद भी चाहते हैं कि चुनावी रण में उतरने के लिए आर-पार की लड़ाई का एलान जरूरी है। रोहतक में होने वाली महापरिवर्तन रैली से पहले यदि हुड्डा को कांग्रेस की कमान नहीं सौंपी गई तो उनके समर्थक कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने का दबाव भी हुड्डा पर बना सकते हैं।

महापरिवर्तन रैली में यह फैसला अलग पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने का भी हो सकता है और कांग्रेस में रहकर हर सीट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारने का भी संभव है। हुड्डा समर्थक विधायकों का मानना है कि यदि अब भी कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए तो चुनावी रण में मुश्किलें आना तय हैं।

हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जिस तरह से कांग्रेस दिग्गजों को निशाने पर लेना शुरू किया है, उसके मद्देनजर हुड्डा की रोहतक में होने वाली महापरिवर्तन रैली काफी अहम है। हुड्डा 18 अगस्त को यह रैली करेंगे। इससे दो दिन पहले 16 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद रथयात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में हुड्डा समर्थक विधायकों को लगता है कि यदि अभी से सक्रियता नहीं दिखाई तो लोगों को जवाब देना भारी हो जाएगा।

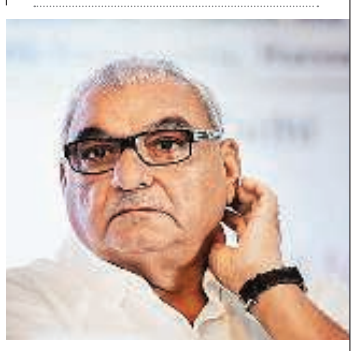

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल फोटो

रैली के बहाने कार्यकताओं को करेंगे सक्रिय

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार हुड्डा ने बड़े ही रणनीतिक अंदाज में 18 अगस्त की रैली रखी है। तब तक हाईकमान ने कोई निर्णय कर लिया तो ठीक अन्यथा इस रैली में हुड्डा किसी नई पार्टी का संकेत देने के साथ ही अपने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पूर्व विधायकों तथा मौजूदा विधायकों को एक्टिवेट (सक्रिय) कर सकते हैं। यहां यह जिक्र करना भी जरूरी है कि कांग्रेस में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल और चौ. भजनलाल ने भी अलग पार्टियां बनाई थीं, लेकिन उनको अपनी पार्टियों का एक समय के बाद कांग्रेस में ही विलय करना पड़ा।

दरअसल, हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी का शिकार है। हुड्डा समर्थक विधायकों की दलील है कि पिछले छह साल के अंतराल में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर न तो कोई संगठन खड़ा कर पाए और न ही पार्टी को मजबूती दे सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का खजाना भी पूरी तरह खाली है। तंवर को हटाने की मुहिम लंबे समय से चल रही है, लेकिन हुड्डा खेमे को इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही। ऐसे में अब चुनाव से ठीक पहले हुड्डा समर्थकों ने आरपार की लड़ाई लड़ने के साथ ही एक रणनीति के तहत हाईकमान को आंखें दिखानी शुरू की हैं।

हुड्डा समर्थक विधायकों ने हाईकमान के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला तो यह कि तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर हुड्डा को कमान सौंपी जाए और दूसरी यह कि टिकटों का आवंटन हुड्डा अपने ढंग से करेंगे। भले ही इसमें बाकी गुटों के नेताओं को उनकी राजनीतिक क्षमता के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। हाईकमान ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला इसलिए नहीं लिया, क्योंकि दलील दी जा रही कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है। हुड्डा समर्थक विधायक इस दलील से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि तमाम काम और बहाने छोड़कर हरियाणा के बारे में इसलिए फैसला जरूरी है, क्योंकि यहां अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

गाली-गलौज से आहत विधायक दहिया का इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सोनीपत के राई हलके से महज तीन वोट से जीते कांग्रेस विधायक जयतीर्थ दहिया ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रधान अशोक तंवर पर चार जून को गाली देने का आरोप लगाने वाले दहिया इस मामले में आलाकमान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं लिए जाने से आहत थे। शुक्रवार को शुरू हो रहे विधानसभा के अंतिम सत्र से एक दिन पहले ही उन्होंने विधानसभा सचिवालय में जाकर इस्तीफा दे दिया।

दहिया ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है, जब हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच दहिया अहम कड़ी रहे हैं। दहिया ने इस्तीफे के पीछे खुलकर कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो वह पार्टी में कई माह से अनदेखी के शिकार थे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली में पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद

जयतीर्थ दहिया फाइल फोटो

द्वारा बुलाई बैठक के बाद दहिया ने तंवर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मामले में पार्टी प्रभारी को शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रकरण में हुड्डा के अलावा किसी दूसरे पार्टी विधायक ने दहिया का साथ नहीं दिया, जबकि तंवर के खिलाफ सभी मोर्चा खोले हुए थे। इस्तीफे का दूसरा बड़ा कारण हाईकमान द्वारा हुड्डा को बागडोर नहीं सौंपना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त को प्रस्तावित रैली से आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। ऐसे में दहिया के इस्तीफे को हाईकमान पर दबाव की दिशा में पहला प्रयास बताया जा रहा है।

बसपा विधायक ने मायावती पर लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप

जासं, जयपुर: राजस्थान के बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गुरुवार को अपनी ही पार्टी में पैसे लेकर टिकट देने का पार्टी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाया। राज्य विधानसभा भवन में विधायकों के सेमिनार में एक सत्र के दौरान राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि कोई उन्हें ज्यादा पैसे दे देता है तो वह उसे टिकट दे देती हैं । गुढ़ा ने कहा कि एक व्यक्ति को पैसे लेकर टिकट दे दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति यदि अधिक पैसे दे देता है तो उसे टिकट मिल जाता है। यदि तीसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा पैसा दे देता है तो उसे टिकट मिल जाता है । पैसे लेकर टिकट बदल दिए जाते हैं, क्या इसका कोई समाधान है। इस पर भाजपा विधायक दल के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसका स्पष्ट जवाब तो मायावती ही दे सकती हैं।

गौरतलब है कि गुढ़ा अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में उनकी सरकार में मंत्री रहे थे। उस समय भी वह बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन फिर अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बने थे। उधर, इस बारे में बसपा पदाधिकारी बात करने से कतराते रहे। प्रदेश प्रभारी धर्मवीर अशोक से जब गुढ़ा के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वे ही अधिक बता सकेंगे।

रणक्षेत्र में तब्दील हुआ झारखंड कांग्रेस मुख्यालय, लाठीचार्ज

भिड़ंत ▶ जमशेदपुर से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष समर्थकों के सामने सुबोध गुट की एक न चली

निष्कासित नेताओं को कार्यालय से किया बाहर, एक घंटे तक सड़क पर हुई दोनों ओर से जूतम-पैजार

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद गुरुवार को सड़क पर आ गया। वर्चस्व की लड़ाई में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के समर्थक आपस में इस कदर भिड़े कि तू-तू, मैं-मैं, दोनों ओर से गुत्थमगुत्थी और लात-घूंसे के बीच एक घंटे तक कांग्रेस मुख्यालय रणक्षेत्र में तब्दील रहा। लगभग एक घंटे तक दोनों गुटों के कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक-दूसरे से उलझते रहे, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से अधिक कांग्रेसी घायल हुए हैं, जबकि एक मीडियाकर्मी भी घायल हुआ है। इस दौरान एक दिन पहले कांग्रेस के दो नेताओं को पार्टी से निष्कासित किए जाने के खिलाफ सहाय गुट के लोगों की ओर से पार्टी मुख्यालय पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन को भी प्रदेश अध्यक्ष की टीम ने विफल कर दिया। दोनों गुटों के नेताओं ने आपस में मारपीट तो की ही, एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

निष्कासित नेताओं को प्रेस कांफ्रेंस से रोकने के बाद बढ़ा बवाल : लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस का अंदरूनी कलह सतह पर आ गया है और वरीय नेता लगातार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को ही कांग्रेस कार्यालय में घुसने से रोक दिया गया था, वहीं इसके अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने दो नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। गुरुवार को दूसरे गुट के लोग गोलबंद हुए तो कोल्हान और रांची से प्रदेश अध्यक्ष के समर्थक तीन दर्जन गाड़ियों से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां पहले से निष्कासित नेता सुरेंद्र सिंह और राकेश सिन्हा प्रेस कांफ्रेंस करना चाहते थे। इन्हें प्रेस कांफ्रेंस करने से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों ने रोका और बाहर धकेल दिया। इसके बाद कार्यालय के बाहर सड़क पर हंगामा होने लगा।

रांची में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समर्थकों को काबू करने की कोशिश में जुटे पुलिसकर्मी। प्रेट्र

कोयला चोरों से राजनीति नहीं सीखनी : डॉ. अजय कुमार

डॉ. अजय कुमार ने कहा कि उन्हें कोयला चोरी और सीबीआइ जांच में फंसे लोगों से राजनीति नहीं सीखनी। उन्होंने कहा कि सुबोधकांत सहाय इतना गिर सकते हैं कभी सोचा नहीं था। लड़ाई मुझसे नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि खुद सांसद का चुनाव लड़ेंगे और भाई को हटिया से लड़ाएंगे, मेयर सीट पर भी कब्जा चाहिए। ददई दुबे का नाम लिए बगैर कहा कि खुद तो बोकारो से लड़ना चाहते हैं और बेटे को पलामू से टिकट चाहिए। प्रदीप बलमुचु के बारे में भी उन्होंने कहा कि खूंटी और सिंहभूम से खुद और बेटी के लिए इन्हें टिकट चाहिए। फुरकान अंसारी का नाम लिए बगैर कहा कि इन्हें खुद और बेटे के लिए गोड्डा और मधुपुर की सीट चाहिए। ऐसे नेता नए लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं।

ईडी के घेरे में आने के बाद पीएम के पास पहुंचे फारूक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव कराने व अनुच्छेद 35-ए के मुद्दे पर हुई बात : उमर
- सियासी दलों ने कहा-मुलाकात राज्य के लिए नहीं, अपने हितों की खातिर

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में करीब 44 करोड़ के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई पूछताछ के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। फारूक के साथ उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और नेकां के एक सांसद भी थे। अनुच्छेद 35-ए को लेकर राज्य में जारी सियासत के बीच डॉ. अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर स्थानीय राजनीतिक दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में सर्वदलीय बैठक करने के बजाय दिल्ली में पीएम से अचानक हुई यह मुलाकात राज्य के हितों की खातिर नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए की गई नजर आती है। दरअसल, जेकेसीए में हुए घोटाले के मामले में फारूक भी आरोपित हैं और ईडी ने गत बुधवार को चंड़ीगढ़ में उनसे करीब छह घंटे लंबी पूछताछ की थी।

कश्मीर आने के बजाय दिल्ली पहुंचे फारूक : जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैनिकबलों की 100 अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने के साथ अनुच्छेद 35ए को भंग करने की शुरू हुई अटकलों के बीच कश्मीर केंद्रित मुख्यधारा के सियासी दलों को उम्मीद थी कि फारूक गुरुवार को सर्वदलीय बैठक के बारे में कोई अंतिम फैसला लेंगे। सभी उनके कश्मीर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह घाटी आने के बजाए चंडीगढ़ से सीधे दिल्ली पहुंच गए। उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो कल शाम तक श्रीनगर में थे, गुरुवार सुबह वह भी दिल्ली में नजर आए। दक्षिण कश्मीर से नेकां सांसद हसनैन मसूदी भी दिल्ली में थे।

उमर बोले, पीएम से जल्द चुनाव कराने का किया आग्रह : डॉ. अब्दुल्ला ने उमर और हसनैन मसूदी के साथ सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सभी को हैरान कर दिया। करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद उमर ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। डॉ. अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को बताया कि जम्मू-कश्मीर में एक साल से निर्वाचित सरकार नहीं है। इससे कई प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसलिए राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव कराएं जाएं। उमर ने 35ए का हवाला देते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए, जिससे राज्य विशेषकर कश्मीर के हालात बिगड़ें।

लोन ने कहा-इस मुलाकात की कुछ तो वजह होगी : पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने डॉ. फारूक और उमर की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अचानक हुई इस मुलाकात की कुछ तो वजह होगी। लोन ने ट्वीटर पर लिखा, उमर और फारूक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने से पहले सर्वदलीय बैठक का विकल्प क्यों नहीं अपनाया। क्या यह सिर्फ मौके का फायदा उठाने का प्रयास है या फिर आर्थिक अपराधों के लिए क्षमायाचना के लिए है।

वहीं, पीपुल्स यूनाईटेड फ्रंट के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चला रहे पूर्व नौकरशाह शाह फैसल ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेकां कुछ हासिल करने की हड़बड़ी में है या फिर हाल ही में डॉ. फारूक से ईडी की पूछताछ के बाद वह प्रधानमंत्री के साथ नजदीकियां साबित करना चाहती है।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एएनआइ

अर्थव्यवस्था और मंदी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संसद के बाहर और भीतर बोला हमला, तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग

कांग्रेस ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और मंदी के मुद्दे पर सरकार को संसद के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर घेरा। संसद के बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जहां अर्थव्यवस्था के बेपटरी होने और मंदी के पूरी ताकत से आने का मुद्दा उठाया, वहीं दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि अकेले आटोमोबाइल सेक्टर में दस लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की।

राहुल ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था के लगातार कमजोर और बेपटरी होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को फिर घेरा। साथ ही कहा कि मंदी ट्रेन की रफ्तार की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री को संबोधित अपने ट्वीट में राहुल ने कहा कि यदि कोई उन्हें इससे बचने का भरोसा दिला रहा है तो वह पूरी तरह से गलत है।

कांग्रेस ने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2018 में करीब 1.10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। स्थिति यह है कि पांच लाख कारें और तीस लाख दोपहिया वाहन बिके ही नहीं। लगभग सौ कार डीलरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इसके साथ ही पिछले 40 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इस साल अकेले आटोमोबाइल सेक्टर में लगभग दस लाख मजदूर बेरोजगार होने जा रहे हैं। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए दिग्विजय ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। गौरतलब है कि राहुल ने बुधवार को भी ट्वीट कर अर्थव्यवस्था और मंदी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला था।

लोकसभा में विपक्ष ने विचार-विमर्श के बिना विधेयक लाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने गुरुवार को लोकसभा में सरकार पर विपक्षी पार्टियों को संज्ञान में लिए बिना इस सत्र में विधेयक लाने का आरोप लगाया। सरकार ने जहां इन आरोपों को खारिज किया वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा करने की बात कही। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सदन में लाए जाने वाले विधेयकों के बारे में सदस्यों को एक दिन पहले सूचना अवश्य मिल जाए।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार सूचित किए बिना विधेयक ला रही है, इससे सांसदों को तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है। हमारी मांग है कि सरकार कम से कम दो दिन पहले विधेयक के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में

- सरकार ने कहा, कार्य मंत्रणा समिति में तय कार्यक्रमों के तहत लाए जा रहे हैं विधेयक
- स्पीकर बोले-सदस्यों को एक दिन पहले बिल की जानकारी देना करेंगे सुनिश्चित

जो तय हुआ था उसी के तहत विधेयक लाए गए हैं। बुधवार की कार्यसूची में अंकित बांध सुरक्षा विधेयक गुरुवार को नहीं लाया गया, क्योंकि कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा था कि इसे बाद में लाया जाए। इस पर चौधरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि नदी जल बंटवारे से संबंधित संशोधन विधेयक और बांध सुरक्षा विधेयक पर अलग-अलग चर्चा होनी चाहिए। चौधरी ने साफ कहा कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि बांध सुरक्षा विधेयक गुरुवार को नहीं लाया जाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से विधेयक के बारे में सदस्यों को समय से सूचित नहीं किया जा रहा है।

एजेंडे की संशोधित सूची के लिए करना पड़ता है देर रात तक इंतजार : कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि पहले सूचित किया गया था कि गुरुवार को नियम 193 के तहत बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होगी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विस्तारित सत्र है, जिसमें नियम 193 के तहत चर्चा नहीं हो सकती। द्रमुक की कनीमोरी ने कहा कि अगले दिन के एजेंडे की संशोधित सूची के लिए देर शाम तक इंतजार करना पड़ता है। जब सूची सामने आती है तो इसमें पूरी तरह से नए बिल लाए जाने की सूचना होती है। सदन का अपना शिष्टाचार है और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इसे खत्म नहीं करेगी। सत्र का समय बढ़ाया गया था और हम सहयोग कर रहे हैं। हमें कमजोर नहीं समझें।

राजीव गांधी के योगदान से नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व पीएम के 75वें जयंती वर्ष पर देश भर में होंगे बड़े आयोजन
- राज्यों की राजधानी समेत 20 अगस्त को दिल्ली में भी होगा बड़ा कार्यक्रम

राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रही कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कार्यक्रम करेगी। इस जयंती वर्ष के दौरान मतदान की उम्र 18 साल करने, कंप्यूटर और संचार क्रांति के माध्यम से पार्टी युवा पीढ़ी को कांग्रेस के योगदानों से रूबरू कराने का प्रयास करेगी। साथ ही असम, पंजाब और मिजोरम जैसे राजीव सरकार के बड़े समझौतों के जरिये देश में शांति का नया दौर कायम करने के बारे में आम लोगों को बताया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष समारोह का भी पूरे साल देशव्यापी आयोजन करेगी।

कांग्रेस महासचिवों, राज्यों के प्रभारियों और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। राहुल गांधी की गैरमौजूदगी में पार्टी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल की अगुआई में हुई इस बैठक में तय किया गया कि 20 अगस्त को राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर सभी राज्यों की राजधानी के अलावा दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद राजीव जयंती वर्ष के आयोजन के लिए कांग्रेस की एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे साल देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाएगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि राजीव गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति और प्रधानमंत्री के तौर पर अंकित है जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रजातंत्र का हिस्सा बनने का अधिकार दिया। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिये लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के योगदान के बारे में देश की जनता को बताना जरूरी है। खासतौर पर नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए यह तैयारी की गई है।

रणदीप सुरजेवाला फाइल फोटो

आइटी और संचार क्रांति के लिए राजीव हमेशा याद किए जाएंगे : सुरजेवाला

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने असम समझौता, मिजोरम समझौता और पंजाब शांति समझौते जैसे ऐतिहासिक कदमों के जरिए देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। इसी तरह देश में युवा वर्ग को लोकतंत्र का भागीदार बनाने के लिए मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने का क्रांतिकारी कदम उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि आज के मौजूदा बहुत सारे हुक्मरान राजीव गांधी और उनके साथियों का ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि ये कंप्यूटर ब्वॉयज है, लेकिन आज आइटी व सॉफ्टवेयर क्रांति, टेलीकॉम क्रांति ने देश का नक्शा बदल कर रख दिया और राजीव गांधी इतिहास में हमेशा इसके लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का स्वप्न और रास्ता दोनों राजीव गांधी ने तैयार किए थे। इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि युवाओं, महिलाओं से लेकर समाज के हर वर्ग के बीच राजीव गांधी के इन योगदानों और भारत निर्माण के कांग्रेस के बड़े दृष्टिकोण से रूबरू कराया जाएगा।

बेअदबी मामला

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बाद एडवोकेट जनरल ने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर उठाए सवाल

विस सत्र से पहले बेअदबी मामले पर पंजाब सरकार रक्षात्मक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- सीबीआइ से मामले वापस लेने के बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं : नंदा
- सितंबर 2018 में जारी हो गया था मामला वापस लेने का नोटिफिकेशन
- आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सीबीआइ द्वारा अदालत में दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को लेकर सरकार रक्षात्मक हो गई है। पहले खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस रिपोर्ट को खारिज किया तो अब पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) अतुल नंदा ने सीबीआइ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने सीबीआइ से यह केस वापस ले लिया था। ऐसे में राष्ट्रीय एजेंसी के पास क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के कोई अधिकार नहीं था। सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है।

हालांकि इस मामले को लेकर दुविधा बनी हुई है कि जिस केस की जांच सीबीआइ ने शुरू कर दी हो क्यों उसे वापस लिया जा सकता है? अतुल नंदा से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वह एक बैठक में हैं। राज्य सरकार ने सितंबर 2018 में सीबीआइ से मामलों को वापस लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। नंदा ने कहा है कि जब सरकार ने जांच वापस लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, उसी समय सीबीआइ का अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया। सीबीआइ को क्लोजर रिपोर्ट दायर करने की बजाय यह बताना चाहिए था कि अब वह जांच नहीं कर रही है।

एजी का मानना है कि सीबीआइ का अदालत में अचानक क्लोजर रिपोर्ट देने का फैसला पेचीदा है। उसके इस कदम से साफ है कि आरोपितों को क्लीन चिट देने के लिए जांच एजेंसी जल्दी में थी। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने पंजाब सरकार को क्लोजर रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया, जबकि सीबीआइ ने पंजाब पुलिस की रिपोर्ट और इनपुट का हवाला दिया है।

सीबीआइ के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी : इस मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए नंदा ने कहा है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस अस्टेब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6 के तहत सीबीआइ काम करती है। इस धारा में किसी भी राज्य जहां पर घटना हुई है वहां की सरकार से जांच के लिए सहमति लेना जरूरी है। छह सितंबर 2018 को मौजूदा सरकार ने सीबीआइ से उक्त मामलों को वापस लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। कुछ आरोपित पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर 25 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय इसे कानूनी रूप से बरकरार रखा था।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

हाई कोर्ट में सीबीआइ ने नहीं दी जानकारी

नंदा ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात को नोट भी किया था कि सीबीआइ ने तीन सालों में अपनी जांच में कोई प्रगति नहीं की है। कोर्ट द्वारा सीबीआइ के वकील से बार-बार पूछने के बावजूद उन्होंने सही स्थिति से अवगत नहीं करवाया। जांच में सीबीआइ के विफल रहने के बाद पंजाब सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने काफी प्रगति की है। कुछ आरोपियों से पूछताछ करके एसआइटी ने अन्य आरोपितों की भूमिका का भी पता लगाया। इसमें मोबाइल फोन, चिप, गोली सिक्का और यहां तक कि छह करोड़ रुपये के फंड का भी पता लगाया गया।

25 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड देकर झारखंड आयुष्मान भारत की वर्षगांठ मनाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की।

ईडी ने आरईआइ एग्रो की 481 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

कार्रवाई ▶ 3,871.71 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले से संबंधित इस मामले की सीबीआइ भी कर रही है जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने कई करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले के मामले में आरईआइ एग्रो लिमिटेड की 481 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। मनी लांड्रिंग के मामले में फंसी यह कंपनी बासमती चावल का प्रसंस्करण करती है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि कंपनी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का प्राथमिक आदेश जारी किया गया। कंपनी के खिलाफ 2016 में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 3,871.71 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले से संबंधित है। इस मामले की जांच सीबीआइ भी कर रही है। ईडी ने कहा कि कुल 481.04 करोड़ रुपये की जब्त की गई संपत्तियों में जमीन, भवन, चावल मिल मशीनें, कंपनी के दफ्तर आदि शामिल हैं। इसमें आरईआइ एग्रो लिमिटेड की पवन ऊर्जा योजना भी शामिल है। फ्यूचर ग्रुप की कोलकाता स्थित चार कंपनियों की अचल संपत्ति के पचास फीसद शेयर जब्त किए गए हैं।

जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों संदीप झुनझुनवाला, संजय झुनझुनवाला और अन्य ने यूको बैंक की फ्लैगशिप शाखा की अगुवाई में विभिन्न बैंकों

से 2013 के बाद से कर्ज लिया। ईडी ने कहा कि उन्होंने जिस उद्देश्य से ऋण लिया उस पर रकम खर्च न कर धन का दूसरे कार्यों में हेरफेर किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि यह धोखाधड़ी 3,871.71 करोड़ की है।

ईडी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किये गये संदीप झुनझुनवाला एवं अन्य ने फर्जी बिलों, वर्सना इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य नियंत्रित कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश, निर्माण का अधिक खर्च बताकर तथा अन्य तरीकों से 14 बैंकों से परिचालन के लिए मिले कर्ज का हेरफेर किया। संदीप ने कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों के जरिये करीब 600 करोड़ रुपये का हेरफेर किया। जांच एजेंसी ने इससे पहले भी इस मामले में संपत्तियां कुर्क की हैं। अब तक 1,065.77 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

आतंकी फंडिंग में कारोबारी वटाली की 1.73 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **हाफिज सईद, आइएसआइ, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग व दुबई से धन प्राप्त करने का आरोप**
- **प्रवर्तन निदेशालय वटाली की नौ करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले भी कर चुका है जब्त**

लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और आइएसआइ से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में सक्रिय अलगाववादियों और आतंकियों तक पहुंचाने के आरोप में कारोबारी जहूर अहमद वटाली की कुछ और संपत्तियां जब्त की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही जहूर वटाली की लगभग नौ करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है। ताजा मामले में उसकी 1.73 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी फंडिंग व मनी लांड्रिंग की जांच का सामना कर रहा वटाली दुबई से आए 1.74 करोड़ रुपये के स्रोत की जानकारी देने विफल रहा। माना जा रहा है कि यह पैसा आइएसआइ या हाफिज सईद की ओर से आतंकी फंडिंग के रूप में भेजा गया था। इसलिए, इसी रकम के बराबर उसकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। इनमें वटाली के रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज 1.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के साथ ही जम्मू-कश्मीर बैंक की दिल्ली शाखा में जमा 25 लाख रुपये भी शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके पहले वटाली की उन संपत्तियों को जब्त किया गया था, जो हवाला के मार्फत से भेजी गई आतंकी फंडिंग के पैसे से बनाई गई थीं।

उल्लेखनीय है कि एनआइए ने लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने उसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। ईडी ने पूर्व में कहा था कि वटाली हुर्रियत नेताओं के लिए धन एकत्रित करने में संलिप्त पाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, जांच में पता चला कि हुर्रियत नेताओं ने पाकिस्तान से बिचौलिये के जरिये और पाकिस्तानी उच्चायोग से सीधे धन प्राप्त किया। गुलाम मोहम्मद भट्ट के घर की तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज से भी इसकी पुष्टि हुई थी। दस्तावेज से पता चला था कि जहूर वटाली हाफिज सईद, आइएसआइ, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग व दुबई से धन प्राप्त कर रहा था।

मनी लांड्रिंग में रेलीगेयर के पूर्व प्रमोटरों के ठिकानों पर छापे

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्ववर्ती रेलीगेयर प्रमोटर बंधु मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है।

जांच एजेंसी की ओर से दायर इस मामले में बताया गया है कि दिल्ली में सात स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इसमें सिंह बंधुओं से जुड़े रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी, आरईएल एक्जीक्यूटिव एनके घोषाल, हेमंत ढींगरा के खिलाफ ईसीआइआर (एनफोर्समेंट केस इनफार्मेशन केस) दर्ज किया है।

पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) के शिकायत दर्ज करने के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत ईसीआइआर दायर की गई है। रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की सहायक कंपनी रेलीगेयर फिनवेस्ट (आरएफएल) ने सिंह बंधुओं और अन्य का नाम लेते हुए अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 740 करोड़ रुपये की धांधली की गई है। लेकिन सिंह बंधुओं ने कंपनी में हुई इस गफलत के लिए गोधवानी पर आरोप लगाया था। अपराध शाखा में दर्ज एफआइआर में धोखाधड़ी, धांधली और आपराधिक साजिश आदि आरोप लगाए गए हैं। फरवरी, 2018 तक सिंह बंधु आरईएल पर नियंत्रण रख रहे थे। इसी महीने वह आरईएल के बोर्ड से बाहर हो गए थे। उसके बाद आरईएल और आरईएफ के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2,397 करोड़ रुपये के गबन के इस मामले में आर्च फाइनेंस लिमिटेड और आरएचसी लिमिटेड जैसी कंपनियों की जांच कर रहा है। फोर्टिस और रैनबैक्सी के भी प्रमोटर रह चुके सिंह बंधु के आपसी संबंध भी हेल्थकेयर चेन में धन के डायवर्जन को लेकर खराब चल रहे हैं। दायची सांक्यो में मध्यस्थता पर अधिक भुगतान के बाद दोनों भाइयों में तनाव और बढ़ गया था। रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज के अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद पर जापानी दवा कंपनी को 3,500 करोड़ रुपये देने की शिवेंदर ने पेशकश की थी।

कानून बनने के बाद मथुरा में पहली बार दर्ज हुआ तत्काल तीन तलाक का मुकदमा

जागरण संवाददाता, मथुरा

मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट बनने के बाद मथुरा में तत्काल तीन तलाक का मुकदमा गुरुवार को दर्ज किया गया। महिला थाना प्रभारी रुचि त्यागी ने बताया कि इस कानून के लागू होने के बाद जिले में इस तरह का पहला मामला दर्ज किया गया है। इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार महिला थाने के बाहर दामाद एक लाख रुपये दहेज में न देने पर उसकी बेटी को एक साथ तीन तलाक बोलकर चला गया। मामला थाना कोसीकलां क्षेत्र का है।

दहेज उत्पीड़न से आजिज जुमीरत कुछ महीने पहले मायके आ गई। शौहर सहित ससुरालीजनों की शिकायत महिला थाने में की। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुलह के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि थाने के बाहर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। तभी जुमीरत के शौहर इकराम ने कहा कि जब तक उसे दहेज में एक लाख रुपये नहीं मिलेंगे, बीवी को ससुराल नहीं ले जाएगा। इतना ही नहीं, इकराम ने सबके सामने बीवी जुमीरत को एक साथ तीन पार तलाक बोला और चला गया।

ये हैं प्रावधान

- यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।
- मामला सिविल की श्रेणी से निकालकर आपराधिक श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
- मुकदमा दर्ज होते ही तत्काल तीन तलाक गैर कानूनी हो जाएगा।
- यह संज्ञेय अपराध माना जाएगा और बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान है।
- बिल में तीन साल तक की सजा और आरोपित पर जुर्माना भी लग सकता है।
- मजिस्ट्रेट आरोपित को जमानत दे सकता है बशर्ते महिला के बयान हो चुके हों।
- महिला गुजारा भत्ता और बच्चा पाने की अधिकारी, का निर्णय अदालत करेगी।

गुरुवार को पीड़िता के परिजन एसएसपी से मिले। इसके बाद जुमीरत की मां फाता की तहरीर पर महिला थाने में मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट की धारा यू-एस-4 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मोबाइल पर लिखकर भेजा दो बार 'तलाक'

जागरण संवाददाता, हाथरस : गुरुवार को तत्काल दो तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला थाने पहुंची शमा परवीन ने बताया कि उसके पति ने उसे मोबाइल पर दो बार 'तलाक' लिखकर मैसेज भेजने के बाद फर्जी तलाकनामा बनवाकर भेजा है। दो में से एक बेटे को चोरी-छिपे लेकर भाग गया। गुरुवार को मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने आनन-फानन तत्काल तलाक संबंधी नए कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया। शमां परवीनकी शादी अप्रैल 2010 में एहसान मिस्त्री से हुई थी। शमां का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उससे मारपीट करता आ रहा है। दिसंबर 2018 में पति उसे लेकर हाथरस में रहने लगा। शमां के अनुसार 15 जुलाई 2019 को मारपीट की। इसके बाद घर से चला गया। साथ ही एक बेटे को भी ले गया। इसके बाद मोबाइल पर 'तलाक-तलाक' लिखकर मैसेज भेज दिया। दूसरे दिन 10 रुपये के स्टांप पेपर पर फर्जी तलाकनामा बनवाकर भिजवा दिया।

तीन तलाक पर ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा नहीं मानेंगे कोई कानून

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: तत्काल तीन तलाक को अपराध करार देने वाले बिल पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, मगर बंगाल के एक मंत्री ने इस कानून को मानने से ही इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में जन शिक्षा व पुस्तकालय मामले के मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था तो सिद्दिकुल्ला ने उस फैसले को भी मानने से इन्कार कर दिया था।

तीन तलाक को लेकर बंगाल के मंत्री व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दिकुल्ला चौधरी ने विवादित बयान दिया और कहा कि तीन तलाक बिल पास होना दुख का विषय है। यह इस्लाम पर हमला है। सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम तीन तलाक पर बने कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि जब इस पर केंद्रीय कमेटी की मीटिंग होगी तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर ममता के मंत्री इस विवादित बयान से आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है। विशेष कर बंगाल में भाजपा के हमलावर रुख का सामना कर रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर एक बार फिर मुसीबत झेलनी पड़ सकती है।

आइएमए पोंजी घोटाले में मुहम्मद मंसूर खान को 14 तक न्यायिक हिरासत

बेंगलुरु, एएनआइ : आई मॉनिटरी एडवाइजरी (आइएमए) पोंजी घोटाले में मुख्य आरोपित मुहम्मद मंसूर खान को 14 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उसकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई कस्टडी एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई थी। इस घोटाले के अन्य आरोपित कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान तो एसआइटी के समक्ष पेश हुए, लेकिन अयोग्य घोषित किए जा चुके कर्नाटक के विधायक रोशन बेग खराब तबीयत का हवाला देकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए।

बता दें कि इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 30 हजार मुसलमानों को चूना लगाने वाला मुहम्मद मंसूर खान करीब 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर दुबई भाग गया था। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया था।

मंसूर पहले दुबई चला गया था और फिर बाद में भारत लौटने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विगत शुक्रवार को नई दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि मुहम्मद मंसूर खान की कंपनी आइएमए में एक लाख से अधिक लोगों ने निवेश किया था। इसकी कुल 17 कंपनियां हैं। मंसूर खान अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों से इन कंपनियों में निवेश करने का आग्रह करता

मुहम्मद मंसूर खान फाइल फोटो

था। एसआइटी के मुताबिक इस फर्जी कंपनी में 4,084 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया था और खान को अपने निवेशकों को 1400 करोड़ रुपये लौटाने थे।

डीआइजी और आइएमए पोंजी स्कीम घोटाले में एसआइटी प्रमुख रविकांत गौड़ा ने बताया कि एसआइटी अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए गुरुवार को जमीर अहमद खान तो पेश हुए, लेकिन रोशन बेग पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि फरार होने से पहले मुहम्मद मंसूर खान ने शिवाजीनगर के विधायक आर. रोशन बेग पर 400 करोड़ रुपये नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। बेग बाद में उन बागी विधायकों के खेमे में शामिल हो गए थे, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। एसआइटी ने बेग को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने 26 जुलाई तक का समय मांगा। इस पर एसआइटी ने उन्हें 19 जुलाई से पहले पेश होने को कहा था। लेकिन बेग बीमार होने की दलील देकर गुरुवार को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच निकले।

इस्लामिक बैंकिंग के नाम किया था घोटाला : मैनेजमेंट ग्रैजुएट मुहम्मद मंसूर खान ने 2006 में आई मॉनिटरी एडवाइजरी (आइएमए) के नाम से इस्लामिक बैंकिंग का कारोबार शुरू किया और निवेशकों को बताया कि यह संस्था बुलियन में निवेश करेगी और निवेशकों को 7-8 फीसद रिटर्न देगी। चूंकि इस्लाम में ब्याज से मिली रकम को अनैतिक और इस्लाम विरोधी माना जाता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए मंसूर ने धर्म का कार्ड खेला और निवेशकों को 'बिजनेस पार्टनर' का दर्जा दिया और भरोसा दिलाया कि 50 हजार के निवेश पर उन्हें तिमाही, छमाही या सालाना अवधि के अंतर्गत 'रिटर्न' मिलेगा। इस तरह वह मुसलमानों के बीच 'ब्याज हराम है' वाली धारणा तोड़ने में कामयाब रहा। अपनी फर्जी स्कीम को आम मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए उसने स्थानीय मौलवियों और मुस्लिम नेताओं को अपने साथ ले लिया।

कार्ति चिदंबरम ने लगाया राजनीतिक द्वेष का आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए घर खाली करने के नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। विशेष अदालत में दायर की गई चुनौती में कहा गया है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को ईडी ने जोर बाग स्थित घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। यह घर ईडी ने एयरसेल मैक्सिस घोटाले में कुर्क किया था।

कार्ति की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उनके घर को कुर्क करने के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील विचाराधीन है और ऐसे में खाली करने का नोटिस देना गलत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ईडी, आयकर विभाग और सीबीआइ जैसी एजेंसियों को गलत तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ पिछले चार साल से इस्तेमाल कर रही है। घर को खाली करने का नोटिस भी बगैर किसी कारण के जारी किया गया है। क्योंकि उस घर में 50 फीसद हिस्सा ही उनका है, जबकि 50 फीसद उनकी मां नलिनी का है।

एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नौ अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। बुधवार को जांच एजेंसियों ने अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करने के लिए विशेष अदालत ने समय मांगा था।

रतुल पुरी की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई

जासं, नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने एक दिन के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में शुक्रवार को फिर से याचिका पर सुनवाई होगी। पिछले सप्ताह शनिवार को पुरी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर हर दिन सुनवाई हो रही है। ईडी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है, जबकि पुरी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें बेवजह हिरासत में लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, ईडी ने अदालत में कहा कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे और हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है।

रक्षा मंत्री को भेंट की मां लक्ष्मी की मूर्ति...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नई दिल्ली में राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा ने मां लक्ष्मी की मूर्ति भेंट की। इस दौरान पेट्रोलियम और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत ओडिशा के कई सांसद भी मौजूद रहे। स्रोत : मंत्री कार्यालय

अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जदएस के 14 बागी विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जदएस के 14 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन बागी विधायकों में 11 कांग्रेस और तीन जदएस के हैं। दोनों ही दलों ने बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इससे पहले कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जरकीहोली और महेश कुमाथल्ली के साथ ही एक निर्दलीय आर शंकर को 25 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया था। ये तीनों नेता 29 जुलाई को शीर्ष कोर्ट में अपील कर चुके हैं।

विस अध्यक्ष ने जिन जद-एस विधायकों को अयोग्य ठहराया है, उनमें एएच विश्वनाथ, के गोपालैया और नारायण गौड़ा हैं। तीनों ने अयोग्य ठहराए जाने के 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए एक संयुक्त याचिका दायर की है।

भाजपा नेता की विवादित टिप्पणी से ओडिशा विधानसभा में हंगामा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- **विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक**
- **बीजू जनता दल एवं कांग्रेस ने विष्णु सेठी के बयान पर जताई आपत्ति**

भाजपा विधायक दल के उपनेता विष्णु सेठी के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को ओडिशा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तीन तलाक विधेयक को लेकर सदन में हो रही चर्चा के दौरान सेठी के विवादित बयान पर हुए हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सूर्यनारायण पात्र ने सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक स्थगित कर दी। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

इससे पूर्व, भाजपा विधायक ने सदन में तीन तलाक पर अपना मत रखते हुए कहा कि तीन तलाक की प्रथा कई मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं हैं। ऐसे में तीन तलाक बिल कानून में तब्दीली होने से वर्ग विशेष की महिलाएं लाभान्वित होंगी। शादी के बाद आसानी से तलाक मिल जाने से पति द्वारा छोड़ी गईं वर्ग विशेष की महिलाओं को रेड लाइट इलाके में देखा जाता है। मुंबई और कोलकाता में इसके उदाहरण देखने को मिले हैं। विष्णु सेठी के इस बयान पर बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के विधायक इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सदन में हंगामा करने लगे। सदन में हंगामा होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

वर्ग विशेष की महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र ने कहा कि विधानसभा में टिप्पणी रखने से पहले विरोधी दल के उपनेता को संयम बरतना चाहिए। वहीं, बीजद के नेताओं ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी स्वीकार योग्य नहीं है।

टिप्पणी पर सेठी ने दी सफाई : विवाद को बढ़ता देख भाजपा नेता सेठी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैंने एक रिपोर्ट के आधार पर वह प्रसंग उद्धृत किया। किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए हमने यह बात नहीं की और ना ही करेंगे। परिस्थिति के दबाव में आकर वर्ग विशेष की महिलाएं देह व्यापार में शामिल हो रही हैं। यह बात यूनिसेफ रिपोर्ट में भी आई है। मैंने अगर यह बात कह दी तो उसमें क्या गलती हो गई। विधानसभा में यह बात कहने में कोई असुविधा नहीं है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए बेवजह मेरी बात को तूल दिया जा रहा है।

बोले राजनाथ

महाराष्ट्र में दोबारा जीत के संकल्प के साथ सीएम फड़नवीस की महाजनादेश यात्रा को रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

भाजपा-शिवसेना गठबंधन 250 से ज्यादा सीटों का रखे लक्ष्य

ओमप्रकाश तिवारी, अमरावती

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र भाजपा और शिवसेना गठबंधन को 250 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है। वह गुरुवार को अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की महाजनादेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले भाजपा की जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

महाराष्ट्र में भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। अमरावती में आयोजित सभा में राजनाथ और फड़नवीस ने जनता से एक बार फिर भाजपा सरकार को महाजनादेश देने की अपील की। इस अवसर पर राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए राजनाथ ने कहा कि जिस प्रकार जनता ने केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार की भारी बहुमत से वापसी कराई है, उसी प्रकार राज्य में भी फड़नवीस सरकार को वापस लाएं। राजनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इसके बावजूद जब चुनाव बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो वह जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। हमें भरोसा है कि इस बार यदि जनता ने उन्हें महाजनादेश दिया तो वह उनका दिल जीतने में भी कामयाब रहेंगे। राजनाथ के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार ने कई साहसी कदम उठाए हैं। उनमें से एक तीन तलाक विधेयक सामने है। ऐसे में राज्य में भाजपा और इसके सहयोगियों को 220 नहीं, बल्कि 250 सीटों से अधिक जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं।

महाराष्ट्र के अमरावती में गुरुवार को महाजनादेश यात्रा को रवाना करने से पहले आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से चर्चा करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एएनआइ

मुख्यमंत्री फड़नवीस भी पूरी तरह जंग के मूड में दिखे। अपने भाषण में जहां उन्होंने पिछली कांग्रेस-राकांपा सरकार को फेल बताया, वहीं अपनी सरकर को उनकी तुलना में दोगुना कामयाब बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए पिछले पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस-राकांपा की सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में 20 हजार करोड़ रुपये से भी कम खर्च किए। फड़नवीस ने कहा, मैं जनता के पास जाकर इस यात्रा के माध्यम से अपने पांच वर्ष के काम की जानकारी दूंगा और उनसे अगले पांच वर्ष के लिए महाजनादेश भी लूंगा। उनके आदेश का पालन करूंगा। फड़नवीस ने उम्मीद जताई कि इस बार भी महाजनादेश भाजपा को ही मिलेगा।

बता दें कि संत तूकड़ों जी महाराज की कर्मभूमि से महाजनादेश यात्रा का प्रारंभ किया गया है, जो दो चरणों में 24 दिन चलेगी और 31 अगस्त को नासिक में समाप्त होगी। इस दौरान यह राज्य के सभी 32 जिलों से होकर गुजरेगी।

गैर हिंदू से डिलिवरी नहीं लेने का विवाद पहुंचा पुलिस तक, जांच के आदेश

नईदुनिया, जबलपुर

- **जोमैटो ने शिकायत कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप**
- **पुलिस ने खाना मंगाने वाले अमित शुक्ला को नोटिस देने की तैयारी की**

जोमैटो और जबलपुर के एक ग्राहक के बीच डिलिवरी के लिए भेजे गए गैर हिंदू युवक को लेकर उपजा विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। मामले में दिल्ली से जोमैटो कंपनी द्वारा भेजा गया पत्र मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही खाना मंगाने वाले अमित शुक्ला को भी नोटिस देने की तैयारी कर ली गई है। जोमैटो ने पत्र में अमित शुक्ला पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि अमित शुक्ला ने यह कहते हुए डिलिवरी लेने से इन्कार कर दिया था कि डिलिवरी देने वाला गैर हिंदू है। इसके साथ ही इसको लेकर ट्वीट कर दिया था। इसके जवाब में जोमैटो ने भी ट्वीट किया था। जोमैटो ने लिखा था कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता है। भोजन खुद एक धर्म है। जोमैटो द्वारा ट्विटर पर दिए गए जवाब की सोशल मीडिया में काफी तारीफ हुई थी। जोमैटो ने अब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अमित के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) को पत्र भेजा है। कंपनी ने घटनाक्रम का ब्योरा पत्र में लिखा है, इसके अलावा यह भी कहा है कि ग्राहक ने इसे ट्विटर पर डाला, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए पत्र में दी गई जानकारी को रिकॉर्ड में लिया जाए।

एसपी ने इस मामले में अधीनस्थ अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। आधिकारिक शिकायत का पत्र मिलने पर जबलपुर निवासी अमित शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसपी अमित सिंह ने बताया कि अमित शुक्ला को नोटिस भेजकर पूछा जाएगा कि क्या आपने इस मामले को ट्विटर पर डाला था और यदि ऐसा किया है तो क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

1.5 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तकनीकी संपर्क इकाई (आइटीएलयू) पर। कैबिनेट ने मॉस्को में इसरो की आइटीएलयू स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इसरो रूस के सहयोग से गगनयान परियोजना पर काम कर रहा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 अगस्त 2019

योगी सरकार पर विपक्ष और हमलावर, मुख्यमंत्री-डीजीपी निशाने पर

उन्नाव दुष्कर्म कांड ▶ सुप्रीम कोर्ट के दखल से विपक्ष की मुहिम को मिली और ताकत, विपक्षी पार्टियों ने निकाले जुलूस और किया कैंडिल मार्च

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से विपक्ष की सरकार विरोधी मुहिम को ताकत मिली है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले के आरोपितों को योगी सरकार का समर्थन हासिल है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडिल पर पोस्टर जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डीजीपी ओपी सिंह व आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर के चित्र भी हैं। पोस्टर के शीर्षक में लिखा है- इन तीनों के हटे बिना उन्नाव की पीड़ित बेटी को न्याय नहीं मिलेगा।

अखिलेश बोले, लोकतंत्र में इससे बुरे दिन नहीं: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी कर पीड़िता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोपित विधायक को प्रदेश के बाहर जेल में स्थानांतरित करना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में अपराधियों को ही प्रश्रय दिया। इससे अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। प्रदेश की बदनामी दुनिया भर में हो गई है। लोकतंत्र में अब इससे बुरे दिन कभी नहीं आ सकते।समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट भी किया गया- 'उन्नाव मामले में यूपी सरकार के मुंह पर सुप्रीम तमाचा! सारे केस दिल्ली ट्रांसफर, 45 दिन में सुनवाई पूरी, परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा, 25 लाख रुपये का मुआवजा।'

कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा: उन्नाव के माखी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कांग्रेस ने योगी सरकार के मुंह पर तमाचा बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि मामले से जुड़े पांच मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्देश ने साफ कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी सरकार की न्याय और जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों की आस्था भारत की न्याय प्रणाली में मजबूत हुई है। कांग्रेस लगातार आंदोलन कर पीड़ितों के लिए जो मांग कर रही थी। कोर्ट ने उनका स्वतः संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। तिवारी ने कहा कि इस मामले में जितने भी आरोपित हैं, उन्हें भाजपा सरकार संरक्षण दे रही थी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू का कहना था कि पीड़िता और वकील को उच्चस्तरीय इलाज, सभी पीड़ितों को एक-एक करोड़ रुपये सहायता राशि मिले।

लखनऊ में गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के लिए हजरतगंज में मशाल जुलूस निकालते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकते पुलिसकर्मी। जागरण

बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजी जा सकती है पीड़िता

जागरण संवाददाता, लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल कालेज में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा सकता है। चिकित्सकीय बोर्ड ने इस पर सहमति जता दी है। बोर्ड का कहना है कि पीडिता को एयरलिफ्ट करना संभव है। डॉक्टरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती दुष्कर्म पीड़िता के बारे में दो प्रश्न पूछे थे।

पहला यह कि दुष्कर्म पीड़िता को इलाज के लिए क्या दिल्ली एयर लिफ्ट करना संभव है। दूसरा, क्या केजीएमयू में उसका इलाज मुमकिन है। इस पर गुरुवार को ही केजीएमयू प्रशासन ने तुरंत छह सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया। बोर्ड ने सभी चिकित्सकीय रिपोर्ट का अध्ययन के बाद दिल्ली एयर लिफ्ट करने पर सहमति दे दी। वैसे बोर्ड ने पीड़िता का केजीएमयू में भी इलाज मुमकिन बताया है।

कुछ देर के लिए हटा वेंटीलेटर : केजीएमयू के मीडिया प्रवक्ता डॉ. संदीप तिवारी के मुताबिक, पीड़िता का दोपहर में कुछ देर के लिए वेंटीलेटर हटाया गया, मगर हालत बिगड़ने लगी। ऐसे में उसे दोबारा वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं, घायल वकील को दो-दो घंटे बिना वेंटीलेटर सपोर्ट के रखने का प्रयास किया जा रहा है।

पीड़िता की कार से सात घंटे पहले टोल से गुजरा था ट्रक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद सीबीआइ और सक्रिय हो गई है। गुरुवार को सीबीआइ की एक टीम ने 'कातिल' ट्रक के रूट की पड़ताल भी की। सीबीआइ की एक टीम ने गुरुवार को लालगंज-रायबरेली मार्ग पर स्थित अइहर टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में मौरंग लदा ट्रक अलसुबह 5.19 बजे टोल प्लाजा से निकला। दोपहर 12.32 पर पीड़िता की कार वहां से गुजरी। दोपहर लगभग एक बजे अटौरा के पास सुलतानपुर मोड़ के निकट हादसा हो गया। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ की जानकारी में आया है कि जिस कार में पीड़िता व उनके परिजन सवार थे, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जबकि ट्रक की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रति घंटा थी। ट्रक गलत दिशा में था।

वहीं बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई से जुड़े लोगों के मुताबिक, अगर मौरंग लदा ट्रक 6.30 बजे भी रायबरेली पहुंचा होगा और शहर में ही कहीं उसकी अनलोडिंग हुई होगी तो उसमें कम से कम तीन घंटे का वक्त लगता है। फिर ट्रांसपोर्ट से माल का मूल्य लेने में एक घंटे का वक्त लग जाता है। ट्रक को यहां से निकलते-निकलते 12 बज गया होगा। जिस रफ्तार से ट्रक निकला था, वो संदेह पैदा कर रहा है।

आज रायबरेली पहुंचेगी टीम : दिल्ली से सीबीआइ के फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेगी और रायबरेली जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। वहीं पीड़िता का हाल जानने गुरुवार को सीबीआइ टीम भी ट्रामा सेंटर पहुंची और इसके घरवालों से मुलाकात करके घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। टीम ने घायल अधिवक्ता के घरवालों से भी बातचीत की। सीबीआइ ने ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल के दो मोबाइल नंबरों के अलावा ट्रक मालिक के भाई दिलीप पाल, चालक आशीष व क्लीनर के मोबाइल फोन की एक माह की कॉल डिटेल हासिल की है।

दिल्ली महिला आयोग का तंज : दुष्कर्म पीड़िता से मिलने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बॉथम और सदस्य सुनीता बंसल भी गुरुवार को ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं। इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद भी मौजूद रहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अभी तक हरियाली तीज मना रहा था।

आज सीबीआइ कोर्ट में पेश होंगे चालक और क्लीनर : ट्रक चालक व क्लीनर शुक्रवार को सीबीआइ कोर्ट लखनऊ में पेश होंगे। इस आशय का पत्र गुरुवार देर शाम जिला कारागार के जेलर को मिला। ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन को बुधवार को ही 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। इस बीच केस सीबीआइ को स्थानांतरित हो गया।

रायबरेली-लालगंज मार्ग पर दुर्घटना से पहले ऐहार टोल प्लाजा पार करती कार। जागरण

पीड़िता की चिट्ठी सीजेआइ के सामने पेश करने में हुई देरी की जांच का आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीजेआइ की ओर से नामित न्यायाधीश करेंगे निगरानी
- कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल को जांच सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव कांड के अभियुक्तों की ओर से धमकाने की शिकायत वाली पीड़िता की चिट्ठी प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) के सामने पेश करने में हुई देरी पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया है कि वह जांच करके बताएं कि पीड़िता की चिट्ठी प्रधान न्यायाधीश के सामने पेश होने में हुई देरी में रजिस्ट्री के किसी अधिकारी की चूक या लापरवाही थी या नहीं। कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल को मामले की जांच सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया है। जांच की निगरानी प्रधान न्यायाधीश द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे।

इससे पहले मामले पर सुनवाई के दौरान सेक्रेटरी जनरल ने चिट्ठी पेश करने में हुई देरी पर सफाई देते हुए कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हर महीने करीब 5,800 पत्र आते हैं जिन्हें लैटर पिटीशन (पत्र याचिका) कहा जाता है। इस महीने करीब 6,900 पत्र सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुए, जिनमें से एक पत्र पीड़िता का भी था। सेक्रेटरी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 1988 के फैसले के मुताबिक हर चिट्ठी की स्क्रूटनिंग होती है। पीड़िता की चिट्ठी 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुई थी। इस चिट्ठी की भी जांच हो रही थी। उन्हें पीड़िता और उसकी मां के नाम की जानकारी नहीं थी। जैसे ही चिट्ठी के बारे में उन्हें पता चला तो 30 जुलाई को चिट्ठी सामने पेश की गई।

पीड़िता को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट सुबह से दिखा तत्पर: पीड़िता के साथ न्याय करने के लिए कोर्ट कितना तत्पर था इसकी झलक गुरुवार सुबह कोर्ट शुरू होते ही दिखी। जैसे ही अदालत मुकदमों की सुनवाई के लिए बैठी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अदालत कक्ष में बैठे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सीबीआइ निदेशक से बात करें और 12 बजे सीबीआइ का कोई जिम्मेदार अधिकारी पेश होकर कोर्ट को मामले की जांच स्थिति बताए। थोड़ी देर बाद मेहता ने कहा कि सीबीआइ निदेशक ने कहा है कि मामले की जांच लखनऊ में हो रही है इसलिए सारे रिकॉर्ड लखनऊ में हैं। जैसे ही पहली फ्लाइट मिलेगी, रिकॉर्ड दिल्ली मंगाया जाएगा। मेहता ने कोर्ट से सुनवाई शुक्रवार तक टालने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट इसके लिए राजी नहीं हुआ। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआइ निदेशक जांच अधिकारी से जांच की प्रगति पता करके आज ही कोर्ट बताएं। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना की जांच भी सीबीआइ को सौंप दी गई है। इसके बाद 12 बजे सीबीआइ की संयुक्त निदेशक संपत मीणा कोर्ट में पेश हुईं और जांच की स्थिति कोर्ट को बताई गई। कोर्ट ने कहा सात दिन में जांच पूरी होनी चाहिए।

सेंगर के निष्कासन पर असमंजस में रही पार्टी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कुलदीप सेंगर को लेकर भाजपा पिछले कई दिनों से असमंजस में थी। लोग अचरज में थे कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी को कई दलों की खाक छानकर आये सेंगर को बाहर करने का फैसला लेने में इतनी देर लगी। आखिरकार पार्टी ने सेंगर को गुरुवार को बाहर का रास्ता दिखा ही दिया।

सभी दलों ने दिया है सेंगर को मौका : कुलदीप सेंगर जेल में रहते हुए भी उन्नाव की राजनीतिक डोर संभाले हैं। सांसद साक्षी महराज जैसे दिग्गज भी लोकसभा चुनाव में उनकी मदद के लिए जेल जाकर कृतज्ञता जता चुके हैं। सेंगर के खिलाफ विपक्ष भले आंदोलित है, लेकिन यह भी सही है कि सभी दलों ने उन्हें मौका दिया है। कांग्रेस से सफर शुरू करने वाले सेंगर ने 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्नाव से बसपा के टिकट पर जीत हासिल की। 2007 में क्षेत्र और पार्टी बदल दी और वह बांगरमऊ से सपा के विधायक हो गए। फिर 2012 में वह सपा के ही टिकट पर भगवंतनगर से चुनाव जीते। 2017 में वह भाजपा के टिकट पर फिर बांगरमऊ से चुनाव लड़े और जीत गए। उन्नाव में कुल छह विधानसभा क्षेत्र हैं।

पंद्रह महीने में भी कुलदीप सेंगर के हथियार लाइसेंस रद नहीं कर सका प्रशासन

जागरण संवाददाता, उन्नाव

- जिला प्रशासन में विधायक की हनक, आपत्ति के बाद दवा दी गई निरस्तीकरण की फाइल
- विधायक के पास सिंगल बैरल बंदूक, रायफल और रिवाल्वर का लाइसेंस है

कुलदीप सिंह सेंगर की प्रशासन में अब भी हनक कायम है। विधायक के रसूख के आगे प्रशासनिक अधिकारी जायज कार्रवाई करने से भी कतराते हैं। पंद्रह महीने पहले विधायक के शस्त्र लाइसेंस रद करने की पुलिस ने जो रिपोर्ट दी, उस पर आज तक अफसर निर्णय नहीं ले सके और लाइसेंस निरस्तीकरण की फाइल दबी है। सीबीआइ ने 13 अप्रैल 2018 विधायक को जेल भेजा था। विधायक के पास सिंगल बैरल बंदूक, रायफल और रिवाल्वर का लाइसेंस है। गिरफ्तारी के लगभग एक माह बाद विधायक के तीनों शस्त्र लाइसेंस रद करने की सिफारिश करते हुए पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंप दी थी। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की जिसमें लाइसेंसधारक की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद से लाइसेंस रद करने की फाइल धूल फांक रही है।

दवाब में नहीं दिया गया पीड़िता को लाइसेंस : विधायक का प्रशासन पर दबदबा कायम होने का प्रमाण इससे भी मिलता है कि जब 2008 में विधायक के भाई अतुल सिंह उर्फ जयदीप के खिलाफ एएसपी को गोली मारने का मुकदमा दर्ज हुआ था, तब उसका रिवाल्वर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। लेकिन कुलदीप सेंगर का अब तक न हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायक के दबाव में पीड़िता और उसके वकील महेंद्र सिंह को शस्त्र लाइसेंस नहीं दिए गए। दूसरी ओर विधायक के खास और दुष्कर्म पीड़िता की कार दुर्घटना के मामले में नामजद आरोपितों में शामिल सिंपल मिश्र का लाइसेंस अभी हाल में ही स्वीकृत किया गया है।

अब निलंबित हुए पीड़िता के सुरक्षा कर्मी : मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया है। पीड़िता की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस महकमे ने पहले उनके बचाव की कोशिश की थी लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी एमपी वर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की।

पीड़िता की सुरक्षा में तैनात पुरुष कांस्टेबल सुदेश कुमार (गनर), महिला आरक्षी रूबी पटेल और सुनीता देवी रविवार को हुई कार-ट्रक दुर्घटना के वक्त साथ नहीं थे। हादसे के दूसरे दिन पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह यह कहते हुए तीनों का बचाव करते दिखे थे कि पीड़िता ने खुद उन सभी को कार में जगह न होने की बात कहकर ले जाने से इन्कार कर दिया था। नियमतः वीआइपी सुरक्षा में लगे कर्मियों को कभी भी ऐसा होने पर तत्काल इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को देनी होती है। फोन न मिलने की सूरत में नजदीकी थाने से वायरलेस से संदेश देना होता है लेकिन उन सभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

हिज्ब आतंकी दबोचा, भारी मात्रा में हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षाबलों ने गुरुवार को बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को धर दबोचा। इसके साथ ही उत्तरी कश्मीर के बांडीपोर में आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया है। इस बीच, सुरक्षाबलों ने पांपोर से सटे खिरयू और संबूरा में छापेमार कर छह युवकों को पत्थरबाजी व आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में ले लिया।

जानकारी के अनुसार, वीरवार तड़के बडगाम पुलिस ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ चाड़ूरा के पास काजीपोरा इलाके में दबिश दी। जवानों को देखते ही वहां छिपे आतंकी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षाबलों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक एसाल्ट राइफल और कुछ अन्य विस्फोटकों के अलावा आतंकी संगठन से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं।

पकड़े गए आतंकी की पहचान शौकत अहमद तांत्रे के रूप में हुई है। वह दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के अंतर्गत तांत्रपोरा वारपोरा का रहने वाला है। अधिकारियों ने हिज्ब आतंकी शौकत के पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि उससे पूछताछ जारी है।

बांडीपोर से मिली सूचनाओं के मुताबिक, पुलिस के जवानों ने सेना की 13 जैकलाई के जवानों के साथ मिलकर चंदेजी बांडीपोर के ऊपरी हिस्से में स्थित लशकूट जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने जंगल में बने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया। हालांकि आतंकियों ने जवानों के पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना छोड़ दिया था, लेकिन उनके हथियारों का एक जखीरा वहीं छूट गया था। जवानों ने आतंकी ठिकाने से एसाल्ट राइफल के 700 कारतूस और खाने पीने का सामान बरामद किया। इसके बाद आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया। एक अन्य सूचना के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने जिला पुलवामा में पांपोर से सटे खिरयू और संबूरा में सक्रिय आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों और पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए बुधवार की रात अभियान चलाया था। गुरुवार सुबह तक चले इस अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने खिरयू से पांच और संबूरा से एक युवक को पकड़ा।

आदित्य ठाकरे ने चलाया हल...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान गुरुवार को राज्य के लातूर जिले में आदित्य ठाकरे खेत जोत रहे एक किसान के पास पहुंचे। आदित्य ने किसान के साथ आत्मीयता दर्शाते हुए न केवल कुशलक्षेम जाना बल्कि स्वयं भी हल पर हाथ आजमाया। एएनआइ

जम्मू-कश्मीर में 35ए का समर्थन करने वाले दो वकील निलंबित

जागरण संवाददाता, जम्मू

- जेएंडके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई, कुछ और वकीलों के नाम भी होंगे जारी

जेएंडके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 35ए का समर्थन करने वाले दो वकीलों को निलंबित कर दिया है। एसोसिएशन 24 घंटे में निलंबित किए गए कुछ और वकीलों के नाम जारी करेगी। एसोसिएशन की कार्यकारी कमेटी की गुरुवार सुबह हुई बैठक में 35ए का समर्थन करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने इन वकीलों से स्पष्टीकरण मांगा है। तब तक उनकी एसोसिएशन की बुनियादी सदस्यता निलंबित की गई है। गुरुवार को निलंबित किए गए वकीलों के नाम सीनियर एडवोकेट एवी गुप्ता और एडवोकेट एसपी गुप्ता हैं।

जेएंडके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट अभिनव शर्मा ने हाई कोर्ट परिसर में कहा कि 30 जुलाई को जम्मू के कुछ वकीलों ने बैठक कर 35ए का समर्थन किया था। इसे हटाने की बजाय मजबूत करने की वकालत की थी। इन वकीलों में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवी गुप्ता भी शामिल थे। चूंकि बैठक में बार के पूर्व प्रधान शामिल थे, लिहाजा यह संदेश गया कि बार एसोसिएशन 35ए का समर्थन कर रही है। कश्मीर में पूर्व नौकरशाह शाह फैजल समेत अन्य ने कुछ वकीलों की राय को जम्मू बार एसोसिएशन की राय बताकर इसका स्वागत भी किया। इससे बार एसोसिएशन की छवि को ठेस पहुंची हैं।

शर्मा ने कहा कि बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सीनियर एडवोकेट बीएस सलाथिया की अध्यक्षता में हुई जनरल हाउस की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जम्मू बार 35ए को हटाने की मांग करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जारी केस में बार का पक्ष सुनने की अपील लेकर आवेदन भी देगी।

जनरल हाउस का फैसला बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि सुबह हुई कार्यकारी कमेटी की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बार के किसी भी सदस्य को 35ए या अन्य किसी मुद्दे पर बयान देने का अधिकार नहीं होगा। आधिकारिक तौर पर केवल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ही कोई बयान जारी कर सकते हैं।

उन्नाव मामले में छात्रा ने सवाल किया तो निरुत्तर हो गए पुलिस अफसर

जागरण संवाददाता, बाराबंकी : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बालिका सुरक्षा जागरूकता के दौरान एक छात्रा ने जब उन्नाव मामले को लेकर पुलिस से सवाल किया तो उनसे जवाब देते नहीं बना। बस इतना ही कहा कि जांच चल रही है। अपने सवाल से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करने वाली छात्रा का वीडियो सोशल साइट पर खूब वायरल हो रहा है। लोग टिप्पणियों के जरिए उसके सवाल और साहस की सराहना भी कर रहे हैं। बाराबंकी में एक माह से चल रहे बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के समापन पर बुधवार को एक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

यह था सवाल : 11 वीं की छात्रा मुनीबा किदवई ने प्रश्न में पूछा कि हमे अपराध का विरोध जरूर करना चाहिए पर टोल फ्री नंबरों पर विरोध सूचना देने के बाद वह सुरक्षित रहेगी इसकी क्या गारंटी? उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता को रायबरेली में जान से मारने की कोशिश की गई। उसका कहना था कि अगर विपक्षी कोई बड़ा आदमी है तो कोई कैसे सुरक्षित रहेगा? पहले तो एएसपी आरएस गौतम चुप हो गए। फिर कहा उस कांड में अभी जांच चल रही है।

जज्बा

दुश्मन के साथ मौसम की चुनौतियों का भी सामना कर रही बीएसएफ, सुरक्षाबल की 18 चौकियों पर बाढ़ का खतरा बना, जवान मोर्चे पर डटे

बाढ़ भी नहीं डिगा पाती सीमा प्रहरियों का बुलंद हौसला

विवेक सिंह, जम्मू

सर्दियों में कोहरा हो या गर्मियों में कड़ाके की धूप या बरसात में बाढ़। सीमा प्रहरी दुश्मन के साथ मौसम की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए डटे रहते हैं। इन दिनों बरसात में भारी बारिश के कारण सीमांत क्षेत्रों में बहने वाले नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। सांबा व जम्मू में बसंतर, निक्की तवी व चिनाब दरिया से सटे इलाकों में सीमा सुरक्षाबल की करीब 18 चौकियों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

जम्मू संभाग में कठुआ से लेकर अखनूर तक 202 किलामीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) है। इसमें अखनूर में चिनाब के पार 10 किलोमीटर आइबी सेना के पास है। बाढ़ जैसे हालात का सामना करने में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी दक्ष हैं। चार फीट तक चौकियों के पानी में डूबने तक सीमा प्रहरी वहां बने रहते हैं। ऐसे हालात में भी चिनाब नदी में सीमा प्रहरी वाटर पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अगर बाढ़ ज्यादा भयंकर रूप लेती है तो भी सीमा प्रहरी पीछे नहीं हटते। वर्ष 2014 की विनाशकारी बाढ़ में फंसे कई जवान पेड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गए थे। बाद में सीमा प्रहरियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया था।

राज्य में बीएसएफ के फील्ड कमांडरों को विशेष हिदायतें दी हैं कि अग्रिम इलाकों के निरंतर दौरे कर बरसात के मौसम में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत बनाएं। जम्मू क्षेत्र में चार अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में अग्रिम चौकियों में तैनात जवानों को हर समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अक्सर दुश्मन खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है।

ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि सीमा पार सक्रिय आतंकी घुसपैठ करने के लिए मौका तलाश रहे हैं। हाल ही पाक से हुई सक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग में भी सीमा सुरक्षा बल ने यह मुद्दा उठाया था। ऐसे हालात में कठुआ की पहाड़पुर से अखनूर के परगवाल तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नदी, नालों से लगती सीमा की सुरक्षा का नए सिरे से आकलन किया जा रहा है। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई तारबंदी की मरम्मत करने के लिए भी कार्रवाई जारी है। सीमा पर यहां तारबंदी को नुकसान हुआ है, वहां तुरंत कंटीले तार बिछाई जा रही है।

श्रीनगर में गुरुवार को मूसलधार बारिश से सड़कों के साथ सुरक्षा चौकी जलमग्न हो गई। यहां तैनात जवान पानी में खड़े होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते नजर आए। प्रेट्र

-आइजी एनएस जम्वाल, सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बवाल, दो छात्र नेता भेजे जेल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में गुरुवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। वहां खूब तोड़फोड़ की और कुलपति को घेर लिया। इसके बाद विवि के इतिहास में पहली बार पुलिस प्रशासनिक भवन तक पहुंची और छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

दो को जेल भेज दिया। उन पर शांतिभंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। जेल भेजे छात्र नेताओं में छात्रसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सुफियान व पूर्व सचिव हुजैफा आमिर शामिल हैं। इंतजामिया ने भी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 10 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इससे कैंपस में तनाव बढ़ गया है। विवि कैंपस के बाहर आरएएफ और पीएसी के साथ कई थानों की पुलिस तैनात की गई है।

एएमयू प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक छात्र नेता को निष्कासित और दो को निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में कुछ छात्र विवि के चुंगी गेट को शांतिभंग के आरोप में छात्र नेताओं को जेल भेजा है। कैंपस में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस के साथ आरएएफ व पीएसी तैनात है।

-आकाश कुलहरि, एसएसपी

तभी से बंद किए हुए थे। छात्र नेताओं ने गुरुवार सुबह दम दिखाने का फैसला लिया। विवि के मिंटो सर्किल स्कूल के छात्रों को साथ लेकर प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया। गुस्साए छात्रों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे व खिड़कियों के कांच तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों की नाम पटिट्काओं को उखाड़ दिया। उपद्रवी छात्र वहां घंटों हंगामा काटते रहे। हालात बेकाबू होते दिखे तो आखिर पुलिस बुला ली गई।

कुलपति की गाड़ी को घेरा : हंगामे के दौरान कार्यालय से आवास जा रहे कुलपति की गाड़ी को छात्रों ने घेर लिया। छात्र उनसे बात करने की जिद कर रहे थे लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश की। इस बीच पुलिस आई, तब कुलपति जा सके।

अगस्त और सितंबर माह में मानसून के सामान्य रहने की संभावना : मौसम विभाग

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को चार माह के मानसूनी मौसम के आखिरी दो महीनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक, अगस्त-सितंबर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है।

विभाग के अनुसार, अगस्त-सितंबर के दौरान देशभर में बारिश दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 100 फीसद होने की संभावना है। हालांकि इसमें आठ फीसद की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ अगस्त महीने में बारिश की बात करें तो यह एलपीए का 99 फीसद होने की संभावना है। इसमें भी नौ फीसद की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। 1961-2010 की अवधि के आधार पर अगस्त-सितंबर में देशभर में बारिश का एलपीए 42.83 सेंटीमीटर है। मालूम हो कि अप्रैल में मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य मानसून का अनुमान व्यक्त किया था। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने गुरुवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र निर्मित होने की वजह से अगले दो हफ्तों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

गुजरात के वडोदरा में मूसलधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह है कि लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ (नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स) की टीम को उतारना पड़ा है। एएफपी

महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी : मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में गुरुवार से लगातार तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है।

गुजरात के वडोदरा शहर में घुसा नदी का पानी, मगरमच्छ भी घुसे : अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो : मध्य गुजरात में भारी बरसात के चलते विश्वामित्री नदी का पानी वडोदरा शहर में घुस आया और शहर टापू बन गया। नदी से कई मगरमच्छ भी शहर में घुस गए। वन विभाग की टीमों ने अब तक तीन मगरमच्छों को पकड़ा है। वहीं, दीवार गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और करीब पांच हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। बीते 24 घंटे में वडोदरा में 20 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। इसके चलते शहर का हवाई, रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार देर रात उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया। वडोदरा और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की चार-चार टीमें, सेना व एसआरपी की दो-दो टीमों के अलावा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी कार्यरत हैं। इसके अलावा सूरत से भी फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई हैं। पुणे से एनडीआरएफ की पांच टीमें एयरलिफ्ट की जाएंगी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव मुकेश पुरी ने बताया कि करीब 1500 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को क्लोरीन और ओआरएस का वितरण कर रहा है।

वडोदरा में पिछले तीन दशक की रिकॉर्ड बारिश : मौसम विभाग के निदेशक जयंत सरकार ने बताया कि बीते तीन दशक में वडोदरा में यह रिकॉर्ड वर्षा है। उन्होंने बताया कि गुजरात के कई शहरों में आगामी तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका है।

गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को मूसलधार बारिश के बाद एयरपोर्ट का एक दृश्य। यहां 24 घंटे में 500 मिमी बारिश हुई है। प्रेट्र

न्यूज गैलरी

झारखंड के दुमका में चोर को भीड़ ने पीटकर मार डाला

दुमका : झारखंड में लोग कानून को हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। दुमका जिले के जरमुंडी से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल चिहुंटिया गांव में बुधवार रात ग्रामीणों ने एक चोर को पीट-पीट कर मार डाला। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीण बलिराम मरांडी ने बताया कि चिहुंटिया निवासी ओलोन लाल मरांडी के घर बीती रात करीब एक बजे चार चोर सेंधमारी कर रहे थे। तभी घर पर सो रहे ओलोन की नींद खुल गई। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक को धर दबोचा, जबकि तीन भाग निकले। गुस्साई भीड़ ने चोर को पीट-पीट कर मार डाला। उसकी पहचान भोला हाजरा के रूप में हुई। उसके खिलाफ झारखंड के अलावा पंजाब व बंगाल में चोरी-डकैती के मामले दर्ज हैं। (जासं)

रामपुर में मालगाड़ी के चार डिब्बे बेपटरी , पांच घंटे मार्ग बाधित

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर में गार्ड की बोगी समेत मालगाड़ी के चार डिब्बे गुरुवार सुबह साढ़े पांच बजे नगरिया और मिलक रेलवे स्टेशन के बीच में बेपटरी हो गए। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि पटरी चटकने के चलते यह हादसा हुआ है। इसकी तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। दुर्घटना के बाद दिल्ली से लखनऊ रेल मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। पांच घंटे बाद 10 .50 बजे नई दिल्ली से लखनऊ रेल मार्ग सुचारू हो सका। दुर्घटना राहत ट्रेन और मुरादाबाद डिवीजन से पहुंची टीम ने डिब्बों को ट्रैक पर चढ़ाया। (जासं)

श्रीजगन्नाथ मंदिर में गुटखा खाकर प्रवेश पर रोक लागू

पुरी : ओडिशा के पुरी में स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के अंदर गुटखा खाकर प्रवेश पर रोक गुरुवार से प्रभावी हो गई है। यह नियम भक्तों से लेकर श्रीमंदिर के सेवक, प्रशासनिक अधिकारी सभी पर लागू होगा। इस नियम का उल्लंघन करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति, सेवक या फिर प्रशासनिक अधिकारी पाया जाता है तो उससे 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। (जासं)

जुए में हारा पत्नी, दोस्तों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक जुआरी व शराबी पति अपनी पत्नी को भी जुएं में हार गया। इसके बाद जुआरी दोस्तों ने पत्नी संग सामूहिक दुष्कर्म किया। एसीजेएम (पंचम) के आदेश पर पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता के मुताबिक उसके पति के मित्र अरुण व रिश्तेदार अनिल घर आते थे। जुए और शराब का दौर चलता था। एक दिन जुए में पति ने उसे ही दांव पर लगा दिया, जिस पर अरुण और अनिल ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वह मायके चली आई। नौ दिसंबर 2018 को पति ने माफी मांगी। इस पर वह उसके साथ ससुराल को रवाना हो गई। रास्ते में पति ने अरुण व अनिल को बुला लिया। दोनों ने फिर दुष्कर्म किया। (जासं)

बड़ा मामला ▶ सम्भल में सपाइयों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, जुलूस निकाला

आजम के समर्थन में उतरे सपाई, प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने दी गिरफ्तारी, बिना मुचलका छोड़े गए

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

गुरुवार को रामपुर सियासत का अखाड़ा बन गया। सांसद आजम खां के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई के अलावा बुधवार को विधायक अब्दुला की हुई गिरफ्तारी के विरोध में सपाई सड़कों पर उतर आए। सांसद, विधायकों समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह गिरफ्तारी दी। रामपुर, सम्भल, अमरोहा में हंगामे के बीच सैकड़ों सपाइयों को हिरासत में लेकर जिलों की पुलिस लाइन लाया गया। बाद में सभी को बिना मुचलका के छोड़ दिया गया।

सपाइयों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार सुबह से ही रामपुर की सीमाएं सील कर दी गईं थीं। वाहनों को चेकिंग के बाद निकलने दिया गया। मुरादाबाद में रामपुर सीमा के क्षेत्र मूंढापांडे पर अवरोध लगाकर वाहनों को रोक दिया गया। यहां बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, मुरादाबाद से सांसद डॉ. एसटी हसन, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, सम्भल की असमौली विधायक पिंकी यादव को हिरासत में लिया गया। रामपुर में सुबह से ही सांसद आजम खां के आवास पर सपाई एकत्रित रहे। दोपहर में आजम के विधायक पुत्र अब्दुल्ला को रोके जाने के बावजूद जुलूस निकाला और जिला कारागार के पास सपाइयों ने धरना दिया। यहां से सभी को गिरफ्तारी कर लिया गया। दो घंटे बाद उनको समर्थकों के साथ छोड़ दिया गया। अमरोहा में पूर्व मंत्री एवं विधायक इकबाल महमूद के घर पर सपाई जुटे। वहां से जुलूस निकला तो पुलिस ने रोक लिया। विधायक को गिरफ्तार कर ले जाया गया। सम्भल में सपाइयों ने प्रदेश सरकार की खिलाफत करते हुए नारेबाजी की। सरकार का पुतला दहन किया। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सपाइयों का उत्पीड़न हो रहा है। मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है।

रामपुर जाने वाले मार्गों को रोकने के चलते दो घंटे तक बरेली हाईवे बाधित रहा। वाहनों की लंबी लाइन लग गईं। लोग गर्मी में अकुला गए। कुछ देर बाद सपाइयों को रिहा कर दिया गया। बिजनौर में 125 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

मुरादाबाद में रामपुर जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाती पुलिस। जागरण

ईडी ने आजम खां के खिलाफ दर्ज किया केस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम खां के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ईडी जल्द आजम की संपत्ति की जांच कर अपना शिकंजा कसेगा। बताया गया कि ईडी ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज कराये गये 26 मुकदमों को अपने केस का आधार बनाया है।

बीते दिनों ईडी ने डीएम रामपुर से पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ दर्ज कराये गये मुकदमों का ब्योरा मांगा था। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद आजम पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आजम खां पर ग्राम आलियागंज के 26 किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा करके उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लेने का आरोप है। रामपुर के थाना अजीमनगर में इसका मुकदमा दर्ज है। जौहर यूनिवर्सिटी में किया गया अरबों रुपये का निवेश भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकता है। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बड़ी रकम चंदे के रूप में भी ली गई थी।

बिहार में मां से बदला लेने के लिए स्कूल में घुसकर छात्र की हत्या

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में घुसकर बदमाशों ने गुरुवार को सातवीं के एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। छात्र सूरज की मां के साथ बुधवार को छिनतई हुई थी। सुमन देवी के साथ मारपीट कर बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया था। उन्होंने बदमाशों की पहचान कर ली थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से कुछ समय बाद दो बदमाश पकड़े गए। उनकी जमकर धुनाई कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के कहने पर एक बदमाश छूट गया। दूसरे आरोपित मुन्ना को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। मामला दर्ज हुआ और उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई। माना जा रहा है कि प्रतिशोध में मुन्ना के साथी विकास समेत अन्य ने स्कूल में सूरज की हत्या कर दी। घटना के लिए परिजन स्कूल के शिक्षक को भी दोषी बता रहे।

अहियापुर थाना क्षेत्र के बाड़ा जगन्नाथ स्थित सरकारी स्कूल में घटना गुरुवार दोपहर की है। विजय राम का पुत्र सूरज कुमार (12) भाई बादल के साथ स्कूल गया था। दोपहर करीब एक बजे मध्यांतर (टिफिन) हुआ। तीन बदमाश स्कूल के निकट पहुंचे। इसमें से एक ने शिक्षक के सामने से सूरज को खींच लिया और ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। जब तक शिक्षक कुछ समझते, सभी बदमाश भाग निकले। घटना के बाद शिक्षक सूरज को बाइक से लेकर एसकेएमसीएच पहुंचे। यहां आने के साथ ही चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अहियापुर में छात्र की हत्या के बाद बदहवास परिजन। जागरण

परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। कानून हाथ में लेकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करनेवालों पर भी कार्रवाई होगी।

- मनोज कुमार, एसएसपी

अधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई।

लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला: हत्या के विरोध में उग्र लोगों ने जमकर बवाल काटा। हाईवे जाम कर आगजनी की। स्कूल के फर्नीचर को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। एक शिक्षक की बाइक भी फूंक दी। मध्याह्न भोजन के अनाज, रजिस्टर व अन्य कागजात को भी जला दिया। पुलिस पदाधिकारियों को भी उग्र लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा।

पाकिस्तान के नागरिक की है शत्रु संपत्ति

जागरण संवाददाता, रामपुर : सांसद आजम खां पर जिस शत्रु संपत्ति को कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है, वह पाक नागरिक इमामुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी की है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों में यहां सींगनखेड़ा में रहने वाले इमामुद्दीन का भी परिवार था।

उनकी संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। आरोप है कि सांसद ने वक्फ मुतवल्ली मसूद खां से साठगांठ कर इसी शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया है। इस संबंध में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने तीन जुलाई को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से शत्रु संपत्ति के वक्फ में होने और उसके मुतवल्ली से संबंधित जानकारी आरटीआइ से मांगी थी। भाजपा नेता का कहना था कि सांसद और मसूद अली खां ने उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सरकारी कागजात में हेराफेरी करके शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर लिया है।

गृहमंत्री ने कार्रवाई का दिया था आश्वासन : पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने गृहमंत्री अमित शाह से शिकायत की थी, जिसपर गृहमंत्री ने उन्हें पत्र भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

रामपुर में दंगा कराना चाहते हैं अखिलेश : जयाप्रदा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

उप्र के रामपुर की पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव गलत कार्य करने वाले आजम का खां का समर्थन कर रहे हैं। अब वह मुख्यमंत्री तो हैं नहीं, फिर भी सपा कार्यकर्ताओं को रामपुर में एकत्रित कर वहां दंगा कराना चाहते हैं। भाजपा नेता जयाप्रदा मुरादाबाद पंचायत भवन में महाराजा अग्रसेन संगठन महिला प्रकोष्ठ के तीजोत्सव में हिस्सा लेने आई थीं। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा, कानून अपना कार्य कर रहा है। इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

आजम खां का वीडियो वायरल : सांसद आजम खां का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें कह रहे हैं कि उप चुनाव से लोगों को हटाने के लिए दहशत फैलाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के साढ़े तीन हजार बच्चों का भविष्य दांव पर है। मैं आरटीआइ से जानना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जमीनों की रजिस्ट्री कहां हैं। सर सैयद अहमद खां और मदन मोहन मालवीय को भी मरणोपरांत भू माफिया का खिताब दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मान लिया कि किताबें चोरी की हैं तो मुझ पर मुकदमा करते। दहशत फैला दी। अस्पताल का सामान लूट लिया। मेरे 300 साल पुराने कुरआन ले गए। 250 साल पुरानी महाभारत ले गए।

लखनऊ आकर तीन साल कम हो गई थी अब्दुल्ला की उम्र

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आजम खां के विधायक बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के जन्म प्रमाणपत्र मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। रामपुर के साथ ही लखनऊ में भी उनका जन्म क्वीनमेरी हॉस्पिटल में हुआ था। यहां आकर उनकी उम्र तीन साल कम हो गई थी। तीस सितंबर 1990 में उनका जन्म लखनऊ के क्वीनमेरी हॉस्पिटल में होना दिखाया गया था। इसके बाद क्वीनमेरी हॉस्पिटल ने नौ जनवरी 2015 को उनका डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसी आधार पर लखनऊ नगर निगम ने भी अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र बना दिया। अब्दुल्ला के जन्म-प्रमाण पत्र बनाने को लेकर चल रही पड़ताल में यह तथ्य सामने आए हैं।

रिश्वत न मिली तो लेखपाल ने विधवा का पांच करोड़ का आय प्रमाणपत्र बना दिया

अंबिका मिश्र, अयोध्या : भ्रष्ट तंत्र की चौखट पर गरीब के सपने का मजाक उड़ाते हुए उप्र के अयोध्या में एक लेखपाल ने विधवा तारा देवी को करोड़पति बना दिया। गरीबी से लड़ रही यह विधवा बेटे को छात्रवृत्ति दिलाना चाहती थी। इसी आस में आय प्रमाणपत्र बनवाने तहसील पहुंचीं। दौड़भाग के बाद छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख 30 जुलाई को आय प्रमाणपत्र भी जारी तो हुआ, लेकिन लेखपाल ने उसकी आय पांच करोड़ सालाना लिख दी। अब विधवा इंसाफ के लिए भटक रही हैं। सुनवाई न होने पर सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उसने लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

मानापुर निवासी अमित ने छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाणपत्र का आवेदन किया था। उसकी मां तारादेवी का आरोप है कि आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल ने रिश्वत की मांगी। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, जो मांग पूरा कर पातीं। रिश्वत न मिलने पर लेखपाल ने मनमानी रिपोर्ट लगा दी। उन्होंने उनका आय प्रमाणपत्र में मासिक आय 43 लाख 33 हजार 766 रुपये और वार्षिक आय पांच करोड़ 20 लाख पांच हजार दो सौ रुपये दिखा दी। जबकि हकीकत में तारा देवी के पास मामूली खेती है।

तीन समितियों की पत्रावली गायब होने की आशंका

सोनभद्र नरसंहार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

उभ्भा गांव नरसंहार के बाद जिले की तमाम कृषि समितियों की भी जांच शुरू हो गई है। इस जांच में कई अहम सुराग मिल रहे हैं। इन समितियों में खामियां भी मिलने की बात सामने आ रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि तीन समितियां ऐसी हैं जहां की पत्रावली ही जिले से गायब होने की आशंका है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि करने से अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। सहकारिता विभाग के लोग पत्रावली मंडलीय कार्यालय मीरजापुर से मंगवाने व वहां पता कराने में पड़ गए हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि जिस जमीन को लेकर इतना बड़ा नरसंहार हुआ वह जमीन कभी आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम रही। ऐसी स्थिति में मंडलायुक्त ने जिले की अन्य कृषि समितियों की भी जांच कराने के लिए निर्देश दिए। उसी के अनुसार समितियों की जांच भी शुरू कर दी गई है। जिले में कुल 13 समितियां हैं। इनकी जांच में अभी तक 10 समितियों की रिपोर्ट आ चुकी है। तीन समितियों की पत्रावली अभी मिली नहीं है। बताया जा रहा है कि जिले में इनकी पत्रावली है ही नहीं। अगर पत्रावली नहीं मिली तो समितियों से संबंधित जानकारी मिलना मुश्किल होगा। हालांकि, विभागीय लोग मानते हैं कि वहां के भू-अभिलेख से जमीन का पता चल सकता है।

सैकड़ों फोन पुलिस के रडार पर: उभ्भा गांव नरसंहार में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अज्ञात आरोपितों व संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सैकड़ों लोगों का नंबर सर्विलांस पर लगाकर उनकी काल डिटेल निकाल रही है। उसी के आधार पर आरोपितों को चिह्नित कर पुलिस उनके घर छापेमारी करने में जुटी है। गुरुवार को पुलिस ने मध्यप्रदेश व बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की।

तीन आरोपित गिरफ्तार: नरसंहार के तीन और आरोपितों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। अब जेल जाने वालों की कुल संख्या 55 हो गई। मामले में पुलिस ने 28 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीओ डा. केजी सिंह ने बताया की तीन आरोपित इंद्रमणि, चंद्रमणि व भूषण को गिरफ्तार किया गया है।

कसा शिकंजा

एफएसएसएआइ ने आइआइटीआर के सहयोग से ऐसे खाद्य उत्पादों के लिए बनाया 'गाइडेंस डॉक्यूमेंट', वैज्ञानिक मानकों पर खरा उतरने के बाद ही अब कोई डिजाइनर फूड बाजार में उतारा जा सकेगा

सेहत की कसौटी पर डिजाइनर फूड का स्वाद

रूमा सिन्हा, लखनऊ

सेहत के लिए फायदेमंद बताकर अब फोर्टीफाइड फूड यानी डिजाइनर फूड का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के खाद्य पदार्थ को बाजार में आने से पहले सुरक्षा की कसौटी पर कसा जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आइआइटीआर) के सहयोग से ऐसे खाद्य उत्पादों के लिए 'गाइडेंस डॉक्यूमेंट' तैयार किया है। इसमें सुझाए मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई डिजाइनर फूड बाजार में आ सकेगा।

एफएसएसएआइ की मंशा है कि किसी फूड में प्रयोग किए जाने वाले नोवेल तत्व की सुरक्षा का परीक्षण जरूरी है, जिससे इसके इस्तेमाल से किसी तरह के नुकसान की गुंजाइश न बचे। आइआइटीआर के वैज्ञानिक डॉ.एसपी सिंह कहते हैं कि डिजाइनर या नोवेल फूड का मतलब है कि उसे तैयार करने में किसी नई टेक्नोलॉजी या नए पदार्थ का प्रयोग किया गया हो। इसे उक्त प्रोडक्ट की गुणवत्ता या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कितने सुरक्षित हैं, इसे परखा नहीं जाता है। एफएसएसएआइ का फोकस इन खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता के साथ यह भी परखना है कि इनका सेवन कितना सुरक्षित है।

डिजाइनर फूड से लोगों की सेहत पर पड़ा है बुरा असर। प्रतीकात्मक

देश-विदेश में डिजायनर फूड बाजार में उतारने की होड़ लगी है। अब देश में इस तरह के किसी उत्पाद और उसे तैयार करने की विधि को वैज्ञानिक परीक्षण की कसौटी से गुजरना होगा। डिजाइनर फूड सेवन के लिए सुरक्षित पाए जाने के बाद ही बाजार में लाया जा सकेगा।

प्रो. आलोक धावन, निदेशक सीएसआइआर-आइआइटीआर

पिछले वर्ष भोपाल से आई थी शिकायत : जूस, आटा, नमक, मिल्क आदि को अतिरिक्त विटामिन, मिनरल का प्रयोग कर फोर्टीफाइड किया जाता है। निर्माता कई बार इनमें कुछ ऐसी नई चीजों का प्रयोग करते हैं जिसका पहले कभी उस रूप में प्रयोग नहीं किया गया हो। जैसे मछली के तेल के स्थान पर क्रिल ऑयल। सेब का सिरका या जूस तैयार करने के लिए अल्ट्रा वॉयलेट किरणों का प्रयोग भी ऐसा ही है। पिछले वर्ष भोपाल में इसी तरह फोर्टीफाइड नमक से लोगों की तबीयत बिगड़ने और खाना खराब होने की खबरें आईं थीं।

गुजरात में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या में फांसी की सजा

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- सूरत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात महीने की सुनवाई में सुनाई सजा
- बिहार के बक्सर जिला निवासी अनिल यादव ने की थी वारदात
- जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'ऐसा तो जानवर भी नहीं करते'

गुजरात के सूरत में सात माह पहले अपहरण के बाद एक मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने बिहार के बक्सर जिला निवासी अनिल यादव को फांसी की सजा सुनाई है। जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'ऐसा तो जानवर भी नहीं करते।'

सूरत के लिंबायत घोडादरा निवासी पौने चार साल की मासूम को 14 अक्टूबर 2018 को उसके पड़ोस में रहने वाला अनिल यादव बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और किसी को पता न चले इसके चलते उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया।

पुलिस ने जांच के दौरान मिली सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर बिहार के बक्सर जिला निवासी अनिल यादव की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान बुधवार को सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने मामले को दुर्लभतम बताते हुए कहा कि अनिल आदतन अपराधी है। इस मामले में उसे किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। इस कृत्य के बाद अपराधी में सुधार की कोई गुंजाइश देखना पीड़िता के साथ अन्याय होगा व समाज को भी गलत संदेश जाएगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पीएस काला ने बुधवार देर शाम फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा कृत्य तो जानवर भी नहीं करते हैं। ऐसे अपराधी को किसी भी तरह की रियायत नहीं प्रदान की जा सकती। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

जाट आरक्षण आंदोलन के मामले में छात्र नेता समेत पांच आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, रोहतक : जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाइके बहल की कोर्ट ने छात्र नेता समेत पांच आरोपितों राहुल दादू, जगपाल, छात्र नेता जोगेंद्र उर्फ जोगा, डा. नरेंद्र बल्हारा और दिलावर को बरी कर दिया है। पांचों पर पक्ष पर आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपितों को संदेह का लाभ दिया।

फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा हो गई थी। 19 फरवरी को एग्रो मॉल के सामने जमा भीड़ ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर दिया था। अधिकारी बचाव के लिए एग्रो मॉल में घुस गए थे। भीड़ ने उन्हें वहां बंधक बनाने के साथ पुलिस की गाड़ी फूंक दी थी।

हिंसा के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी भी जला दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर रखा था। पांच माह बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि एग्रो मॉल के सामने हुई घटना में भी पांचों आरोपित शामिल हैं।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

प्रत्येक समस्या अपना समाधान लेकर ही उत्पन्न होती है

मंदी का अंदेशा

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से विकास दर का अनुमान घटाने पर हैरानी इसलिए नहीं, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सब कुछ ठीक नहीं। बात चाहे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में चार वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज होने की हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी के हालात की अथवा शेयर बाजार में छाई सुस्ती की, चारों ओर से उभरते विपरीत संकेत कारोबार जगत को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इन नकारात्मक संकेतों के बीच मोदी सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या ने भी आर्थिक माहौल में निराशा घोलने का काम किया है। भले ही सिद्धार्थ की आत्महत्या के मूल कारण कुछ और हों, लेकिन उनकी मौत को जिस तरह प्रतिकूल कारोबारी माहौल से जोड़ा जा रहा है उससे नीति-नियंता अनजान नहीं हो सकते। नीति-नियंताओं को इस बात से भी अवगत होना चाहिए कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट उद्योग-व्यापार जगत को उत्साह प्रदान करने में सहायक नहीं साबित हुआ। सच तो यह है कि आम बजट के कुछ प्रावधानों ने कारोबार जगत को हतोत्साहित करने का काम किया है।

इससे इन्कार नहीं कि सरकार के विभिन्न विभाग कारोबारी माहौल ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कारोबार जगत की चिंताओं का समाधान करने की पहल सरकार के शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं हो रही है? क्या यह सही समय नहीं कि वित्त मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री आगे आकर उद्योग-व्यापार जगत को इसके लिए आश्वस्त करें कि उसकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा? इस तरह का कोई आश्वासन देना इसलिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि उद्योग-व्यापार को गति प्रदान करके ही सरकार जनकल्याण और विकास की अपनी योजनाओं पर अमल कर पाएगी। निःसंदेह गरीब, किसान और अन्य वंचित तबकों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन इस तरह की प्राथमिकताएं तो तभी पूरी हो पाएंगी जब अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने में कामयाबी मिलेगी। यह कामयाबी कारोबारियों को भरोसा दिलाने और उनके मनोबल को बढ़ाने से ही मिलेगी। यह शुभ संकेत नहीं कि अर्थव्यवस्था के मंदी के चपेट में आने का अंदेशा उभर आया है। इसके पहले कि मंदी की आशंका और गहराए, मोदी सरकार को हालात ठीक करने के लिए न केवल सक्रिय होना चाहिए, बल्कि इसकी चिंता करते हुए दिखना भी चाहिए कि कारोबार जगत की समस्याओं का तेजी से निदान करना उसकी प्राथमिकता में है।

ममता की कोशिश

तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने तृणमूल से 14 सीटें छीन ली है उसके बाद से तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ना लाजिमी है। इसीलिए उन्होंने पहली बार भाजपा एवं अन्य दलों की तरह चुनावी रणनीतिकार का सहारा लिया है। उनकी चुनावी रणनीति इन दिनों प्रशांत किशोर संभाल रहे हैं और उनकी रणनीति के तहत ममता ने भी कोशिश शुरू कर दी है। राज्य की जनता में तृणमूल के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए 'दीदी के बोलो' अभियान शुरू किया गया है। तृणमूल नेतृत्व और किशोर की 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आइ-पीएसी) के अधिकारियों ने हालांकि फोन पर हुई बातचीत या किन लोगों ने फोन किया, इस संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की, परंतु बुधवार को बताया गया कि सोमवार को डिजिटल मंच के शुरू होने के बाद से अब तक इस पर दो लाख से अधिक फोन कॉल आ चुके हैं। वहीं कम से कम एक लाख लोगों ने हेल्पलाइन नंबर तथा वेबसाइट पर अपनी राय रखी है और समस्याएं बताई हैं। व्यापक प्रतिक्रिया मिलने की बातें कही जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद ममता ने जनता तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत पार्टी के एक हजार नेता अगले 100 दिनों में 10 हजार गांवों की यात्रा करेंगे और जनता की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। यह अभियान भी प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राज्य में भाजपा की अचानक बढ़ी लोकप्रियता तृणमूल के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वाम दलों के 34 वर्षों के शासन को समाप्त करते हुए 2011 में सुश्री बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य में अपनी सरकार बनाई थी, परंतु पिछले पांच वर्षों में भाजपा की शक्ति बंगाल में काफी बढ़ चुकी है जिसके मद्देनजर उन्होंने अभी से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि पारंपरिक राजनीति के जरिए भाजपा से पार पाना संभव नहीं है। इसीलिए आधुनिक राजनीतिक सोच एवं चुनाव प्रबंधन में माहिर प्रशांत किशोर को साथ लेकर ममता भाजपा को 2021 में जमीन चटाने की कोशिश में हैं।

अपनी अफगान नीति को धार दे भारत

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

काबुल में संभावित तालिबानी शासन इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ सामरिक पैठ बनाने में फायदा ही पहुंचाएगा

अवधेश राजपूत

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कतर एयरलाइंस की व्यावसायिक उड़ान से जब अमेरिका पहुंचे तो उनकी आगवानी के लिए कोई अमेरिकी मंत्री मौजूद नहीं था। उनके वित्त मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी राजदूत के अलावा पाकिस्तान मूल के कुछ अमेरिकियों ने ही उनका स्वागत किया। वहां केवल एक अमेरिकी महिला प्रोटोकॉल अधिकारी ही उपस्थित थीं। उन्हें तब और असहज होना पड़ा जब पाकिस्तान के बलूच, सिंधी और मोहाजिर तबके के लोगों ने उनके सामने विरोध-प्रदर्शन किया। इमरान खान के साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जावेद बाजवा के अलावा ताकतवर खुफिया एजेंसी आइएसआइ के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी गए। ये सभी हवाई अड्डे से मेट्रो रेल के जरिये पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। ये सभी दूतावास में ही रहे। उनके द्वारा बरती गई इस किफायत की कंगाल और बदहाल होते देश में लोगों द्वारा भारी सराहना की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ सेना के दो शीर्ष जनरल भी साथ गए। असल में इमरान अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान से संपर्क साधना चाहते थे और दोनों जनरल अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम कर चुके थे। पाकिस्तानी जनरल अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडरों को यह समझाने में सफल रहे कि अपनी धरती पर आतंक के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान खासा गंभीर है। दूसरी वजह यह रही कि व्हाइट हाउस में अपने सैन्य नेतृत्व की परेड कराकर इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि जो भी वादे किए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के वास्तविक शासकों यानी सैन्य कमांडरों के सामने हो रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप-इमरान खान वार्ता की कड़ी सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जोड़ी थी जिन्होंने इसके लिए ट्रंप के दामाद के साथ अपने निजी रिश्तों का सहारा लिया। इसकी कोशिशें दिसंबर, 2018 से ही शुरू हो गई थीं जब ट्रंप ने इमरान खान को पत्र लिखकर अफगान शांति प्रक्रिया में उनसे मदद मांगी थी। इमरान खान भी ट्रंप से मिलने को आतुर थे ताकि पाकिस्तान को लेकर उनकी नकारात्मक धारणा दूर कर सकें। इस्लामाबाद ने इसके लिए हालैंड एंड नाइट जैसी लाबिंग फर्म की सेवाएं ली थीं। कुछ अरसा पहले ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि बीते 15 वर्षों में पाकिस्तान ने 33 अरब डॉलर की मदद के बदले में झूठ और फरेब के बदले कुछ और नहीं दिया। वही ट्रंप अब पाक के साथ संबंधों में सुधार के मकसद से इमरान खान का स्वागत करते दिखे। ट्रंप को उम्मीद है कि इमरान खान तालिबान से समझौता कराने में मददगार होंगे ताकि नवंबर, 2020 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी सैनिक स्वदेश लौट आएं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अपने चिरपरिचित अंदाज में शिगूफा छेड़ा कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता का अनुरोध किया है। इससे इमरान के मुर्झाए चेहरे पर भी मुस्कान तैरना स्वाभाविक था।

अमेरिका ने इमरान खान से किसी सैन्य या आर्थिक सहायता का वादा नहीं किया है। इस दौरान पाकिस्तान को केवल 16.5 करोड़ डॉलर की राशि मिली वह भी उन एफ-16 विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जो उसे अमेरिका से मिलेंगे। इसमें भी एक शर्त यह है कि उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इमरान खान के अमेरिका दौरे के कुछ खास निहितार्थ भी रहे। एक तो यही कि अमेरिका-पाक रिश्ते वापस सुधार की ओर अग्रसर हुए हैं। दूसरा यही कि भारत अभी भी अमेरिका के लिए अहम बना रहेगा, लेकिन वाशिंगटन इस्लामाबाद से भी संतुलन साधेगा जैसा कि वह पहले करता था। तीसरा यह कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मामले में पाकिस्तान आधार बिंदु बन गया है। ऐसा इस्लामाबाद की संदिग्ध नीति के कारण हुआ है जहां वह तालिबान की मदद करता तो दूसरी ओर उससे लड़ने के नाम पर अमेरिका से डॉलर वसूलता रहा। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पाक की तालिबान पर पूरी पकड़ है। कश्मीर पर ट्रंप की शिगूफेबाजी इमरान के दौरे की सबसे बड़ी थाती रही, लेकिन इससे पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला। कश्मीर के मसले पर अमेरिकी मध्यस्थता की संभावनाओं पर पाकिस्तानी मीडिया गदगद हो गया। ट्रंप के बयान पर भारत में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से निजी स्पष्टीकरण की मांग पर अड़ा, लेकिन मोदी ने बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति को शर्मसार करना उचित नहीं समझा। इसे अमेरिका ने भी समझा होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली बैठक में इमरान खान ने द्विपक्षीय रिश्तों में आए खालीपन को भरने के साथ ही अविश्वास की खाई को पाटने का काम किया। इमरान का अमेरिका दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह तब हुआ जब तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच रही है। दोहा में तालिबान के साथ अगले दौर की वार्ता फिर से होने जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है।

अमेरिका में इमरान खान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी धरती पर करीब 40 आतंकी संगठनों के 40,000 आतंकवादी सक्रिय हैं जिन पर कार्रवाई करनी होगी। हालांकि इमरान खान के पूर्ववर्तियों ने भी ऐसे दावों के साथ पहले भी अमेरिका को गुमराह किया है और इस मामले में वक्त उनकी भी परीक्षा लेगा। इमरान खान ने अमेरिका में यह भी कहा कि वह तालिबान से मिलकर उसे अफगान सरकार से बातचीत के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर तालिबान के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान आमंत्रित करता है तो हम वहां जरूर जाएंगे।

भारत को भी अपनी अफगानिस्तान नीति में बदलाव करते हुए तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। कूटनीतिक तकाजा यही कहता है कि व्यावहारिकता को सिद्धांतों पर तरजीह दी जाए। तालिबान भले ही आतंकी हों, लेकिन वे हैं तो अफगानी ही। मौजूदा अफगान वार्ता में शामिल न होकर भारत ने इस्लामाबाद को बढ़त बनाने का अवसर दे दिया है। अफगान तालिबान के साथ हालिया वार्ता में अमेरिका, रूस और चीन के अलावा पाकिस्तान भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस युद्ध पीड़ित देश में हमने मानव और अन्य संसाधनों में भारी निवेश किया है। भारत को लेकर अफगानियों में सदियों से अच्छी भावनाएं रही हैं। इनमें तालिबान के कुछ धड़े भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से भी ये भावनाएं बढ़ी हैं। काबुल में तालिबानी शासन इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ सामरिक पैठ और कश्मीर में जारी आतंकी संघर्ष में फायदा पहुंचाएगा। तालिबान की दुश्मनी से ज्यादा उसकी दोस्ती दिल्ली के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

नैतिक पतन का शिकार लोकतंत्र

एनके सिंह

अगर नेता, नौकरशाह और यहां तक कि जज भी नैतिकता के निचले पायदान पर दिख रहे हैं तो इससे गंभीर बात और कोई नहीं

देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआइ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है। तमाम जांच-पड़ताल के बाद जज के प्राथमिक तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सुबूत मिले हैं। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नैतिकता की प्रतिमूर्ति मानते हुए उन्हें पद पर रहने के दौरान हर संवैधानिक सुरक्षा कवच से नवाजा था और उन्हें पद से हटाना एक जटिलतम प्रक्रिया यानी महाभियोग के तहत लगभग नामुमकिन कर दिया था। जिस प्रजातंत्र को उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर हासिल किया उसके भावी पतन का शायद उन्हें अंदाजा नहीं था। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरा प्रशासन 'कांवड़ियों' के आगे इतना नतमस्तक हो गया कि एक जिले के एसपी ने एक कांवड़िये का सार्वजानिक रूप से न केवल पैर दबाया, बल्कि उसका वीडियो आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया, ताकि मुख्यमंत्री देख सकें कि उनके आदेश का अमल किस शिद्दत से किया जाता है। एक अन्य जिले में डीएम और एसपी ने उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और मीडिया को उसका वीडियो उपलब्ध कराया।

लौहपुरुष सरदार पटेल को इस 'स्टील फ्रेम' (वह ब्यूरोक्रेसी को फौलादी ढांचा कहते थे) पर इतना भरोसा था कि संविधान के अनुच्छेद-311 में अधिकारियों को दिए गए सुरक्षा कवच के पक्ष में उन्हें कहा था कि यह कवच इसलिए जरूरी है ताकि अधिकारी राजनीतिक आकाओं के सामने तन कर अपनी बात कह सकें और काम कर सकें। आज 70 साल बाद वह फौलादी ढांचा रीढ़विहीन दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव जिले में सत्ताधारी दल का एक विधायक एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में साल भर से जेल में बंद है। कुछ दिन पहले जब परिवार के साथ वह पीड़िता एक गाड़ी में जा रही थी तो गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी। उसके बाद से वह पीड़िता वेंटिलेटर पर है और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं, जबकी उसके दो रिश्तेदार मौके पर ही मर गए। पीड़िता की मां तथा चाचा के आरोप पर और पूरे राज्य में लोगों के जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने विधायक पर हत्या का और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। जाहिर है अगर आरोपी विधायक गवाहों को डराने-धमकाने के अंदेशे में जेल में नहीं रहता तो इन दिनों विधानसभा में कानून बना या बिगाड़ रहा होता।

एक अन्य मामले पर जरा नजर डालें। सिक्किम में जनता ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बहुमत दिया और विधायकों के बहुमत ने, जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, अपने नेता प्रेम सिंह तमांग को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में साल भर जेल की सजा काट चुके थे और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके थे। यहां सवाल है कि आखिर किसका विवेक गलत था, जनता का या विधायकों का? अब मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि कानून में प्रदत्त अधिकारों के तहत वह उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दे। भ्रष्टाचार में चार्जशीट के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव उस समय के कानून (अंतिम अदालत से सजा न मिलने तक अभियुक्त पाक-साफ माना जाता था) के मुताबिक वर्षों तक बिहार में सरकार बनाते रहे और संसद में मंत्री के रूप में कानून बनाते रहे। बिहार की जनता उन्हें वोट भी देती रही। सवाल है कि क्या 70 वर्षों में जनता का विवेक अपने प्रतिनिधियों को लेकर आज भी वही है या अच्छे नैतिक बल वाले लोग राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं? आज जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति आ गई है या फिर सत्ता के असर के चलते राजनीति अपना नैतिक प्रभाव खोती जा रही है?

आजादी के इतने वर्षों प्रजातंत्र के बाद अगर हमारे कुछ न्यायाधीश, जन-प्रतिनिधि और हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा भाग नैतिक पतन के सबसे निचले पायदान पर दिखाई देते हैं तो यह गंभीर चिंता की बात है। यह भी उतनी ही चिंता की बात है जब जनता भ्रष्टाचार की सजा काट रहे नेता वाली पार्टी को बहुमत दिलाकर और सत्ता में लाकर अपना भाग्यविधाता बनाती है और वह संविधान में निष्ठा की शपथ लेकर फिर वही सब कुछ करता है जो कानूनन जुर्म है।

1828 में अमेरिका में जैक्सोनियन युग के प्रजातंत्र की धूम थी। उसे समझने के लिए फ्रांस के राजनीतिक शास्त्र के जाने-माने विद्वान टोक्विल अमेरिका गए और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि यह सबसे खराब प्रजातंत्र है जिसमें अल्पसंख्यक मत का न तो न्यायपालिका में, न ही विधायिका में और न ही किसी और जन विमर्श में कोई स्थान है। उन्होंने वापस लौटकर 'बहुसंख्यक का आतंक' शीर्षक से एक लेख लिखा जो भविष्य के प्रजातंत्र के लिए दिशा-निर्देशक बना। उसी तरह 1860 में ब्रिटेन में भी सबको मतदान का अधिकार संबंधी विवाद पर प्रजातंत्र में उदारवाद के जनक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, 'मैं इसका पक्षधर कभी नहीं हो सकता कि अंगूठाछाप आदमी को मतदान का अधिकार मिले।' इसके विपरीत भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सार्वजानिक व्यस्क मताधिकार के पक्ष में संविधान बनाया, जबकि उस समय साक्षरता मात्र 12 प्रतिशत थी। आज साक्षरता 76 प्रतिशत है, लेकिन क्या इसके साथ लोगों की सोच, तर्क-शक्ति और सामूहिक समझ भी बदली है? क्या बेहतर शिक्षा, प्रति-व्यक्ति आय, सूचना के प्रवाह ने भारत के नागरिकों की नैतिक गुणवत्ता बदली है? अगर हां, तो जज भ्रष्टाचार का आरोपी क्यों है, विधायक दुष्कर्म और हत्या के आरोप के बाद भी अपनी पार्टी का सदस्य क्यों है? कैसे जनता एक साल जेल की सजा काट चुके एक नेता की पार्टी को सरकार बनाने के लिए चुन लेती है और कैसे वह नेता संविधान को ठेंगा दिखाते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है? और अंत में कैसे फैलादी ढांचे की बुनियाद का कोई हिस्सा-आइएएस और आइपीएस रीढ़विहीन हो जाते हैं? शायद प्रजातंत्र में ही कहीं 'नैतिक लोचा' है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का विज्ञान

मन मनुष्य के शरीर का अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, किंतु वह शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन के अंदर संपूर्ण दुनिया समाहित है। मन एक ऐसा पर्दा है जिस पर इच्छाएं प्रक्षेपित होती हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं वे मन के सहयोग से करती हैं। मन के बिना इंद्रियां ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं। अतः मन को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि मन पर काबू पा लिया तो समझो जीवन को साध लिया।

भारतीय शास्त्रों में मन के लिए मनस् शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका अर्थ है वे साधन या उपक्रम जो किसी घटना, विचार या ज्ञान के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह होते हैं। मन का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय और आत्मा को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी है। जिसकी सहायता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन अपने आप में निर्जीव तत्व है। जब मन आत्मा के संसर्ग में आता है तभी इसमें अनुभूति होती है। प्रत्येक आत्मा के साथ एक मन जुड़ा हुआ होता है। जो उसका आंतरिक सहायक माना जाता है। इसलिए आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा गया है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का बाहरी साधन हैं उसी प्रकार मन ज्ञान प्राप्ति का आंतरिक साधन है।

कहावत है-मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अतः जब व्यक्ति अपने मन में यह सोच लेता है कि वह अमुक काम नहीं कर सकता तो वह अपने अंदर नकारात्मक गुण पैदा कर लेता है। और जब व्यक्ति यह सोच लेता है कि वह अमुक काम कर सकता है तो वह अपने अंदर सकारात्मक गुण पैदा कर लेता है। कबीरदास के अनुसार मन मूर्ख है, लोभी है, चंचल और चोर है। यदि मन बेलगाम हो जाए तो यह हमें विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन पर विचारों का प्रभाव होता है। अतः जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा मन भी होगा। मन भूमि में रोपे गए विचार नामक बीज की किस्म ही किसी के बुरे एवं अच्छे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है।

देवेंद्रराज सुथार

फिटनेस पर बढ़ता जोर

अनीश कुमार

एक दशक पहले फिटनेस उत्पादों का घरेलू बाजार चार हजार करोड़ का था, जो अब 14 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है

हाल ही में एक तथ्य सामने आया है कि बीते दस वर्षों में देश में फिटनेस को लेकर जागरूकता काफी बढ़ गई है। इसके चलते फिटनेस उत्पादों का घरेलू बाजार लगभग चार गुणा बढ़ गया है। एक दशक पहले यह चार हजार करोड़ रुपये का था, जो अब 14 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसमें स्वदेशी उत्पादों का हिस्सा छह हजार करोड़ रुपये और चीन से आयतित उत्पादों का हिस्सा आठ हजार करोड़ रुपये है। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर लोगों की सोच में जो बदलाव आया है, ये आंकड़े उसी की झलक पेश कर रहे हैं।

दरअसल आज आधुनिक जीवनशैली और खानपान जनित बीमारियां लोगों की चिंता का एक बड़ा कारण बनती जा रही हैं। हमने आधुनिक जीवनशैली के नाम पर ऐसी आदतों को अपना लिया है जिसने जाने अनजाने कई तरह की गंभीर बीमारियों को हमारे जीवन में जगह दे दी है। जीवन की आपाधापी में हम संतुलित भोजन नहीं ले पा रहे हैं। आहार में शक्कर और वसा की अधिक मात्रा भोजन को हानिकारक बनाती है। ऊपर से सुविधाएं बढ़ने से लोगों की शारीरिक गतिविधियां एकदम कम हो गई हैं जिससे अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होती जा रही है। इन सबके चलते विश्व के सबसे युवा देश भारत में आज बड़ी संख्या में युवक हृदय रोग, मधुमेह, तनाव, गठिया, दमा जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये बीमारियां सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही हैं, इनका विस्तार छोटे शहरों और गांवों तक तेजी से हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक भारत में सबसे अधिक मृत्यु हृदय संबंधी रोगों के कारण होगी। कुछ शोध बताते हैं कि आज की खराब जीवनशैली के कारण अगले करीब एक दशक में भारत की आबादी के लगभग बीस फीसद युवा हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। रहन-सहन में आए इस बदलाव ने महिलाओं एवं पुरुषों के प्रजनन क्षमता को भी काफी प्रभावित किया है। आज करीब 15 फीसद महिलाएं बांझपन की समस्या से ग्रस्त हैं। पुरुषों में गंजे होने और महिलाओं में बाल गिरना भी कहीं न कहीं इसी की देन है। इससे शरीर में जरूरी प्रोटीन, विटामिन और खनिज पोषक तत्वों की कमी पड़ रही है। इसका प्रभाव हमारी उम्र पर भी पड़ रहा है।

युवावस्था न केवल खुद के विकास के लिए अहम होता है, बल्कि यही वह समय होता है जब कोई भी युवा खुद को परिवार, समाज और देश के लिए तैयार करता है। ऐसे में देश की एक बड़ी ऊर्जावान आबादी के स्वास्थ्य में इस तरह की गिरावट का आना निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसलिए जीवनशैली और खानपान की आदतों की वजह से पैदा हो रही बीमारियों पर परिवार, समाज और सरकार के साथ हमें खुद भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि धीरे-धीरे लोग इसके प्रति जागरूक हो भी रहे हैं। और अपने को स्वस्थ रखने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं जिसकी बानगी योग के बढ़ते चलन और फिटनेस उत्पादों की मांग में आई यह बढ़ोतरी है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं)

शिक्षा का माध्यम बनें भारतीय भाषाएं

भारतीय भाषाओं के समक्ष बड़ी चुनौती शीर्षक से शंकर शरण द्वारा लिखित लेख पढ़ा। लेखक ने भाषाओं के संदर्भ में वर्तमान के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। निःसंदेह आज भी ब्रिटिश शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह हावी है और उसको हटाने को लेकर अथवा भारतीय भाषाओं की पुनर्स्थापना को लेकर सारा विमर्श राजनीतिक अधिक हो गया है। निश्चित रूप से लेखक द्वारा उठाया गया यह प्रश्न उचित है कि भाषा निर्जीव यंत्र नहीं है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके अंदर चेतना का स्पंदन भी। यह भाषा ही सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों को संजोती है तथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां प्राथमिक ही नहीं, पूरी शिक्षा वहां की अपनी भाषा में दी जाती है और वे देश आज उच्च शिखरों को छू रहे हैं। फिर कौन-सी बाधा है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पा रहे हैं? आज यह एक गंभीर समस्या है कि हमारे अबोध बालक विदेशी भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान का विकृत विस्तार कर रहे हैं और दादी-नानी के किस्से-कहानियों में छिपे संस्कारों से दूर हो रहे हैं। अंग्रेजी के वर्चस्व से आज हम सब ग्रसित हैं। आवश्यकता है मजबूती से निर्णय लेकर भारतीय भाषाओं में विमर्श की ओर बढ़ा जाए तथा शिक्षा और संस्कार की भाषा भारतीय भाषाएं हों ऐसा प्रयास किया जाए। हिंदी संपर्क की भाषा है, संविधान सम्मत राजभाषा भी है। क्या आज यह अनिवार्य नहीं है कि हम अंग्रेजी को छोड़कर, प्रादेशिक भेदभाव भूलकर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को पुनर्स्थापित करें?

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

मेलबाक्स

डैमेज कंट्रोल की कवायद

उन्नाव दुष्कर्म कांड में चौतरफा आलोचना झेलने के बाद आखिरकार भाजपा ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बैक फुट पर आई भाजपा को ये कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले एक साल में पीड़िता की मां ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को 33 पत्र लिख कर सुरक्षा की मांगी की थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि विधायक के आदमी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साफ है कि विधायक को सत्ता की शक्ति हासिल थी। अब तक पीड़िता के परिवार के कई सदस्य मारे जा चुके हैं। पीड़िता स्वयं अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती करते हुए विधायक से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं। जांच भी उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सीबीआइ को सौंपी जा चुकी है। देर से ही सही, भाजपा ने विधायक को पार्टी से बाहर तो किया, लेकिन ये पार्टी की संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है।

brijesh.srivastava31@yahoo.com

बड़ा सामाजिक बदलाव

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजादी का कहना है कि तीन तलाक विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के बजाय रातों रात सदन की कार्यसूची में डाल कर पारित करा दिया गया। यह हास्यास्पद बयान लगता है। जिसका खंडन भाजपा द्वारा तुरंत किया गया। हालांकि कांग्रेस को समय रहते अपने सदस्यों को व्हिप जारी करना चाहिए था। वैसे भी राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पर सदन में छह घंटे बहस चली। कांग्रेस के वक्तव्य से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के खातिर तीन तलाक विधेयक पास ना करवा कर और कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर प्रवर समिति के पास भेजने की पक्षधर थी। सदन में 20 विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति ने तीन तलाक विधेयक को बिल बना कर इतिहास रचने के साथ बड़े सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है। मुस्लिम महिला विवाह एक्ट का बन जाना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की जड़ों पर जबरदस्त प्रहार है। अब चाह कर भी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध नहीं कर सकतीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की जबरदस्त प्रबंधन कौशल की वजह से मुस्लिम महिला विवाह विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाया गया जो तलाक-ए-बिद्दत पर फौरन नकेल कसेगा, क्योंकि ये आपराधिक श्रेणी का कानून है। मुस्लिम महिला अधिकारों की रक्षा भी करेगा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिएः नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

डॉ. नीलम महेंद्र
सामाजिक मामलों की जानकार

तीन तलाक : आस्था नहीं, अधिकारों की लड़ाई

देश भर में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी सामाजिक समस्या यानी तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव का पारित होना और फिर कानून बन जाना, एक तरीके से मध्यकालीन परंपरा से छुटकारा पाने के समान है। निश्चित तौर पर इससे नारी न्याय और नारी गरिमा की ऐतिहासिक विजय हुई है। देश की मुस्लिम महिलाओं के जीवन तथा उनके परिवार को तहस-नहस करने वाली इस कुप्रथा को समाप्त कर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति को एक बार फिर देश के सामने रखा है। सरकार की प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि देश के आर्थिक विकास के साथ ही नारी सशक्तीकरण का कार्य करने के लिए कुप्रथाओं को खत्म करना आवश्यक है

संसद के दोनों सदनों से तीन तलाक पर रोक लगाने का बिल पारित होना न केवल मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की ऐतिहासिक विजय है, बल्कि कहा जाए तो 30 जुलाई 2019 की तारीख भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक नई सुबह का आगाज भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में ही इसे असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये के चलते इसे एक कानून का रूप लेने के लिए दो साल लंबा इंतजार करना पड़ा है। हालांकि तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं अपनी जंग जीत चुकी हैं, लेकिन अधिकांश देश के अधिकांश विपक्षी दलों का इस बिल के खिलाफ खड़ा होना राजनीतिक रूप से उनके लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

यह वाकई में समझ से परे है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने को तैयार क्यों नहीं है। अपनी वोटबैंक की राजनीति की एकतरफा सोच में विपक्षी दल इतने अंधे हो गए हैं कि वे यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनके इस रवैये से उनका दोहरा आचरण ही देश के सामने आ रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल राम मंदिर और सबरीमाला जैसे मुद्दों पर यह कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उसके फैसले को स्वीकार करने की बातें करते हैं, वो तीन तलाक पर उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं।

दरअसल एक स्त्री के जीवन की नींव को पल भर में हिला देनेवाला तीन तलाक जैसा मुद्दा एक गंभीर मसला है। किसी महिला की हंसती खेलती गृहस्थी को पल भर में उजाड़ दे, उसे संभलने का एक भी मौका दिए बिना उसके सपनों को क्षण भर में रौंद दे, ऐसे मुद्दे पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। न तो यह कोई मजहबी चश्मे से देखने वाला मुद्दा है और न ही राजनीतिक नफा-नुकसान की नजर से। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस मुद्दे पर विपक्ष ओछी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। कारण इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 'तलाक' को नहीं, तलाक के एक अमानवीय तरीके 'तीन तलाक' को ही कानून के दायरे में लाया जा रहा है। जाहिर है इससे पुरुषों का तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं हो रहा, बल्कि समुदाय विशेष की स्त्रियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है, और यही कारण है कि इसे 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' नाम दिया गया।

इतना ही नहीं, इस्लाम में नौ तरीकों से तलाक दिया जा सकता है। तो अगर उसमें से एक तरीका कम कर भी दिया जाए तो तलाक

> किसी महिला की खुशहाल जिंदगी को अचानक बदहाल बना देना एक बड़ी सामाजिक कुप्रथा है जिसका अंत जरूरी है

देने के आठ अन्य तरीके फिर भी शेष हैं, तो इसका इतना विरोध क्यों? खास तौर पर तब, जब कुरान में 'तलाक-ए-बिद्दत' यानी तीन तलाक का स्पष्ट संहिताकरण नहीं किया गया हो, बल्कि उलेमाओं द्वारा इसकी मनमाफिक व्याख्या की जाती रही हो। दरअसल मुल्ला मौलवियों की मिली-भगत से तीन तलाक और फिर उसके बाद हलाला जैसी कुप्रथाओं ने समय के साथ एक ईश्वरीय रूप ले लिया और पाक कुरान के प्रति आस्था के नाम पर मजहबी भय का माहौल बन गया जिससे अज्ञानतावश लोग इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने फैसले में न्यायालय ने भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 'तलाक-ए-बिद्दत' इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को भी रद कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का भी कहना है कि तीन तलाक का किसी मजहब या कुरान से कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मजहबी आस्था के नाम पर तीन तलाक का विरोध साबित करता है कि यह वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यह आस्था नहीं अधिकारों का मामला है।

जैसा कि आम तौर पर बताया जाता है इस्लाम में निकाह दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, लेकिन जब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की रजामंदी जरूरी होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने का फैसला एक अकेला कैसे ले सकता है? जब यह कॉन्ट्रैक्ट यानी निकाह अकेले में नहीं किया जा सकता, और कम से कम दो गवाहों और एक वकील की मौजूदगी जरूरी होती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अंत यानी तलाक अकेले में या वॉट्सएप या फेसबुक पर बिना गवाह और वकील के कैसे जायज हो सकता है? और जो मजहब के नाम पर इसे जायज ठहरा भी रहे हैं, क्या वो यह बताने का कष्ट करेंगे कि दुनिया का कौन सा मजहब आस्था के नाम पर किसी इंसान तो छोड़िए, किसी अन्य जीव के प्रति असंवेदनशील होने की सीख देता है? वैसे भी दुनिया के 20 इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन तथाकथित मुस्लिम नेता और सांसद ओवैसी का कहना है, 'हमें इस्लामिक मुल्कों से मत मिलाइए, नहीं तो कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा।' तो अगर वे वाकई में कट्टरपंथ के खिलाफ हैं तो उन्हें भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ को त्याग कर पूर्ण रूप से भारत के संविधान को ही मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे भारत में कट्टरपंथ की जड़ खत्म हो जाएगी।

सच तो यह है कि ये राजनीतिक दल अगर देशहित की राजनीति कर रहे होते तो जो लड़ाई दशकों पहले शाहबानो ने शुरू की थी, वो आज तक जारी नहीं रहती। रही बात इसे अपराध की श्रेणी में लाने की, तो फिर जान लीजिए,

कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए
जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए
कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए
जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए।

जो तीन शब्द एक हंसती खेलती जिंदगी को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दे, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार होना चाहिए।

नारी गरिमा की ऐतिहासिक विजय

वीणा जायसवाल
अध्यापिका, रीवा विश्वविद्यालय

देश भर की मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई से निजात दिलाने वाला विधेयक जल्द कानून की शक्ल लेगा। वास्तव में तीन तलाक कानून न तो किसी जाति, धर्म और न ही किसी पंथ से संबंधित है, बल्कि यह नारी को समानता का अधिकार देना है। हमारे संविधान में भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। यह एक अमानवीय प्रथा थी जिस पर रोक लगने की उम्मीद है। यह देश में लैंगिक समानता को प्रमाणित करता है तथा लैंगिक न्याय का प्रावधान भी करता है। ऐसा कानून अन्य कई इस्लामिक देशों में भी बना है।

इस विधेयक को अंजाम तक पहुंचाने में महिलाओं ने विशेष योगदान दिया है जो सराहनीय है। इस संघर्ष में सबसे अहम नाम है उत्तराखंड की सायरा बानो का जो इस मामले को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लेकर गईं। उनके अलावा आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहां और अतिया साबरी उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की। इनमें से किसी को फोन पर तलाक मिला था, किसी को स्पीड पोस्ट से, किसी को स्टांप पेपर पर तो किसी को कागज के एक टुकड़े पर, लेकिन ऐसी महिलाएं ही देश की अमानवीय कुप्रथाओं को खत्म करने और मानवता विरोधी कार्यों को समाप्त करने में सदैव अहम भूमिका निभाती रही हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट पर एक गैर-सरकारी संगठन 'इंडिया स्पेंड' ने विश्लेषण किया जिसके अनुसार, भारत में तलाकशुदा महिलाओं में करीब 25 प्रतिशत मुस्लिम हैं। हालांकि मुसलमानों में तलाक का तरीका सिर्फ तीन तलाक को ही समझ लिया गया है। जबकि तीन तलाक से होने वाले तलाक का प्रतिशत बहुत कम है। मुसलमानों में तलाक, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-मुबारत जैसे तलाक के कई अन्य प्रचलित तरीके हैं और इनके माध्यम से ही अधिकतर तलाक होते हैं, लेकिन तीन तलाक की चर्चा सबसे अधिक होती है, जो गैर इस्लामिक होने के साथ साथ असंवैधानिक भी है। इसीलिए तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनको न्याय देने के लिए अनेक प्रयास किए हैं- जैसे दहेज प्रथा पर कानून, घरेलू हिंसा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून, महिलाओं के साथ अत्याचार को समाप्त करने के लिए उनसे कार्यस्थल पर उत्पीड़नात्मक कार्य न हो सके, इसके तमाम कानून बनाकर महिलाओं को एक मजबूत अधिकार प्रदान किया गया है।

आज तक तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया था। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का कार्य सरकार ने कर दिखाया। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें समझौते का प्रावधान भी है, और अगर पति-पत्नी के बीच सुलह हो गया तो इससे परिवार जुड़ सकता है, इसीलिए इसका कार्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

सोचने वाली बात यह है कि देश में आज भी ऐसे राजनीतिक दल व्याप्त हैं जो ऐसे मानवता विरोधी कार्यों को सराहने की बजाय विरोध करना ज्यादा उचित समझते हैं तथा ऐसी कुप्रथाओं को खत्म करने की बजाय उस पर राजनीति करते हैं। उनको यह याद रखना चाहिए कि यह कानून मानवता का परिचायक है। महिलाओं के न्याय से संबंधित है, उनके जीवन को एक नई उम्मीद देने वाला है। इससे उनके अधिकारों का हनन नहीं हो सकेगा। लेकिन अभी भी एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा, क्योंकि कानून बनाना तो एक पक्ष हुआ, लेकिन इस कानून के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना दूसरा पक्ष है। जिन महिलाओं के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, खासकर उन महिलाओं को इसकी समग्र जानकारी हो, देश-समाज को इसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा इस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

खरी-खरी

सड़क के गड्ढों की गुफ्तगू

गिरीश पंकज

किसी शहर में कुछ गड्ढे रहा करते थे। शहर में उनका अच्छा-खासा प्रभाव था। नगर निगम का भी उनको पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था। उनके प्रति लोगों के मन में भी बड़ा सम्मान था। राह चलते जो कोई भी उन्हें देखता, फौरन दूर से नमस्ते करके आगे बढ़ जाता। हां, कुछ नादान किस्म के लोग जो इन गड्ढों की अनदेखी कर आगे बढ़ने की कोशिश करते, उनको ये गड्ढे अपने पास बुलाकर अच्छा सबक सिखाते थे। हर गड्ढे को अपने स्वरूप पर बड़ा गर्व था। गर्व हो भी क्यों न! आखिर आए दिन कोई न कोई उनसे गले मिलने के लिए आकर बिछ ही जाता था। आप ही बताएं, यदि आज की दुनिया में कोई खुद आकर गले मिले तो भला किसे खुशी नहीं होगी? सड़क के गड्ढों को भी होती है।

कभी-कभी गड्ढे अकेले बोर भी होते। लेकिन सहसा उनके अपने अकेलेपन का एहसास खत्म हो जाता था, जब कोई अचानक उनसे लिपट जाता था। कभी कोई बाइक चलाने वाला, कभी साइकिल वाला, कभी कोई पदयात्री। कभी-कभी कार के पहिए भी गड्ढों से हैलो-हाय कर लिया करते थे। इससे गड्ढों के जीवन की बोरियत कम हो जाती। वरना आप ही सोचिए, सड़कों के गड्ढे बेचारे बिछे पड़े हैं चुपचाप, अकेले। उनको देखने वाला कोई नहीं। नगर निगम तक उनकी ओर नहीं देखता। क्या बीतती होगी गड्ढों के मन में? लेकिन जब कोई अचानक रपट कर गड्ढों से लिपटते हुए गले मिलता है तो गड्ढों की आत्मा बहुत खुश होती है, उन्हें शाबाशी देती है और गुनगुना उठती है- आई मिलन की बेला देखो आई...!

बरसात में तो यह गड्ढे गद्गद् रहते हैं। एक गड्ढा दूसरे से कहता है- अब आएगा मजा। सड़क पर पानी भरा रहेगा और लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कहां समतल है और कहां गड्ढा। लोग सीधे आकर हमसे लिपट जाएंगे। पहले गड्ढे की बात सुनकर दूसरे ने कहा- तू बड़भागी है रे! तू कुछ मोटा-ताजा है। तुझसे लिपटने अधिक लोग आते हैं। मैं अभी दुबला-पतला हूं, इसलिए कोई मिलता ही नहीं। कभी कभार कोई आया और लड़खड़ाकर आगे निकल लिया।

बड़े गड्ढे ने उसे सांत्वना देते हुए कहा- चिंता न कर छोटे। तू नगर निगम पर भरोसा रख। कल तू भी मेरी तरह बड़ा जो जाएगा। हो सकता है खाई बन जाए। बारिश आने दे, तेरी छाती भी चौड़ी हो जाएगी। लोग तुझसे भी खूब लिपटेंगे।

बड़े की ये बातें सुनकर छोटे गड्ढे की आंखें छलछला उठीं।

ट्वीट-ट्वीट

तत्काल तीन तलाक पर कानूनी वार के बाद अब लगे हाथों हलाला, मुताह और मिस्यार जैसी कुप्रथाओं का भी खात्मा होना चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा दिया गया है। दावा है कि आइपीसी के सेक्शन में सिर्फ एक वाक्य जोड़ने से ये दुष्कर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। अब इस पर नरेंद्र मोदी सरकार के जवाब का इंतजार है।

समीर अब्बास@TheSamirAbbas

उन्नाव हो या हिंदुस्तान का कोई कोना, विधायक हो या सांसद, मंत्री हो या संतरी, महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म और खून करने वाली को सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए और वो है 'मौत'। अपने समाज के घृणित अंग को हमें खुद ही काटकर अलग करना होगा।

अजय आलोक@alok_ajay

कुलदीप सेंगर को भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया। यह स्वागतयोग्य है। हालांकि वह एक दलबदलू नेता है और उम्मीद है कि अब सपा और बसपा भी उसे वापस अपने खेमे में नहीं लेंगे।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

श्रद्धांजलि

रामविलास पासवान
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री, भारत सरकार

मेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा उसके जैसा

आंखें बंद करता हूं तो अभी भी रामचंद्र की बचपन से लेकर अब तक की सारी गतिविधियां दिमाग में घूम जाती हैं। अब तो वह चार बार का सांसद हो चुका था, अपना भरा-पूरा एक बड़ा परिवार था, लेकिन मेरे लिए वह बच्चे के ही समान था। मुझे याद है कि काफी अरसे पहले हम लोग विदेश गए थे तो सड़क पार करते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बस हंसने लगा कि भैया अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हैं।

सामान्यतया भाइयों में बचपन के दिनों में तो लगाव होता ही है, लेकिन कई कारणों से धीरे-धीरे रिश्तों में कुछ दूरी-सी आने लगती है। लेकिन रामचंद्र और मेरे बीच यह संबंध पूरी तरह से अमिट रहा। शायद कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने हम दोनों को बहुत मजबूती से जोड़कर रखा था।

याद आता है वह दौर, आज से करीब चार दशक पहले का। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। मैं उस समय सामाजिक और राजनीतिक सुधार का झंडा लेकर घूम रहा था। चूंकि मैं शासन-प्रशासन के निशाने पर था, लिहाजा अंडरग्राउंड था। किसी को पता नहीं था कि मैं कहां छिपा हुआ था। छिपते-छिपाते किसी तरह खगड़िया के मारड़ गांव पहुंचा। वहां पर मेरे एक अभिन्न मित्र रहते थे और उन्होंने ही मुझे बुलाया था। दरअसल उनका गांव लगभग चारों तरफ से पानी से घिरा था। ऐसा समझा गया कि वह इलाका मेरे लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यदि वहां कोई आएगा भी तो उसके वहां आने से पहले ही उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अचानक से एक दिन रामचंद्र वहां पहुंच गया। उसने यह कैसे पता लगाया कि मैं यहां छिपा हुआ हूं, इस बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। कुछ देर ठहरने के बाद वह फिर चला गया। यही उसकी खूबी थी, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता था। कभी भी उसने मुझसे कुछ

दिवंगत रामचंद्र पासवान वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे।

नहीं मांगा। जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति था वह। उसकी खुशी इसी में होती थी कि मैं खुश हूं।

आखिरी वक्त तक उसने यही किया। मैं अस्पताल पहुंचा तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। जाहिर है कि तकलीफ रही होगी, लेकिन पूछने पर बिल्कुल सामान्य ढंग से बोला कि कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल टेस्ट के लिए व्हील चेयर की बजाय पैदल ही जाने की बात करने लगा। शायद वह मुझे आश्वस्त करना चाहता था कि सब कुछ ठीक-ठाक है। सचमुच रामचंद्र जैसा भाई कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलेगी।

क्या खोया, मुश्किल है इजहार करना : चिराग पासवान

मेरे लिए यह इजहार कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि मैंने क्या खोया। मेरे छोटे पापा यानी मेरे चाचा एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने व्यवहार से हमेशा एक नया मापदंड खड़ा कर देते थे। मुझे याद है कि वर्ष 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आया था तब मेरे लिए संसद में उन्होंने गाइड का काम किया। यही काम 2019 में वह मंझले पापा के लिए करते देखे गए।

पार्टी की बात करूं तो उनका व्यवहार किसी भी कार्यकर्ता के लिए आदर्श स्थापित करता है। वह मुझसे रिश्ते में भी और उम्र में भी बहुत बड़े थे। उनका अनुभव बहुत बड़ा था। मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, लेकिन पार्टी के मंच पर वह इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखते थे। कभी उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। यह सामान्य बात नहीं है। मैं असहज हो जाता था, लेकिन वह बहुत ही सहजता से सबकुछ कर और कह जाते थे।

फैसले के साथ खड़ा होना, समर्थन देकर नैतिक बल बढ़ाना, उनकी यह सब बड़ी खासियतें थीं। यह अद्भुत गुण था जो किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस सहजता और आत्मीयता से वह लोगों से मिलते थे, क्षेत्र की जनता की बातें सुनते थे, वह किसी भी जन-प्रतिनिधि के लिए एक बड़ी सीख हो सकती है।

एक और गुण जो उनमें कूट-कूट कर भरा हुआ था और मैं उनसे सीखना चाहता हूं, वह है निराशा से कभी घबराना नहीं। मुझे याद है कि वर्ष 2009 में हमारी पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ था। वह स्वयं भी हारे थे और पापा भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उस वक्त परिवार में माहौल को सामान्य बनाने में भी उन्होंने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। छोटे पापा, आप मुझे बहुत याद आएंगे।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर रोक लगाने का फैसला सही है?

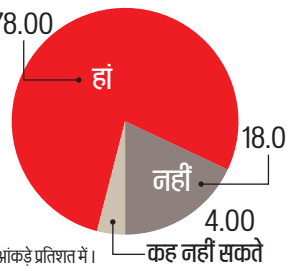

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

भाजपा ने दुष्कर्म के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकालने में देर कर दी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

छूटा जब कांग्रेस अरु कर्नाटक का साथ,
टीपू बेचारा हुआ फिर से वहां अनाथ।
फिर से वहां अनाथ खटाई पड़ी जयंती,
येदियुरप्पा के साथ न उसकी बिल्कुल बनती।
गढ़-गढ़कर इतिहास आजतक सेक्युलर-झूठा,
कांग्रेस का साथ आज सत्ता से छूटा!

-ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

रामकृष्ण जायसवाल
स्वतंत्र टिप्पणीकार

बिना नाखून वाला पंजा बनता आरटीआइ

सूचना का अधिकार कानून में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है, लेकिन इसमें विचारणीय यह है कि ऐसा होने से इसका मूल उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है, जिस कारण इसके सभी पहलुओं पर समग्र चर्चा होनी चाहिए थी

सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य सरकार और शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करना है। इसी के लिए सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। लेकिन समयानुसार सूचना के अधिकार का उपयोग लोगों के द्वारा अपने निजी हितों तथा दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की ऐसी सूचनाओं की मांग लोगों द्वारा की जाने लगी जिसका उनसे कोई औचित्य नहीं होता था। भारत में इसका प्रमुख कारण है कि यहां नागरिक समाज का पूर्णतया अभाव रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आम तौर पर किसी देश में नागरिक समाज बनने में उसकी आजादी के बाद तकरीबन 200 वर्षों का समय लगता है। भारत के संदर्भ में यदि इस समयावधि की बात करें तो यह अभी बहुत दूर है। भारत का नागरिक आज इतना प्रबुद्ध नहीं हुआ है जो सरकार के कार्यों में सहयोग कर सके। दूसरी ओर सूचना के अधिकार कानून में अधिकारियों की भी सूचना तंत्र में उदासीनता को देखा जा सकता है जिसने आरटीआइ को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरटीआइ के अंतर्गत मांगी गई सूचना 30 दिनों में देनी अनिवार्य होती है, लेकिन उदासीनता के कारण सभी नियम तिरोहित हो चुके हैं। इससे बड़ी संख्या मे शिकायतें और अपील लंबित हैं। वर्ष 2019 के मई माह तक ही 52,000 अपीलें और शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं। इसका प्रमुख कारण है सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों का न होना। साथ ही एक प्रमुख कारण नागरिक समाज का अभाव तो है है।

इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। प्रायः सूचना का अधिकार, नागरिकों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का आरटीआइ में संशोधन विधेयक लाकर सूचना के अधिकार को कमजोर करने का कार्य कर रही है। सरकार ने सूचना अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा लिया

गया है और अब इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है।

इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आरटीआइ अधिनियम की धारा 13 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध करती है। इस विधेयक मे उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हो जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय है। ऐसे में इनकी सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय होंगी। लेकिन यह प्रश्न उठना वाजिब है कि क्या सरकार संशोधन विधेयक लाकर सूचना के अधिकार को एकाधिकार नियंत्रित चाहती है? क्योंकि यह संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सूचना के अधिकार का पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होगा और सरकार ही सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों, वेतन, भत्ते आदि तय करेगी, जिसका निर्धारण संसद के हाथों में था। सूचना आयोग पूर्णतः अपनी स्वायत्तता को बनाए हुए था, लेकिन इस संशोधन के पूर्ण होते ही आरटीआइ की डोर केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी। फिर आरटीआइ अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने कार्यों और दायित्वों आदि का समग्रता से निर्वाह नहीं कर सकेगी। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरटीआइ पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होते ही वह उसके दबाव में आ जाएगी और स्वतंत्रता के साथ सरकार के कार्यों को उजागर नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, इस संशोधन के बाद आम नागरिकों को सरकार से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि यह सही है कि आरटीआइ कानून में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी और यह संशोधन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, किंतु इसमें केंद्र सरकार को स्वयं इसे अपने नियंत्रण में लेने से एक प्रकार से यह संदेश जा सकता है कि यह आरटीआइ को कमजोर बनाने जैसा है। सूचना आयोग की उदासीनता को दूर करने तथा सूचना आयुक्तों के खाली पदों को भरने करने की जरूरत थी। लेकिन सूचनाधिकार कानून की स्वायत्तता को भंग करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि आरटीआइ कानून की स्वायत्तता भंग होना और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आना, यह बिना नाखून वाले पंजे के समान होने जैसा ही है।

हालांकि अब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, ऐसे में अब इसे कानून का रूप लेने में महज कुछ ही औपचारिकताएं बची हैं। चाहे कुछ भी हो इस कानून की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए ताकि सरकार के सभी कार्यों और उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। इसे बिना नाखून वाला पंजा बनाना, इस कानून को पूरी तरह से कमजोर करने के समान होगा।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 2 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

14 साल बाद घाटे के दलदल में एयरटेल

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्षों तक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही भारती एयरटेल ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 2,866 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। गत 14 साल में कंपनी ने पहली बार कंसोलिडेटेड घाटा दर्ज किया है। सुनील मित्तल की कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 97.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी ने 107.2 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया था। कंपनी के बयान के मुताबिक उसकी कुल आय आलोच्य तिमाही में 4.7 फीसद बढ़कर 20,738 करोड़ रुपये रही।

इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में हम अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट हैं। अब उद्योग की बारी है कि वह अपना योगदान करे।
— अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	37,018.32	▼ 462.80
निफ्टी	10,980.00	▼ 138.00
सोना प्रति दस ग्राम	₹35,795	▲ ₹15
चांदी प्रति किलोग्राम	₹41,530	▼ ₹590
डॉलर	₹69.06	▲ ₹0.27
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$63.63	

कारपोरेट हलचल

संस्कृत अकादमी में आयुर्वेद शिक्षण केंद्र

दिल्ली संस्कृत अकादमी में एक आयुर्वेद प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया गया। इस अध्ययन केंद्र में लगभग 193 प्रशिक्षार्थी शिक्षण ले रहे हैं। यह केंद्र तीन माह चलेगा। केंद्र का शुभारंभ दिल्ली संस्कृत अकादमी की उपाध्यक्ष डॉ. कांता भाटिया ने किया।

सीपीडब्ल्यूडी का हरियाली महोत्सव

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के बागबानी विभाग ने केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर एनएच4 एनआइटी के पार्क में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में सीपीडब्ल्यूडी फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता इंद्रजीत सिंह, सीपीडब्ल्यूडी में सहायक निदेशक इंद्रमणि त्यागी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आवासीय परिसर में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण

एनटीपीसी दादरी विद्युत नगर स्थित महिला संस्था जागृति समाज ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। जागृति समाज की सदस्यों और बाल वाटिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने बाल भवन एवं बाल वाटिका परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

आइजीएल में निदेशक बने गर्ग

अमित गर्ग ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) में निदेशक (कॉमर्शियल) पद पर कार्यभार संभाल लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट गर्ग को तेल व गैस क्षेत्र में 32 वर्ष का लंबा अनुभव है। गेल में आने से पूर्व गर्ग बीपीसीएल में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

जुलाई के आंकड़ों से और गहराई ऑटो बाजार की मंदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जुलाई में कारों व अन्य वाहनों की बिक्री में तेज गिरावट
- मारुति सुजुकी की बिक्री 36 फीसद, होंडा की 49 फीसद तक गिरी

जुलाई का महीना भी देश के आटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई राहत की खबर लेकर नहीं आया। सभी तरह के वाहनों की बिक्री देश में गिरती जा रही है। मध्यम वर्ग छोटी व एसयूवी कार नहीं खरीद रहा, और वाणिज्यिक वाहनों के भी खरीदार नहीं मिल रहे। ट्रैक्टरों की बिक्री भी घट रही है, जो बताती है कि ग्रामीण बाजार में भी मांग की स्थिति अच्छी नहीं है।

गुरुवार को आटोमोबाइल कंपनियों ने जुलाई की बिक्री के जो आंकड़े पेश किए हैं। उसके मुताबिक कार बाजार में करीब 50 फीसद हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी की घरेलू बाजार में बिक्री 36 फीसद कम हुई है। होंडा मोटर्स की कारों की बिक्री 49 फीसद गिरकर 10,250 यूनिट रह गई है। ह्युंडई मोटर की बिक्री में 10 फीसद की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले एक वर्ष में दो नए मॉडल लांच कर चुकी ह्युंडई की घरेलू बाजार में बिक्री 10 फीसद घटी है। साफ है कि नए मॉडल भी ग्राहकों को लुभा नहीं पा रहे।

कार बाजार के किसी भी सेगमेंट में उम्मीद नहीं दिख रही है। एस्सार समूह की एस्सार एग्रो मशीनरी ने बताया कि पिछले महीने ट्रैक्टरों की बिक्री 13.4 फीसद कम हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के आंकड़े बताते हैं कि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 17 फीसद घटकर 15,969 यूनिट रह गई है। कंपनी की पैसेंजर वाहनों की बिक्री 15 फीसद घटी है। समूह के प्रमुख (बिक्री व विपणन) वीजे राम नाकरा का कहना है, 'ग्राहकों की उदासीनता अभी तक खत्म नहीं हुई है। मानसून की स्थिति बेहतर है। ऐसे में अब उम्मीद आगामी त्योहारी सीजन से ही है।' भारी वाहन और वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली एक अन्य कंपनी अशोक लेलैंड की बिक्री 28 फीसद घटी है। मझोले व छोटे वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री को 41 फीसद का झटका लगा है।

दोपहिया वाहनों का भी बुरा हाल : दोपहिया वाहन कंपनियों की स्थिति भी महीना दर महीना बिगड़ती जा रही है। बजाज ऑटो ने गुरुवार को बताया कि जुलाई में उसकी बिक्री में पांच फीसद कमी आई है। दोपहिया वाहनों की कुल घरेलू बिक्री तो 13 फीसद की गिरावट के साथ 2,05,470 यूनिट रह गई है। हालांकि निर्यात में आठ फीसद की वृद्धि हुई है, जिससे कुल बिक्री की गिरावट पांच फीसद पर ही सीमित रही है। देश की एक अन्य दोपहिया निर्माता कंपनी टीवीएस की बिक्री इस महीने 13 फीसद घटी है। अभी तक स्कूटरों की बिक्री पर मंदी की छाया नहीं पड़ी थी। लेकिन टीवीएस के स्कूटरों की बिक्री इस महीने 11.59 फीसद घटी है।

मारुति सुजुकी का प्रदर्शन लचर : मारुति सुजुकी की कुल वाहन बिक्री 33.5 फीसद घट कर 1,09,264 यूनिट रह गई है। पिछले वर्ष जुलाई में कुल बिक्री 1,64,369 यूनिट थी। छोटी कारों (आल्टो, वैगनआर) की बिक्री में 69 फीसद, कांपैक्ट कारों (स्विफ्ट, इग्निस, बलेनो, डिजायर) की बिक्री 22.7 फीसद घटी है। लेकिन 38.1 फीसद की गिरावट के साथ सबसे चौंकाने वाली बिक्री यूटिलिटी व्हीकल्स (विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस, आर्टिगा) सेग्मेंट की रही। यह बिक्री चौंकाने वाली इसलिए है, क्योंकि यह सेग्मेंट सिर्फ मारुति के लिए नहीं, बल्कि दूसरी कार कंपनियों के लिए भी अब तक उम्मीद की एकमात्र किरण था। यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी, एमपीवी आदि) की बिक्री में कमी ऑटो सेक्टर में मंदी की गंभीरता को बताता है।

ईवी से संबंधित लक्ष्य में ढिलाई नहीं बरतेगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नीति आयोग के सीईओ ने कहा - शहरों को स्वच्छ बनाने और तेल आयात घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जरूरी
- यह भी कहा - पूर्व की गलत नीतियों के चलते मोबाइल, सोलर पैनल आयातक बनकर रह गए, ईवी में ऐसा नहीं होने देंगे

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के बावजूद सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी तैयारियों में कोई ढिलाई बरतने नहीं जा रही है। सरकार इस संबंध में अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल और पेट्रोल जैसे परंपरागत ईंधन से चलने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए आने वाले समय में उन पर टैक्स का बोझ और बढ़ा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि हम इंडस्ट्री के रोडमैप का इंतजार कर रहे हैं। हम उन उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं, जिन्हें हासिल करना चाहते हैं। हम यह निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ करना चाहते हैं। सरकार ने हमारे शहरों को स्वच्छ बनाने, नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने, तेल आयात कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आंदोलन को गति देने के लिए हरसंभव उपाय किया है। अब निजी क्षेत्र की बारी है कि वह भी अपना योगदान करे। अब उन्हें स्वच्छ वाहनों का चैंपियन बनने के लिए नेतृत्व करना चाहिए।

कांत का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार 2023 के बाद 150 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया और 2025 के बाद तिपहिया की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसे लेकर ऑटो उद्योग खासा चिंतित है। उद्योग का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं मिलने की वजह से उनके लिए भविष्य की रणनीति पर काम करना मुश्किल हो रहा है।

कांत ने कहा, 'पूर्व की गलत नीतियों के चलते हम मोबाइल, टेलीकॉम उपकरण और पीवी सोलर का आयात करने वाले देश बन गए हैं। हम इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में ऐसा नहीं होने देंगे। हम समुचित उपाय करते हुए घरेलू बाजार और निर्यात के लिए मेक इन इंडिया पर जोर जारी रखेंगे। हम भारत को वैश्विक बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाएंगे।'

इस बीच, सूत्रों का कहना है कि जरूरी हुआ तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से पेट्रोल-डीजल वाहनों पर टैक्स का बोझ बढ़ा सकती है, ताकि उनके इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सके। इससे जो राशि आएगी, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने पिछली बैठक में ईवी पर जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसद करने का फैसला किया है। इससे पूर्व आम बजट 2019-20 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपायों का एलान किया जा चुका है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो ब्याज के भुगतान के एवज में वह 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है।

मंदी की दस्तक ▶ आइएमएफ, बीओएएमएल घटा चुके हैं अनुमान

क्रिसिल ने भी जीडीपी विकास दर अनुमान में की कटौती

क्रिसिल ने 7.1 फीसद से घटाकर 6.9 फीसद रखा चालू वित्त वर्ष का विकास दर अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

आर्थिक सुस्ती के मंडराते बादलों के बीच गुरुवार को देश की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए आर्थिक विकास दर अनुमान घटा दिया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर अनुमान 20 आधार अंक कम करते हुए 6.9 फीसद रखा है। इस कटौती के लिए क्रिसिल ने मानसून के पर्याप्त नहीं होने और वैश्विक मंदी को सबसे प्रमुख कारण बताया है। कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने घरेलू मांग में गिरावट का हवाला देते हुए भारत का आर्थिक विकास दर अनुमान घटाकर सात फीसद कर दिया था। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों की शोध एजेंसियों ने भी पिछले दिनों भारत की जीडीपी वृद्धि दर में चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 आधार अंकों यानी 0.5 फीसद तक की कमी का अनुमान लगाया था। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने भी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर सात फीसद किया था।

यही नहीं, क्रिसिल ने आने वाले दिनों में अनुमान और घटाने की संभावना से इन्कार नहीं किया है। अनुमान घटाने की पीछे आर्थिक सुस्ती की बात कही गई है। हालांकि क्रिसिल ने यह भी कहा है कि दूसरी छमाही में ब्याज दरों की कटौती और उपभोग बढ़ने से स्थिति सुधर सकती है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 6.8 फीसद उसके पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में 8.2 फीसद रही थी। आर्थिक सर्वे में सरकार ने विकास दर के सात फीसद रहने की बात कही है।

ये चुनौतियां बनीं आधार : क्रिसिल ने देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष कई तरह की मौजूदा चुनौतियों को गिनाया है। इनमें मानसून की बारिश में कमी, वैश्विक कारोबार विवाद, एनबीएफसी संकट शामिल हैं। इन सभी वजहों ने मिलकर मध्यम वर्ग की तरफ से बाजार में आने वाली मांग पर बहुत ज्यादा असर डाला है। क्रिसिल ने यह अनुमान देश के प्रमुख आठ औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर महज 0.2 फीसद रह जाने की खबरों के एक दिन बाद ही घटाया है।

चीन में विस्तार नहीं कर पा रहीं आइटी कंपनियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गैर-कर बाधाओं के चलते कंपनियों की वृद्धि रुकी
- वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने मांगा पूरा ब्योरा, कहा चीन समेत सभी देशों के समक्ष रखेंगे मुद्दा

चीन में भारत की आइटी कंपनियों को कारोबार करने में दिक्कत पेश आने लगी है। चीन की तरफ से गैर-कर बाधाओं के चलते आइटी सेक्टर की भारतीय कंपनियां वहां अपना कारोबार विस्तार नहीं कर पा रही हैं। सरकार ने आइटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम से इस संबंध में विस्तार से ब्योरा मांगा है, ताकि चीन की सरकार के समक्ष इस मसले को उठाया जा सके।

आइटी कंपनियों की तरफ से यह मसला वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बुधवार को हुई बैठक में उठा। गोयल ने आइटी कंपनियों के मुद्दों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई थी। बैठक में आइटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस ने भी हिस्सा लिया। कंपनियों ने कहा कि चीन के बाजार में उनकी पहुंच सीमित होती जा रही है। इसके चलते चीन में भारतीय कंपनियों के निवेश और कारोबार में वृद्धि रुक गई है। आइटी कंपनियों के साथ वार्ता का यही प्रमुख मुद्दा भी था क्योंकि इसकी वजह से आइटी कंपनियां वहां नया कारोबार भी शुरू नहीं कर पा रही हैं। गौरतलब है कि चीन का आइटी सेवा बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।

बैठक में सत्यम वेंचर्स इंजीनियरिंग, एनआइआइटी टेक, इनवेंटो रोबोटिक्स, टेक महिंद्रा और विप्रो के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। गोयल ने बैठक में नैसकॉम से चीन समेत समूचे पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय कंपनियों के सामने आ रही चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा है। गोयल ने बैठक में कहा, 'सरकार भारतीय कंपनियों को पूरी दुनिया में अपने पंख फैलाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। इसके लिए वह चीन समेत जापान और कोरिया के साथ बातचीत करने को तैयार है।'

वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने कंपनियों को अन्य बाजारों में भी संभावनाएं तलाशने को कहा। इनमें नॉर्डिक देश, पूर्वी और मध्य यूरोप, कनाडा, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। गौरतलब है कि देश के जीडीपी में आइटी उद्योग का योगदान 2016-17 में 7.7 फीसद था। इसके 2025 में 10 फीसद तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

कारोबार की विफलता को अनुचित नहीं मानना चाहिए : सीतारमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

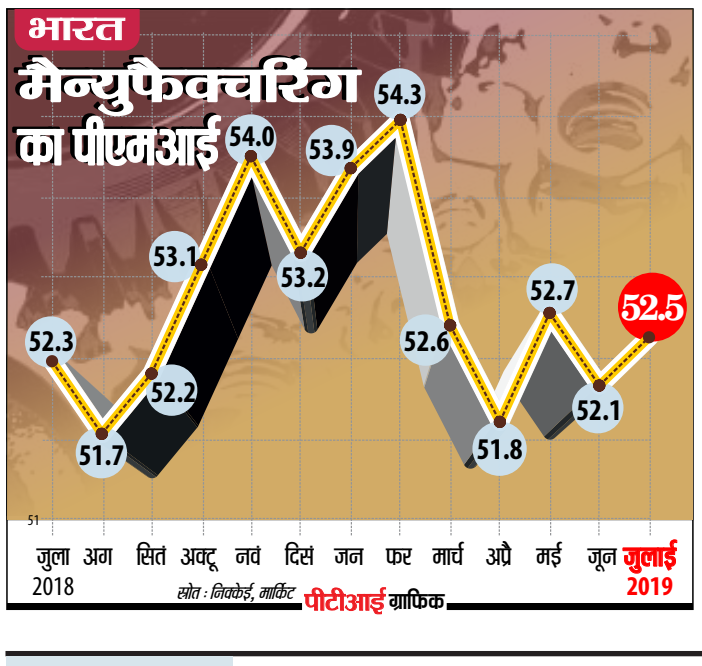

- वित्त मंत्री ने कहा, कारोबार छोड़ने का सम्मानजक सिस्टम होना चाहिए

कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की मृत्यु पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश में कारोबार की विफलता को अनुचित नहीं मानना चाहिए। इसके उलट हमें सम्मानित तरीके से कारोबार छोड़ने की प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) पर बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि कारोबारियों को आइबीसी के प्रावधानों के अनुरूप कारोबार छोड़ने या समस्या के समाधान का सम्मानजक अवसर मिलना चाहिए। सीतारमण का यह बयान ऐसे समय आया है जब बुधवार को ही सिद्धार्थ का शव कर्नाटक की नेत्रावती नदी के किनारे मिला। सिद्धार्थ ने एक पत्र में कहा था कि अन्य वजहों के साथ-साथ आयकर विभाग द्वारा लगातार परेशान किए जाने के चलते वे खुद को कारोबार में विफल महसूस कर रहे हैं। हालांकि आयकर विभाग ने इन आरोपों को खारिज किया है। तेलुगू देशम पार्टी के सदस्य जयदेव गल्ला ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के चलते व्यवसाय फेल हो सकता है। बैंकों की जवाबदेही का संज्ञान में लेने की जरूरत है। लोन लेने के लिए व्यवसायी व्यक्तिगत गारंटी के हस्ताक्षर करते हैं, उसके चलते वे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं।

जीएसटी संग्रह में मात्र 5.8 फीसद वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह

अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत देते हुए चालू वित्त वर्ष के जुलाई में जीएसटी संग्रह में मात्र 5.8 फीसद वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल जुलाई में जीएसटी संग्रह 1,02,083 करोड़ रुपये रहा, जबकि यह पिछले साल महीने में 96,483 करोड़ रुपये था। इस साल जून में जीएसटी संग्रह 99,939 करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई में सीजीएसटी संग्रह 17,912 करोड़ रुपये, एसजीएसटी संग्रह 25,008 करोड़ रुपये और आइजीएसटी संग्रह (सैटलमेंट से पूर्व) 50,612 करोड़ रुपये रहा। आइजीएसटी संग्रह में 24,246 करोड़ रुपये आयात पर आइजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। वहीं, क्षतिपूर्ति सेस के रूप में 8,551 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल और मई में राज्यों को क्षतिपूर्ति सैस के रूप में 17,789 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

जीएसटी संग्रह में इतनी कम वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुस्ती की ओर इशारा करती है। हालांकि सरकार का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान घरेलू व्यापार से वसूले गए जीएसटी में पिछले साल समान अवधि के मुकाबले 9.2 फीसद की वृद्धि हुई है जबकि आयात पर जीएसटी संग्रह में 0.2 फीसद की गिरावट आई है। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान जीएसटी संग्रह में महज 6.83 फीसद की वृद्धि हुई है। जहां तक रिटर्न फाइलिंग का सवाल है, तो इस साल जून के लिए 31 जुलाई तक 75.79 लाख रिटर्न दाखिल हो चुके हैं।

यह है सरकार का लक्ष्य : चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सीजीएसटी से 5.26 लाख करोड़ रुपये तथा आइजीएसटी से 28,000 करोड़ रुपये (सभी सैटलमेंट के बाद) जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं क्षतिपूर्ति सैस के रूप में 1.09 लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा जुटाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर सरकार ने वित्त वर्ष (2019-20) में जीएसटी के जरिये 6,63,343 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

जीएसटी पहली जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। तब से कुल 25 महीनों में से सिर्फ सात महीने ऐसे रहे हैं जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है।

निराशा

सेंसेक्स 462.80 अंकों की गिरावट के साथ 37,018.32 पर बंद, निफ्टी 138.00 अंकों के नुकसान के साथ 10,980.00 पर स्थिर हुआ

पांच महीने के निचले स्तर तक लुढ़का बाजार

मुंबई, प्रेट्र : आर्थिक सुस्ती के आंकड़े और यूएस फेड के सख्त बयान के कारण निवेशकों का उत्साह घटने से गुरुवार को शेयर बाजारों में गिरावट रही और प्रमुख सूचकांक पांच महीने के निचले स्तर पर आ गए। बीएसई का सेंसेक्स 462.80 अंकों की गिरावट के साथ 37,018.32 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 786.94 अंकों का गोता लगाकर 36,694.18 का निचला स्तर छूआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 138.00 अंकों की गिरावट के साथ 10,980.00 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक शुरुआती मार्च के बाद निचले स्तर पर बंद हुए हैं।

सेंसेक्स में वेदांता में सर्वाधिक 5.55 फीसद गिरावट रही। टाटा मोटर्स, एसबीआइ और भारती एयरटेल में चार फीसद से अधिक, यस बैंक और इन्फोसिस में तीन फीसद से अधिक, टाटा स्टील और लार्सेन एंड टुब्रो में दो फीसद से अधिक गिरावट रही। यस बैंक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, टीसीएस और एशियन पेंट्स एक फीसद से अधिक लुढ़के। दूसरी ओर मारुति सुजुकी में सर्वाधिक 1.86 फीसद तेजी रही। पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक फीसद से अधिक उछले।

प्रतीकात्मक

अन्य शेयरों में बीएसई पर एचसीएल इन्फोसिस्टम्स में 6.29 फीसद और टीवीएस मोटर कंपनी में 2.49 फीसद गिरावट रही। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के धातु सेक्टर में सर्वाधिक 3.37 फीसद गिरावट रही। दूसरी ओर ऊर्जा सेक्टर में सर्वाधिक 0.51 फीसद तेजी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.86 फीसद और स्मॉलकैप में 1.10 फीसद गिरावट रही।

यूएस फेड ने किया निराश : अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) ने बुधवार को अपनी मुख्य दर 0.25 फीसद घटाकर 2.0-2.25 फीसद कर दिया। फेड ने एक दशक से अधिक समय में पहली बार अपनी ब्याज दर में कटौती की है। लेकिन इसके बाद फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान ने निवेशकों को निराश कर दिया। उन्होंने कहा कि फेड का यह कदम किसी कटौती चक्र की शुरुआत नहीं है।

आर्थिक मोर्चे पर मिले झटके : बुधवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए सरकारी आंकड़े के मुताबिक जून में प्रमुख आठ उद्योगों की रफ्तार घटकर 0.2 फीसद रह गई। इससे औद्योगिक विकास में गिरावट की आशंका भी पैदा हो गई है। वित्तीय घाटा भी पहली तिमाही में ही पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान के 61.4 फीसद पर पहुंच गया है। वाहन कंपनियों ने भी गुरुवार को जुलाई की बिक्री के फीके आंकड़े पेश किए। इससे पता चलता है कि उपभोक्ता माहौल में अभी भी तेजी नहीं आई है। वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश का विकास अनुमान घटाकर 6.9 फीसद कर दिया है।

विदेशी निवेशकों ने पूंजी निकाली : सेंट्रम ब्रोकिंग के सीनियर वीपी और रिसर्च (वेल्थ) प्रमुख जगन्नाथन थुनुगंटला ने कहा कि बजट के बाद विदेशी निवेशकों ने गत करीब एक महीने में तीन अरब डॉलर (करीब 20.7 हजार करोड़ रुपये) के शेयर बेचे हैं। यूएस फेड के चेयरमैन के बयान ने भी निवेशकों का उत्साह घटाया। तिमाही नतीजे बता रहे हैं कि पहली बार निफ्टी में शामिल कंपनियों का शुद्ध लाभ घट सकता है।

कॉफी डे एंटरप्राइजेज में लगातार तीसरे दिन लगा निचला सर्किट

नई दिल्ली : कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में लगातार तीसरे दिन निचला सर्किट लगा। ये बीएसई पर 9.98 फीसद फिसलकर 110.95 रुपये पर बंद हुए। गत तीन सत्रों में कंपनी के शयर 42 फीसद से अधिक लुढ़क चुके हैं और इस दौरान कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,723.16 करोड़ रुपये घट गया है।

सोना लगभग सपाट, चांदी 590 रुपये टूटी

- सोना 15 रुपये चढ़कर 35,795 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा
- चांदी 590 रुपये लुढ़ककर 41,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों के कमजोर रुझानों और घरेलू बाजारों में सुस्त मांग के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 590 रुपये लुढ़ककर 41,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोना 15 रुपये की मामूली मजबूती के साथ 35,795 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया।

न्यूयॉर्क में सोने में 1,407 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.12 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में तेजी आने से अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार में सोने पर दबाव दिखा। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुख्य नीतिगत ब्याज दर में भविष्य की संभावित कटौती को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। इसके कारण विदेशी बाजारों में सोने में बिक्री का रुझान रहा। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी मुख्य ब्याज दर 0.25 फीसद घटाकर 2.0-2.25 फीसद कर दी। यूएस फेड ने 10 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दर घटाई है। राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 15 रुपये की मामूली मजबूती के साथ 35,795 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 35,625 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 27,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर स्थिर रही।

चांदी हाजिर 590 रुपये लुढ़ककर 41,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वीकली डिलीवरी 864 रुपये गिरकर 40,570 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये गिरकर 84,000 रुपये खरीद और 85,000 रुपये बिक्री के स्तर पर आ गई।

238 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 तक। यह साल 2018 में 142 अरब डॉलर था। यह बात अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला पिछले दिनों कोलोराडो में एक कार्यक्रम के दौरान कही थी।

मारा गया ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा

आतंक पर अंकुश ▶ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका को दी थी धमकी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

गोपनीय अभियान के तहत अमेरिका ने की कार्रवाई

वाशिंगटन : अमेरिका के लिए एक वक्त बड़ा खतरा बनने वाले अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा भी मारा गया। हमजा (30) ने अपने पिता की मौत का बदला देने के लिए कई बार अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी। यह हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि अलकायदा के उत्तराधिकारी माने जा रहे हमजा को कब और कहां ढेर किया गया। उसके पिता ओसामा को अमेरिका के सील कमांडो ने मई, 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हमजा को मार गिराने के अभियान में अमेरिकी सरकार की अहम भूमिका थी। उन्होंने इस गोपनीय अभियान के बारे में इस शर्त पर जानकारी दी कि उनके नामों को गुप्त रखा जाएगा। इन अधिकारियों ने हालांकि यह नहीं बताया कि जिस हमले में हमजा मारा गया, उसे कब और कहां अंजाम दिया गया था। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ट्रंप प्रशासन के पहले दो साल के कार्यकाल के दौरान हमजा बिन लादेन मारा गया। उसे इस साल फरवरी में विदेश मंत्रालय के उस एलान से पहले मारा गया था, जिसमें हमजा का पता बताने वाले व्यक्ति को दस लाख डॉलर (करीब सात करोड़ रुपये) का इनाम देने की घोषणा की गई थी।

ओसामा के 20 बच्चों में एक था हमजा : अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गत फरवरी में बताया था कि ओसामा के 20 बच्चों में हमजा 15वें स्थान पर है। उसकी तीसरी पत्नी से हमजा का जन्म हुआ था। अलकायदा ने हाल के सालों में उसके कई संदेश जारी किए थे। लेकिन पिछले कुछ माह से उसका कोई संदेश नहीं आया।

अलकायदा सरगना बनाने की थी तैयारी : फाउंडेशन फॉर द डिफेंस डेमोक्रेसिस के वरिष्ठ सदस्य थॉमस जॉस्लीन ने कहा, 'ऐसी संभावना है कि हमजा पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उसे अलकायदा के अगले सरगना के तौर पर तैयार किया जा रहा था। तालिबान के साथ संबंधों में भी उसकी अहम भूमिका थी।'

अल-जवाहिरी की तलाश जारी : एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अयमान अल-जवाहिरी को अलकायदा का सरगना बनाया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए को उसकी अब भी तलाश है। सीआइए ने उसे खोजने के लिए 2012 और 2013 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में कई प्रयास किए थे। लेकिन उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका था।

हमजा फाइल फोटो

ट्रंप ने नहीं दिया जवाब

ह्वाइट हाउस में बुधवार को जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमजा के मारे जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता।'

सात करोड़ रुपये का इनामी आतंकी था हमजा

दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना रहा ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन के मारे जाना का दावा किया गया है। अमेरिका ने उसपर 10 लाख डॉलर यानी लगभग सात करोड़ रुपये इनाम की घोषणा की थी। हमजा तेजी से अलकायदा का प्रमुख नेता बनकर उभर रहा था।

हमजा के पिता आतंकी ओसामा को 2011 में मार गिराया था। फाइल

ओसामा का था सबसे प्रिय बेटा

हमजा बिन लादेन सऊदी अरब के जेद्दाह में 1989 को पैदा हुआ था। हमजा की जिहादी प्रवृत्ति को देखते हुए वह ओसामा के सबसे प्रिय बेटों में से एक था। उसका पूरा नाम हमजा बिन ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था।

आतंकी की बेटी से शादी

हमजा बिन लादेन ने 17 साल की उम्र में ईरान में अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला की बेटी से शादी की। उसका ससुर भी अलकायता का आतंकी लीडर था। इस शादी के कई वीडियो सामने आए थे। अगस्त 2018 में हमजा के चाचा के हवाले से खबर आई थी कि उसने 9/11 के अपहर्ता मोहम्मद अता की बेटी से शादी की है, लेकिन हमजा के भाई उमर बिन लादेन ने इसका खंडन किया था।

पहले भी आई मारे जाने की खबर

जनवरी 2001 में जब हमजा 12 वर्ष का था, तभी अमेरिकी हवाई हमलों में उसके मारे जाने का वीडियो जारी किया गया था। यह तब की बात है जब हमजा अपने पिता लादेन के साथ दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में अपने भाई की शादी में शामिल होने गया था। मार्च 2003 में भी हमजा और उसके भाई शाद बिन लादेन के घायल होने और पकड़े जाने की झूठी खबरें आई थीं।

बेनजीर भुट्टो की हत्या में आया नाम

वर्ष 2007 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या करने में उसका नाम आया। इसके बाद वह ईरान में 2010 तक घर में नजरबंद रहा।

अमेरिका ने घोषित किया वैश्विक आतंकी

अमेरिका ने जनवरी 2017 में हमजा बिन लादेन को आधिकारिक तौर वैश्विक आतंकी सूची में शामिल किया था। उसे लादेन के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। उसकी आतंकी और आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया। यहीं नहीं अमेरिका ने उसकी सूचना देने पर सात करोड़ रुपये इनाम देने की घोषित भी की थी।

अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री पर लगाया प्रतिबंध

ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ की फाइल फोटो। एएफपी

- ईरान को स्पष्ट संदेश देने के लिए ट्रंप प्रशासन ने की कार्रवाई
- जरीफ ने प्रतिबंध का किया स्वागत, कहा-कोई असर नहीं

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन : ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से ईरान के साथ बातचीत की संभावनाएं पूरी तरह धूमिल हो गई हैं। अमेरिकी कार्रवाई का स्वागत करते हुए जरीफ ने कहा है कि इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के कोषागार मंत्री स्टीवन मेंयूचिन ने कहा, 'ईरानी शासन को यह स्पष्ट संदेश देने वाला कदम है कि उसके हालिया कृत्य पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। जरीफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के गैरजिम्मेदाराना एजेंडे पर अमल करते हैं।' इस कार्रवाई पर जरीफ ने कहा, 'अमेरिकी प्रतिबंध की वजह यह है कि मैं ईरान का दुनिया में प्रमुख प्रवक्ता हूं। इसका मेरे या मेरे परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान के बाहर मेरी कोई संपत्ति नहीं है। आपका आभारी हूं कि आप अपने एजेंडे के लिए मुझे इतना बड़ा खतरा समझ रहे हैं।'

प्रतिबंध का क्या पड़ेगा असर : ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध के चलते जरीफ की अमेरिका में अगर कोई संपत्ति होगी तो वह जब्त कर ली जाएगी। वह अमेरिका में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। वह अक्सर ही अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ईरानी मिशन का दौरा करते रहते हैं। इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि अमेरिका के साथ अगर बातचीत का कोई रास्ता खुलता है तो ईरान की ओर से कौन अगुआई करेगा? वह 2013 से ईरान के विदेश मंत्री हैं।

अमेरिका से अच्छा जुड़ाव : ईरानी विदेश मंत्री जरीफ का अमेरिका से अच्छा जुड़ाव है। यही वजह यह है कि उन्होंने अमेरिका से ही पढ़ाई की है। अमेरिका खामनेई समेत ईरान के विशेष बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और शीर्ष सैन्य प्रमुखों पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है।

रूहानी ने प्रतिबंध को बताया, बचकाना कदम

तेहरान, एपी : ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने विदेश मंत्री जरीफ पर प्रतिबंध लगाने के कदम को बचकाना और कूटनीतिक अवरोध करार दिया है। रूहानी ने कहा, 'वे (अमेरिकी) बचकाना काम शुरू कर रहे हैं। वे हर दिन दावा करते हैं कि बिना शर्त ईरान के साथ वार्ता करना चाहते हैं और फिर हमारे विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगाते हैं।'

परमाणु करार में निभाई थी अहम भूमिका : पिछले साल मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु करार से अमेरिका के हटने का एलान किया था। इसके साथ ही ईरान पर कई सख्त प्रतिबंध थोप दिए थे। तभी से दोनों देशों में तनाव चल रहा है। ईरान ने साल 2015 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और जर्मनी के साथ परमाणु करार किया था। इस करार में जरीफ ने अहम भूमिका निभाई थी।

ईरान के इन कृत्यों से बढ़ी तनातनी : अमेरिका ने ईरानी खतरे से निपटने के लिए पश्चिमी एशिया में विमानवाहक पोत और बमवर्षक विमान तैनात कर रखे हैं। हाल के महीनों में कई तेल टैंकरों पर हुए हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया था। ईरान ने गत जून में अमेरिका के एक निगरानी ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले तक का आदेश दे दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में वह इससे पीछे हट गए थे। ईरान ने परमाणु करार का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम संवर्धन भी तेज कर दिया है।

प्रदर्शनकारियों को चीन ने किया आगाह

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग में चीन विरोधी आंदोलन को लेकर प्रदर्शकारियों को आगाह करते हुए चीन ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीनी सेना द्वारा विरोधियों के खिलाफ की जाने वाली सैन्य कार्रवाई को दिखाया गया है। सैन्य अभ्यास को दिखाते इस वीडियो को बुधवार को सोशल मीडिया में हांगकांग की छावनी से जारी किया गया।

तीन मिनट के इस वीडियो में सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर से दागी जा रही गोलियां, रॉकेट लांचर और अन्य सैन्य हथियारों को दर्शाया गया है। इसमें दंगे से निपटते सैनिकों को दिखाया गया है, जिसमें हेलमेट पहने चीन की सेना डंडे लिए विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में लगी है। एक सैनिक लाल झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है जिसपर लिखा है- रुक जाओ वरना सेना बल प्रयोग करेगी। वीडियो के अंत में हाथ बंधे प्रदर्शनकारियों को हिरासत केंद्र की ओर ले जाते दिखाया गया है। वीडियो में हांगकांग में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई है। यह वीडियो उस दिन जारी किया गया है जिस दिन दर्जनों प्रदर्शनकारियों को दंगा फैलाने के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया।

पीएलए डे पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बैठक

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं के बीच सिक्किम के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) से सटे नाथुला में विशेष बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (बीपीएम) हुई। एएनआइ

जागरण संवाददाता, कोलकाता : चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 92वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं के बीच सिक्किम के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) से सटे नाथुला, दमाई और बुमला में विशेष बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (बीपीएम) हुई। पीएलए के निमंत्रण पर भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कई अधिकारी और सैनिक शामिल थे, स्थापना दिवस पर एलएसी के साथ विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों व समारोहों में हिस्सा लिया। पूर्वी सेना कमान की ओर से एक बयान में बताया गया है कि पीएलए के सैनिकों ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सद्भावना के तौर पर भारतीय पक्ष की ओर से भी इस अवसर पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

पाक की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने मरयम नवाज से की पूछताछ

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएन-एन) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज से पूछताछ की। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 45 वर्षीय बेटी मरयम से यह पूछताछ बुधवार को ठोकर नियाज बेग स्थित एनएबी के दफ्तर में की गई।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, एनएबी ने मरयम से चौधरी चीनी मिल के साथ अरबों रुपये के लेन-देन के बारे में जानकारी मांगी। इस चीनी मिल में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा मरयम की भी हिस्सेदारी है। मरयम ने अपने जवाब में बताया कि इस बारे में सारी जानकारी पनामा पेपर लीक मामले की छानबीन करने वाली संयुक्त जांच टीम को उपलब्ध करा दी गई थी। मरयम से इस कंपनी के विदेशी हिस्सेदारों के बारे में भी पूछा गया था। एनएबी ने मरयम को मामले में पूरी जानकारी के साथ आठ अगस्त को फिर उपस्थित रहने को कहा है। एनएबी के दफ्तर से लौटने के बाद मरयम ने एक ट्वीट में कहा कि यह सुनियोजित तरीके से उन्हें और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश है।

मरयम नवाज। फाइल

चीन में ऐतिहासिक टीवी कार्यक्रमों पर रोक

बीजिंग, रायटर : चीन में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग रेग्यूलेटर अथॉरिटी ने ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े धारावाहिक व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसके स्थान पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम दिखाने के लिए कहा गया है। सरकार नियंत्रित अथॉरिटी ने यह कदम चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के 70 साल पूरे होने के मौके पर माहौल बनाने के लिए किया है। एक अक्टूबर 2018 से लागू समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों सेंसरशिप को धीरे-धीरे कर कड़ा किया गया है। रेग्यूलेटर अथॉरिटी ने 86 कार्यक्रमों की सूची देकर उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। ये सभी चीन की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित थे जिनमें लोग संघर्ष करते हुए सफल होते दिखाई गए थे। इनमें स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आमजन संघर्ष करते दिखाई गए थे।

रेस्तरां से इस्लामी चिह्न और अरबी में लिखे शब्द हटवाए

बीजिंग, रायटर : चीन की राजधानी बीजिंग में प्रशासन ने सभी हलाल रेस्तरांओं को अरबी भाषा में लिखे अल्फाज और मुस्लिम प्रतीक चिह्न हटाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का तर्क है कि उसका यह कदम देश की मुस्लिम आबादी को मुख्यधारा से जोड़ेगा।

बीजिंग में 11 रेस्तरांओं हलाल मांस के उत्पाद बेचते हैं। वहां जाने पर पता चला कि सभी रेस्तरांओं से इस्लाम के प्रतीक चिह्न हटा दिए गए हैं और अरबी भाषा में लिखे अल्फाज दीवारों व साइन बोर्डों से मिटा दिए गए हैं। पता चला कि ऐसा लोक प्रशासन के अधिकारियों के आदेश पर किया गया। इनके स्थान पर बोर्ड में चीनी भाषा में उत्पाद के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। लेकिन उसमें भी कहीं इस्लाम धर्म का भाव प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। नूडल्स में हलाल मांस का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां में तो सरकारी अधिकारियों ने खड़े होकर प्रतीक चिह्नों और अरबी में लिखी बातों को हटवाया। उन्होंने रेस्तरां के मैनेजर से कहा, विदेशी संस्कृति नहीं चीनी संस्कृति से जुड़ी बातें लिखें और प्रदर्शित करें।

चीन में चीनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का अभियान सन 2016 से चल रहा है। इसके तहत कई मस्जिदों से खाड़ी के देशों में बनी मस्जिदों जैसे गुंबद हटवाए गए। मस्जिद प्रबंधन को चीनी पैगोडा में बनी छतों के आकार का निर्माण करने के लिए कहा गया। चीन में करीब दो करोड़ मुस्लिम हैं। कहने को उन्हें धार्मिक आजादी है लेकिन उन्हें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के अनुसार दिखावा किए बगैर धार्मिक गतिविधियां अंजाम देनी हैं।

यमन में सैन्य परेड पर मिसाइल हमले में 32 लोगों की मौत

अदन, रायटर/एपी : यमन के अदन शहर में गुरुवार को हाउती विद्रोहियों ने एक सैन्य परेड पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 32 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों का राजधानी सना समेत यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना 2015 से उससे मुकाबला कर रही है। अदन में सऊदी समर्थित सरकार का नियंत्रण है।

अधिकारियों के अनुसार, मिसाइल उस समय गिरी जब सैन्य परेड चल रही थी। यह परेड अदन के समीप ब्रेका शहर में निकाली गई थी। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि हमले में कितने सैनिकों की मौत हुई है लेकिन इतना जरूर कहा कि मृतकों में कई कमांडर शामिल हैं। हाउती विद्रोहियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरिया ने कहा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल से संयुक्त अरब अमीरात के प्रति वफादारी रखने वाले बलों को निशाना बनाया गया। यमन के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को अदन में एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन में विस्फोटकों से भरी एक कार से धमाका किया गया।

एक और भारतीय जासूस पकड़ने का पाकिस्तान ने किया दावा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पुलिस ने डेरा गाजी खान कस्बे में एक 'भारतीय जासूस' को पकड़ने का दावा किया है। उसने कथित रूप से राजू लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को तफ्तीश के लिए अपनी खुफिया एजेंसी के हवाले करने की भी बात कही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि यह रिपोर्ट अप्रमाणिक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा है कि अप्रमाणिक मीडिया रिपोर्ट पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हमें पाकिस्तान की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

पाकिस्तानी मीडिया ने विगत बुधवार को दावा किया था कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने लाहौर से 400 किमी दूर डेरा गाजी खान कस्बे में एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने उसकी पहचान राजू लक्ष्मण के नाम से बताई है। लक्ष्मण को आगे की जांच के लिए किसी अज्ञात स्थान पर भेजा गया है। पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी लियाकत लेघारी ने कहा कि 30 वर्षीय राजू को सीमा पर तैनात मिलेट्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले पाकिस्तानी पुलिस ने दावा किया था कि लक्ष्मण को बलुचिस्तान प्रांत से कस्बे में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान वही प्रांत है पाकिस्तान जहां से कुलभूषण जाधव को भी गिरफ्तार करने का दावा करता रहा है।

कांग्रेस ने कहा, पाक के झूठे प्रचार को रोके सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) की मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर भारत को बदनाम करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर चिंता जताई है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान इस बेबुनियाद और झूठी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में भारत की छवि खराब करने का घिनौना प्रयास कर रहा है। इसलिए, सरकार को पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तिवारी ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियों पर हाल में दो रिपोर्ट जारी की है। इन दोनों रिपोर्ट को अज्ञात स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है और इनमें पाकिस्तान की तरफ से भारत में फैलाए जाने वाले आतंकवाद को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। दोनों रिपोर्ट में भारत के नजरिये को भी शामिल नहीं किया गया है। जबकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ दुष्प्रचार के लिए इन रिपोर्टों का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस नेता ने सरकार से कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत को वह गंभीरता से ले, क्योंकि भले ही हम देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की रिपोर्ट को खारिज कर दें, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में इसे गंभीरता से पढ़ा जाता है।

पैराग्लाइडिंग हादसे में यूट्यूब स्टार ग्रांट थांपसन की मौत

लॉस एंजिलिस, एएफपी : यूट्यूब पर अपने लोकप्रिय चैनल 'द किंग ऑफ रैंडम' से मशहूर अमेरिकी ग्रांट थांपसन की एक पैराग्लाइडिंग हादसे में मौत हो गई। 38 वर्षीय ग्रांट बीते सोमवार को अमेरिका के उटाह में पैराग्लाइडिंग ट्रिप पर गए थे, जहां वह हादसे का शिकार हो गए। ग्रांट के यूट्यूब पर एक करोड़ दस लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

चैनल पर डाले गए उनके वीडियो को अरबों बार देखा जा चुका है। वाशिंगटन काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि बचाव दल ने दुर्घटनाग्रस्त पैराग्लाइडर को ढूंढ़ निकाला है। उसमें मौजूद वीडियो रिकार्डिंग उपकरण के जरिये दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है। शरीर पर लगे जीपीएस डिवाइस की मदद से ग्रांट थांपसन के शव का पता चला। ग्रांट की मौत की खबर से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। यूट्यूब के जरिये प्रसिद्धि पाने से पहले वह 11 वर्षों तक पायलट की नौकरी कर चुके थे।

ओबामा ने बनवाए थे शरणार्थी बच्चों के लिए हिरासत केंद्र

- विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं के निशाने पर आए राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया जवाब

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका में शरणार्थियों का मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। शरणार्थियों के खिलाफ अपनी सख्त नीति को लेकर विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं के निशाने पर आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस समस्या के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट किया, 'ओबामा प्रशासन ने 2014 में बच्चों के लिए हिरासत केंद्र बनाए थे। बच्चों को मां-बाप से अलग रखने की नीति की शुरुआत उन्होंने ही की थी। हालात सुधरते नहीं देख मैंने इसे खत्म कर दिया।' उल्लेखनीय है कि भारी विरोध के कारण ही राष्ट्रपति ट्रंप ने शरणार्थी बच्चों को उनके मां-बाप से अलग रखने का अपना आदेश वापस लिया था।

अगले साल होने वाले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की होड़ में शामिल सीनेटर कमला हैरिस ने हाल में फ्लोरिडा के एक बाल शरणार्थी हिरासत केंद्र का दौरा किया था। एक अन्य डेमोक्रेट सीनेटर माइकल बेनेट ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को घेरते हुए कहा था कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए ना कि किसी हिरासत केंद्र में। कोर्ट में दाखिल एक दस्तावेज में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन ने 900 से ज्यादा बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप। एपी

अफगानिस्तान की सेना के अधिकारी ने किया आइएमए का दौरा

जागरण संवाददाता, देहरादून : अफगानिस्तान सेना के डिफेंस अटैची (रक्षा से जुड़े) कर्नल करिमुल्लाह करीमी दो दिवसीय दौरे पर भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) पहुंचे हैं। इस दौरे का उद्देश्य अकादमी में प्री-मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेटों से मुलाकात कर उनसे प्रशिक्षण के अनुभव जानना है। यहां पहुंचने पर उन्होंने अकादमी के उप समादेशक व मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल जीएस रावत से भी भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

साथ ही आइएमए में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अफगानिस्तान के कैडेटों से मुलाकात की। अकादमी के उप समादेशक मेजर जनरल रावत से भी उन्होंने भारत व अफगानिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय सेना द्वारा अफगानिस्तान को मिल रहे सकारात्मक मिलिट्री व प्रशासनिक सहयोग पर भी उन्होंने सेना व अकादमी का धन्यवाद किया। यह उम्मीद जताई कि दोनों देशों के सामरिक संबंध आने वाले समय में और बेहतर होंगे।

गुलाम कश्मीर के जमीनी हालात बदलने में जुटा पाक

- कब्जा बरकरार रखने को जम्मू-कश्मीर के हिस्से की पहचान
- सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनसांख्यिकी में बदलाव करने का लगाया आरोप

वाशिंगटन, एएनआइ : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर इलाके की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में बदलाव करने का आरोप लगाया है। कहा है कि इसके जरिये पाकिस्तान इलाके के मूलवासियों की आवाज और अपेक्षाओं को दबाना चाहता है। ऐसा वह इलाके पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कर रहा है। इन लोगों ने गुलाम कश्मीर को जम्मू-कश्मीर का अविभाज्य अंग बताया है।

इंस्टीट्यूट फॉर गिलगित बाल्टिस्तान स्टडीज, वाशिंगटन में कार्यरत सेंग एच. सेरिंग ने कहा, पाकिस्तान कानूनी मान्यताओं को उल्लंघन कर कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में बाहरी लोगों को बसा रहा है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर जमीन के बाहरी लोगों अवैध रूप से पट्टे दे रहा है। चीन को भी इलाके का एक हिस्सा दे दिया गया है। यह स्टेट सबजेक्ट रूल गिलगित-बाल्टिस्तान का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। यहां पर आकर किसी भी प्रांत के पाकिस्तानी अब जमीन खरीद सकते हैं और बस सकते हैं। पाकिस्तान धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर के इस हिस्से की पहचान खत्म करता जा रहा है। वह वहां पर अतिक्रमण कर इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर आमादा है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के केंद्रीय सचिव जामिल मकसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले जम्मू-कश्मीर पर कब्जा किया। इसके बाद वहां पर कब्जा कायम करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया। अब वहां रहने वाले कश्मीरी नागरिक पाकिस्तान की अंतहीन तानाशाही वाला शासन झेलने को मजबूर हैं जिसमें उसकी सेना की सबसे बड़ी भूमिका है।

यूएई अगले साल जुलाई में मंगल पर भेजेगा अंतरिक्ष यान

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अगले साल जुलाई में मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। 'होप प्रोब' नाम का यह यान मंगल पर भेजा जाने वाला अरब जगत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। इस अंतरिक्ष अभियान का नाम अमीरात मंगल मिशन (ईएमएम) रखा गया है। इसमें मंगल के वातावरण के विभिन्न स्तरों से लेकर इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि लाल ग्रह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म होने के क्या कारण रहे। यूएई के इस यान को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लांच किया जाएगा। यान के 2021 की पहली तिमाही में मंगल पर पहुंचने की संभावना जताई गई है।

यूएई स्पेस एजेंसी (यूएईएसए) और मुहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर (एमबीआरएससी) ने कहा है कि अगर यह मिशन सफल रहा तो यह मंगल के वातावरण की तस्वीरें लेने वाला पहला यान होगा। यूएईएसए के अध्यक्ष अहमद बेलहौल अल फलासी ने कहा है कि इस मिशन की सफलता अरब और इस्लामिक जगत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

मैं बांग्लादेश के खिलाफ टीम के शानदार प्रदर्शन से काफी खुश हूं। हम आगामी मैचों में भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
— दिमुथ करुणारत्ने, कप्तान, श्रीलंका

कुछ महीने मेरे लिए मुश्किल रहे : ओसाका

न्यूयॉर्क, एएफपी : पूर्व विश्व नंबर एक जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने कहा है कि पिछले कुछ महीने उनके लिए काफी मुश्किल रहे हैं। 21 वर्षीय ओसाका 26 अगस्त से शुरू होने जा रहे अमेरिकी ओपन में अपना खिताब बचाने उतरेंगी। इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ओसाका ने कहा कि इस जीत के बाद से उनके लिए टेनिस खेलना आसान नहीं रहा है।

एशेज ▸ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव ने खेली 144 रनों की पारी, कंगारू टीम ने बनाए 284 रन

स्मिथ ने शतक से की वापसी

16 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं स्मिथ, ब्रॉड को मिले पांच विकेट

मैच के दौरान विकेट चटकाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड। एएफपी

बर्मिंघम, प्रेट्र : 16 महीने पहले जिस समय स्मिथ ने गेंद से छेड़छाड़ के प्रकरण की बात प्रेस वार्ता में कबूली थी और उस दौरान वह फूट-फूटकर रो पड़े थे। उसके बाद शायद उन्होंने यह बात ठान ली थी कि वह अपनी वापसी को भी यादगार बनाएंगे। यह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को एशेज के पहले टेस्ट के पहले दिन साबित भी कर दिया। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स जब अपनी कहर बरपाती गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेज रहे थे तो उसी दौरान स्मिथ का उनकी गेंदबाजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैच के खत्म होने के बाद जहां इंग्लिश प्रशंसक उनकी हूटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक अपने स्टार बल्लेबाज का तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के कारण स्मिथ के साथ डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट पर प्रतिबंध लग गया था और इन तीनों ने इस टेस्ट के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की।

हालांकि, वार्नर और बेनक्राफ्ट की वापसी तो खास नहीं रही लेकिन स्मिथ ने शतक जड़कर अपनी वापसी का शानदार जश्न मनाया। दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एजबेस्टन में मौजूद सभी को जवाब भी दे दिया। उन्होंने दिखा दिया सफेद जर्सी और लाल गेंद वाले इस खेल में वह टीम के कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। उनकी 144 रनों की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 284 रनों तक पहुंच गई। स्मिथ ने अपनी पारी में 219 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 16 चौके और दो छक्के जड़े। उन्होंने नौवें विकेट के लिए पीटर सिडल (44) के साथ 88 रन और 10वें विकेट के लिए नाथन लियोन (नाबाद 12) के साथ 74 रन जोड़कर टीम को मैच में लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने करियर का 24वां टेस्ट शतक जड़ा। इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड (5/86) ने सर्वाधिक विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक दो ओवर में बिना विकेट गंवाए 10 रन बना लिए थे। रॉरी बर्न्स (04) और जेसन रॉय (06) क्रीज पर डटे हैं। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 274 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला इंग्लिश गेंदबाजों ने गलत साबित कर दिया। ब्रॉड ने वार्नर (02) को एलबीडब्ल्यू आउट करके टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाया। इसके बाद ब्रॉड ने कैमरन बेनक्राफ्ट (08) को रूट के हाथों कैच आउट कराकर टीम को दूसरी सफलता दिलाई। दोनों बल्लेबाजों की वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही।

एंडरसन ने बीच में छोड़ा मैदान

बर्मिंघम : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान बीच में ही मैदान को छोड़कर पवेलियन चले गए। एंडरसन को पिंडली में कुछ परेशानी थी जिसका स्कैन कराने के लिए उन्हें एजबेस्टन मैदान छोड़ना पड़ा। 37 वर्षीय एंडरसन को पिंडली में चोट थी, लेकिन उन्होंने बुधवार को फिटनेस टेस्ट पास किया था, जिसके बाद उन्हें अंतिम एकादश में जगह मिली। इस दौरान एंडरसन ने सिर्फ चार ओवर फेंके, लेकिन उन्हें विकेट हासिल नहीं हुआ।

वार्नर की हूटिंग

बर्मिंघम : ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इंग्लैंड के खिलाफ आउट होने के बाद पवेलियन लौट रहे थे तब इंग्लिश प्रशंसकों ने इस बायें हाथ के बल्लेबाज को सैंड पेपर दिखाकर उनकी हूटिंग की। पहले टेस्ट मैच के दौरान वार्नर पहली पारी के चौथे ओवर में केवल दो रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार बने। इंग्लैंड क्रिकेट के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें कुछ प्रशंसक सैंड पेपर दिखाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट को पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था। इसके कारण वार्नर और स्मिथ पर एक-एक साल के लिए जबकि बेनक्राफ्ट पर नौ महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीनों की अब टेस्ट क्रिकेट टीम में वापसी हुई है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी हुआ आगाज

बर्मिंघम : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैड के बीच गुरुवार से एशेज सीरीज शुरू हो गई और जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे, वैसे ही आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी आगाज हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आसीसी) ने टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए इस प्रारूप में बदलाव किए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दो साल तक चलेगी जिसके बाद विश्व को सबसे लंबे वाले प्रारूप टेस्ट का विश्व चैंपियन मिलेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में आइसीसी की रैंकिंग की शीर्ष-नौ टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान कुल 27 सीरीज खेली जाएंगी, जिसमें 71 मैच होंगे। टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता जून 2021 में ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर मिलेगा।

टेस्ट में पहली बार खिलाड़ियों ने पहनी नंबर वाली जर्सी

बर्मिंघम : एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का एक नया अध्याय भी शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से टेस्ट क्रिकेट का नया रूप दुनिया के सामने आया जब दोनों टीमों के खिलाड़ी इस प्रारूप में पहली बार नंबर वाली जर्सी पहनकर उतरे। आइसीसी ने टेस्ट को रोमांचक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे खिलाड़ी नंबर वाली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। यानी जिस जेंटलमैन गेम की शुरुआत सफेद पैंट-शर्ट से हुई थी और वो अब कुछ हद तक रंगीन टी-शर्ट की तरफ पहुंच रहा है। हालांकि, अभी सफेद कपड़ों पर रंगीन नंबर और नाम ही हैं।

भारत का अगला कोच चुनने को लेकर दबाव नहीं : कपिल

खेल संवाददाता, कोलकाता

आयोजन

▸ ईस्ट बंगाल के 100 साल पूरे होने के मौके पर बोले देव

▸ कहा, दबाव में वे होते हैं जो जिम्मेदारी से घबराते हैं

एक कार्यक्रम के दौरान कपिल देव। एएनआइ

भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने कहा कि टीम इंडिया का अगला कोच चुनने को लेकर वह किसी तरह के दबाव में नहीं हैं।

ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करने कोलकाता आए कपिल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैं नए कोच के चयन को लेकर किसी तरह के दबाव में नहीं हूं। दबाव में वे लोग होते हैं, जो दी जाने वाली जिम्मेदारी निभाने से घबराते हैं।' मालूम हो कि टीम इंडिया के अगले कोच का चयन कपिल की अगुआई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति करेगी। क्रिकेट और फुटबॉल की तुलना को लेकर पूछे गए सवाल पर कपिल ने बेबाकी से अपने एक हाथ को ऊपर व दूसरे को नीचे दिखाते हुए कहा कि दोनों में यही अंतर है। फुटबॉल दुनिया का हरेक देश खेलता है, जबकि क्रिकेट 12, 14 अथवा 15 देश ही खेलते हैं। फुटबॉल बड़ा एथलीट बनने के लिए धार प्रदान करता है। यही वजह है कि क्रिकेटर भी अभ्यास सत्र में फुटबॉल खेलते हैं। खिलाड़ियों के लिए फिटनेस बेहद जरूरी है। पेले और डिएगो मेराडोना पर उन्होंने कहा, 'मेरे पसंदीदा फुटबॉलर तो मेराडोना ही हैं। वह भले सर्वश्रेष्ठ रनर नहीं थे, लेकिन जब बॉल उनके पैरों में आती थी, उस वक्त दुनिया में उनसे तेज कोई नहीं होता था।' ईस्ट बंगाल के लिए दशकों पहले खेले प्रदर्शनी मैच को याद करते हुए 'हरियाणा हरिकेन' के नाम से मशहूर कपिल ने कहा, 'क्लब फुटबॉल में खेल नहीं, बल्कि क्लब को लेकर दीवानगी देखने को मिलती है। इससे समर्थकों की क्लब के प्रति विश्वसनीयता का पता चलता है।'

ईस्ट बंगाल ने कपिल देव को 'भारत गौरव सम्मान' से नवाजा

खेल संवाददाता, कोलकाता : ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने अपने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को 'भारत गौरव सम्मान' से सम्मानित किया। गुरुवार को यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए क्लब के शताब्दी समारोह में कपिल को राज्य के खेल मंत्री अरूप राय ने सम्मानित किया। मालूम हो कि कपिल ने जून, 1992 में ईस्ट बंगाल क्लब की तरफ से एक प्रदर्शनी मैच खेला था। क्लब की ओर से भारतीय फुटबाल के दिग्गज पीके बनर्जी को सदी के सर्वश्रेष्ठ कोच के सम्मान से नवाजा गया। पूर्व फुटबॉलर मनोरंजन भट्टाचार्य और भास्कर को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया।

अमलराज के साथ मेरी जोड़ी मेल खाती है : चिंग

ताइवान की चेंग आइ-चिंग अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) में सर्वोच्च रैंकिंग वाली खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी गोवा चैलेंजर्स की स्टार **चेंग आइ चिंग से विकास पांडेय** ने यूटीटी में दिल्ली दबंग के खिलाफ होने वाले आगामी मुकाबले को लेकर विशेष बात की। पेश हैं उस बातचीत के प्रमुख अंश :-

साक्षात्कार

● **पहले मैच में जीत के बाद आपकी टीम को चेन्नई लायंस के खिलाफ 7-8 से हार मिली। इस हार को आप कैसे देखती हैं?**

-वास्तव में इस तरह के मुकाबले में हारना बहुत निराशाजनक है। यह एक करीबी मुकाबला था। दिन के आखिरी मैच में मुकाबले को जीतने के लिए तीन अंक चाहिए थे। अर्चना कामत ने बहुत ही बहादुरी वाला खेल दिखाया और हमें जीत के इतने करीब ले गईं। लेकिन मधुरिका ने भी निर्णायक समय पर दबाव की स्थिति में अच्छा खेल दिखाया और टीम के लिए अहम अंक हासिल किए। इस हार से हम निराश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्कोर लाइन बुरी नहीं थी और इसमें जीते हुए अंक हमें आगे ले जाने में मदद करेंगे।

● **आपने अपना सिंगल्स मुकाबला जीता और एंथोनी अमलराज के साथ जोड़ी बनाकर आपने अहम अंक जुटाए। उनके के साथ अपनी जोड़ी को लेकर आप क्या कहेंगी?**

-हम पूरी तरह से एक नई जोड़ी के रूप में खेल रहे हैं और एक सच्चाई यह भी है कि मैं पहली बार किसी विदेशी खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर खेल रही हूं। एंथोनी अमलराज एक बहुत दमदार एथलीट और शानदार पैडलर हैं और हमारी जोड़ी बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। यह हमारे प्रदर्शन में भी दिखा।

● **दबंग दिल्ली ने पिछले मुकाबले में एक बड़ी जीत दर्ज की थी जिसके साथ आपका अगला मुकाबला है। इस मुकाबले को गोवा कैसे देख रहा है?**

-निसंदेह यह बहुत मुश्किल मैच होगा। हमें उन्हें हराने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते।

● **दबंग दिल्ली के पास जी साथियान, जॉन पर्सन और बेर्नाडेट स्जोक्स में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को आपके द्वारा रोकने की कैसी रणनीति होगी?**

-हमें उन्हें हराने के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। मेरे साथी और मैं बहुत आश्वस्त हैं कि हम शानदार खेल दिखाएंगे और उन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे जो हमें खेलते देखने आते हैं।

● **शुक्रवार को होने वाले मैच में आप बर्नाडेट या कृत्विका सिन्हा रॉय के खिलाफ उतरेंगी। आप उनकी खेलने की शैली के बारे में कितना जानती हैं ?**

-मैंने उन्हें खेलते हुए देखा है और साथ ही मैंने सपोर्ट स्टाफ से उनके खेलने के तरीके के बारे में जानकारी ली है। मैंने उनके खिलाफ अपनी रणनीतियां भी बना रखी हैं। हालांकि मैं अब अपनी रणनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगी।

● **आपकी टीम में शामिल भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के आपसी संबंधों के बारे में कुछ बताइए?**

-हम अलग-अलग जगहों से आते हैं, लेकिन हमारा यही लक्ष्य स्पष्ट होता है कि हम एकजुट होकर गोवा चैलेंजर्स के लिए जीत हासिल करें। लीग के कारण मैं पहली बार भारत आई हूं।

कोच शास्त्री के लिए विराट कोहली ने तोड़ा प्रोटोकॉल

विवाद

▸ सीओए ने बताया, अभिव्यक्ति की आजादी

▸ कहा, कोच की नियुक्ति सीएसी ही करेगी

विराट कोहली। फाइल फोटो, प्रेट्र

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच को लेकर जब आवेदन मांगे गए थे तब प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने साफ कहा था कि इस प्रक्रिया में कप्तान की भूमिका नहीं होगी। दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने कोच पद के लिए अपनी पसंद को खुलेआम जाहिर कर दिया था और रवि शास्त्री का समर्थन किया। कोहली के अपनी पसंद के साफ इजहार के बाद सीओए ने कहा है कि कप्तान एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है।

सीओए के एक सदस्य ने कहा कि कोहली लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और उन्हें बोलने से नहीं रोका जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या कप्तान का शास्त्री के साथ अपने संबंधों के बारे में बात करना तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के लिए एक तरह का इशारा है? इस पर सीओए सदस्य ने कहा कि ऐसा नहीं है। सदस्य ने कहा, 'यह उनका विचार है और उन्होंने इसे जाहिर किया है। यह लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम किसी को कुछ भी कहने से नहीं रोक सकते। क्यों हर व्यक्ति का हर शब्द मायने रखता है? वह टीम के कप्तान हो सकते हैं, लेकिन सीएसी भी है और कोच की नियुक्ति को लेकर फैसला उसे लेना है। करोड़ों लोग इस देश में रह रहे हैं और आप हर किसी को उसकी बात रखने से नहीं रोक सकते। यह देखना होगा कि सीएसी कोहली के बयान को किस तरह से लेती है। हर किसी का चीजें करने का अपना एक तरीका होता है।'

दिलचस्प बात यह है कि तब दूसरे खिलाड़ियों की बात आती है तो उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। यही बात बीसीसीआइ के अधिकारियों पर लागू होती है जिन्हें जवाब देने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत होती है। इससे फिर एक बार सवाल पैदा होता है कि क्या अलग लोगों के लिए अलग नियम हैं। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावसकर ने हाल में कहा था कि किस तरह राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अपने कदम कई बार पीछे लेने पड़ते हैं।

गावसकर ने कहा था, 'चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज के लिए टीम चुन ली, बिना कप्तान के बारे में चर्चा किए। इससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोहली अपनी मर्जी से कप्तान हैं या चयनकर्ताओं की मर्जी से। दोबारा कप्तान नियुक्त किए जाने तक वह टीम चयन की बैठक में भी बुलाए जाते हैं। केदार जाधव और दिनेश कार्तिक को खराब प्रदर्शन करने के कारण टीम से बाहर कर दिया जाता है और इससे एक संदेश दिया जाता है, लेकिन कप्तान उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद भी अपने पद पर हैं।'

इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी टीम चयन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अब समय आ गया है जब चयनकर्ताओं को सभी प्रारूपों के लिए एक जैसी टीम चुननी चाहिए।

कोहली को अपनी राय रखने का हक : रंगास्वामी

नई दिल्ली, प्रेट्र : शांता रंगास्वामी ने गुरुवार को कहा कि कप्तान के रूप में विराट कोहली को अपनी राय देने का हक है, लेकिन भारतीय टीम के अगले मुख्य कोच का चयन तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) की सामूहिक राय के आधार पर होगा, जिसकी वह खुद भी एक सदस्य हैं। सीएसी के अन्य सदस्य कपिल देव और अंशुमन गायकवाड़ हैं। इसी समिति ने दिसंबर में भारतीय महिला टीम के कोच का चयन भी किया था। भारतीय टीम के अमेरिका रवाना होने से पहले कोहली ने कहा था कि यदि रवि शास्त्री को वेस्टइंडीज दौरे के बाद भी पद पर बरकरार रखा जाता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रंगास्वामी ने कहा, 'विराट कप्तान हैं और उन्हें अपनी राय देने का हक है, लेकिन यह हम तीनों (सीएसी) की सामूहिक राय से होगा, जिससे यह तय होगा कि अगला मुख्य कोच कौन होगा। मैंने ने कुछ मीडिया रिपोर्ट पढ़ी हैं और मैं इस मुद्दे पर अंशुमन का समर्थन करती हूं। हमें सभी पहलुओं को देखने की जरूरत है, उसका अनुभव, टीम को एकजुट रखने की क्षमता और यह देखना कि वह कितना अच्छा रणनीतिकार है।'

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज काफी रोमांचक होगी : रीफर

फ्लॉयड रीफर। ट्विटर

फोर्ट लॉडरडेल (फ्लोरिडा), प्रेट्र : वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कोच फ्लॉयड रीफर को यकीन है कि कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन की वापसी से भारत के खिलाफ टी-20 मैचों की सीरीज काफी रोमांचक होगी।

वेस्टइंडीज की टी-20 टीम हालात के अनुकूल ढलने के लिए फ्लोरिडा पहुंच गई है। रीफर ने इसे युवा और अनुभवी टीम का अच्छा मिश्रण बताया है। रीफर ने कहा, 'यह टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। यह काफी रोमांचक सप्ताहंत होगा जिसमें दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। हमारे पास पोलार्ड और नरेन जैसे खिलाड़ी फिर टीम में हैं। उनके साथ कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट भी हैं जिनके पास इस प्रारूप का काफी अनुभव है। हमारे पास खारे पियरे के रूप में युवा स्पिनर है जो पिछले साल भारत में खेला था। वह अच्छा फील्डर भी है। एंथोनी ब्रेंबल शानदार प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं और गयाना के लिए उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वह अब इस स्तर पर अपने फन का लोहा मनवाने को बेताब है।'

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टी-20 मैच शनिवार को फ्लोरिडा में खेला जाएगा।

साइना-श्रीकांत बाहर, प्रणीत जीते

थाइलैंड ओपन

▸ दूसरे दौर में नेहवाल और किदांबी को मिली अप्रत्याशित हार

▸ साई प्रणीत ने हमवतन शुभंकर डे को हरा अंतिम-आठ में बनाई जगह

बैंकॉक, प्रेट्र : दिग्गज भारतीय शटलर साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत को गुरुवार को थाइलैंड ओपन में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बी साई प्रणीत ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

इस हार के साथ ही सातवीं वरीय साइना का कोर्ट पर वापसी का सफर बहुत जल्दी समाप्त हो गया, जो इस टूर्नामेंट के जरिये करीब दो महीने बाद वापसी कर रही थीं। वह एक गेम की बढ़त का फायदा उठाने में विफल रहीं और 48 मिनट तक चले महिला सिंगल्स के दूसरे दौर के मुकाबले में जापान की गैर वरीय सयाका ताकाहाशी से 21-16, 11-21, 14-21 से हार गईं। पीवी सिंधू की अनुपस्थिति में साइना के हारने से भारत का इस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में अभियान समाप्त हो गया। साइना ने चोट के कारण इंडोनेशिया ओपन और जापान ओपन से हटने का फैसला किया था।

इसके बाद पांचवीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने भी एक गेम की बढ़त गंवा दी और उन्हें पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में थाइलैंड के खोसित फेतप्रदाब से 21-11, 16-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, गैर वरीयता प्राप्त पी कश्यप तीसरी वरीय चीनी ताइपे के चोऊ टिएन चेन की चुनौती का सामना नहीं कर पाए। भारतीय शटलर को महज 33 मिनट में 9-21, 14-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, पिछले सप्ताह जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले साई प्रणीत ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए हमवतन शुभंकर डे पर 21-18, 21-19 से आसान जीत दर्ज की और अंतिम-आठ में अपना स्थान पक्का किया। अब साई प्रणीत का सामना अगले दौर में जापान के सातवीं वरीय कांता सुनेयामा से होगा।

भारत के लिए पुरुष डबल्स स्पर्धा में अच्छी खबर रही, जहां सत्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फजर अलफियां और मुहम्मद रियान आर्दियांतो की इंडोनेशियाई जोड़ी पर सीधे गेम में 21-17, 21-19 से जीत दर्ज की। अब भारतीय जोड़ी का सामना शुक्रवार को कोरिया के चोई सोलग्यू और सियो सेयूंग जाए की क्वालीफायर जोड़ी से होगा। मिक्स्ड डबल्स में भी भारत के लिए गुरुवार का दिन काफी निराशाजनक रहा, जहां प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी हांगकांग के टांग चुन मान और से यिंग सुएत की आठवीं वरीय जोड़ी से 16-21, 11-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

फुटबॉल डायरी

लिवरपूल की जीत में विल्सन ने बिखेरी चमक

दोस्ताना मुकाबले में ल्योन को 3-1 से हराया, हैरी विल्सन ने 25 गज की दूरी से दागा शानदार गोल

गोल करने के बाद लिवरपूल के खिलाड़ी हैरी विल्सन (दायें)। एएफपी

पेरिस, एएफपी : इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने एक दोस्ताना मुकाबले में फ्रेंच क्लब ल्योन को 3-1 से हरा दिया। लिवरपूल की इस जीत में वेल्स के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैरी विल्सन ने एक बेहतरीन गोल करके लिवरपूल के मैनेजर जुर्जेन क्लोप को अपनी प्रतिभा की शानदार झलक दिखाई।

पिछले सत्र में लोन पर क्लब से बाहर रहने वाले विल्सन ने खेल के 53वें मिनट में 25 गज की दूरी से एक शानदार गोल किया। इससे पहले लिवरपूल के ब्राजीली स्ट्राइकर रॉबर्टो फर्मिनो (17वें मिनट) ने गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलाई। इसके बाद ल्योन के जोकिम एंडरसन (21वें मिनट) के आत्मघाती गोल की बदौलत लिवरपूल ने पहले हाफ में बढ़त बना ली। वहीं, ल्योन की ओर से मेंफिस डिपे ने खेल के चौथे मिनट में इकलौता गोल दागा, लेकिन उस शुरुआती बढ़त को उनकी टीम भुना नहीं पाई।

यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल का यह आखिरी अभ्यास मुकाबला था जिसे इस सप्ताह के अंत में वेंबले में कम्यूनिटी शील्ड में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ सत्र की शुरुआत करनी है। इस मुकाबले के जरिये लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मुहम्मद सलाह ने भी अपने क्लब में वापसी की, जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने में व्यस्त थे।

पेद्रो का यादगार गोल : एक अन्य दोस्ताना मुकाबले में चेल्सी ने सल्जबर्ग को 5-3 से हरा दिया, जहां पेद्रो ने एक यादगार गोल दागा। रोसी बार्कले के क्रॉस पर पेद्रो ने बैक हिल (एड़ी) से कमाल का गोल करके चेल्सी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा चेल्सी की ओर से क्रिस्टियन पुलिसिक ने दो बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। उधर, आर्सेनल ने फ्रेंच क्लब एंजर्स को पेनाल्टी शूटआउट तक चले एक अन्य मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं।

फेलिक्स के दम पर जीता एटलेटिको : स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने मेजर सॉकर ऑल स्टार टीम को 3-0 से हरा दिया, जहां एटलेटिको के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के युवा सनसनी जोआओ फेलिक्स ने चमक बिखेरी। फेलिक्स ने स्थानापन्न के तौर पर उतरकर एक शानदार गोल दागा। फेलिक्स के अलावा मार्को लॉरेंत और डिएगो कोस्टा ने भी स्कोर किए।

जिदान बोले, हमारा सत्र अच्छा होगा : फ्रेंच स्ट्राइकर करीम बेंजमा की हैट्रिक के दम पर स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड ने बुधवार को एक दोस्ताना मुकाबले में फेनर्बाचे को 5-3 से हरा दिया। प्री सीजन के पांच मुकाबलों में रीयल को 16 गोल खाने पड़े हैं, जो क्लब के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि, रीयल के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने कहा कि हम उपाय ढूंढ लेंगे, हम इस पर काम करेंगे। मैं अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहूंगा और मुझे पता है कि हम में सुधार होगा और हमारा सत्र अच्छा होगा।

बायर्न को हराकर टॉटनहम ने जीता ऑडी कप

म्यूनिख, आइएएनएस : इंग्लिश क्लब टॉटनहम ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को पेनाल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर प्री सीजन टूर्नामेंट ऑडी कप पर कब्जा जमाया। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 की बराबर पर रहा। इस मुकाबले में बायर्न के मैनेजर नाइस कोडाक ने एकदम नई लाइन-अप उतारी, जिसमें केवल एक खिलाड़ी 24 साल की उम्र से ज्यादा (मैनुअल नॉयर 33 साल) का था। इनमें से छह खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनकी उम्र 20 साल या उससे कम थी। घरेलू मैदान एलियांज एरीना में अपने टीम का समर्थन करने पहुंचे बायर्न के समर्थक उस समय हैरान हो गए जब बायर्न की शुरुआती लाइन-अप से रॉबर्टो लेवांदोवोस्की और थॉमस मुलर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम गायब थे। वहीं टॉटनहम के मैनेजर मौरिसियो पोचेटिनो ने हैरी केन, ह्योंग मिन सोन और क्रिस्टियन एरिक्सन को शुरुआती लाइन-अप से बाहर रखा।

पहले दिन भारत-ए के खिलाफ वेस्टइंडीज-ए ने बनाए 243 रन

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : मोंटसिन हॉज और शमारह ब्रुक्स के अर्धशतकों के बावजूद भारत-ए के गेंदबाजों ने दूसरे अनाधिकृत टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज-ए को पांच विकेट पर 243 रनों पर रोक दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज-ए की शुरुआत अच्छी रही। हॉज ने 65, जबकि कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने 119 गेंद में 36 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े। मध्यम तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर ने ब्रेथवेट को 40वें ओवर में आउट करके भारत-ए को पहली सफलता दिलाई। हॉज और ब्रुक्स (53) ने 62 रन की साझेदारी की। भारत-ए के कप्तान हनुमा विहारी ने छह गेंदबाजों को आजमाया, जिनमें से पांच ने विकेट लिए। तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज ने 21 ओवर में 47 रन देकर एक विकेट लिया। शिवम दुबे, कृष्णप्पा गौतम और मयंक मार्कंडेय भी विकेट निकालने में सफल रहे और तीनों गेंदबाजों को एक-एक विकेट हासिल हुआ।

60 लाख रुपये तक पहुंच चुका है भारत-चीन के बीच कारोबार। अभी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। दोनों देशों के बीच सीमा बनाने वाले लिपूलेक दर्रे से यह व्यापार होता है। व्यापार की अवधि 31 अक्टूबर तक निर्धारित है।

बदतर हालात ▶ गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चल रही यात्रा

पाकिस्तान ने सद्भावना यात्रा में शामिल लोगों से सुरक्षा के नाम पर लिए रुपये

पाकिस्तान में गुरुद्वारों की हालत बेहद खराब, लोगों ने किए हैं नाजायज कब्जे

धर्म सिंह, करनाल

कहते हैं मेहमान भगवान होता है। दुश्मन भी घर आए तो उसका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान इन बातों को नहीं मानता। करनाल से गुरुनानक सद्भावना यात्रा में शामिल हुए यात्रियों का पाकिस्तान का अनुभव तो कम से कम ऐसा ही कहता है। दरअसल, वहां पहुंचे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो वाहन उपलब्ध कराए गए, उनके तेल का पैसा यात्रियों से वसूला गया। सुरक्षा दस्ते ने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। यात्रियों की पल-पल की जानकारी कंट्रोल रूम में बैठे सीनियर अधिकारी ले रहे थे। जब भी यात्रियों से कोई मिलता, उसकी पूरी जानकारी ली जाती। वीरवार को गुरुनानक सद्भावना यात्रा करनाल वापस लौट आई। गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में यात्रा संयोजक निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि वहां ज्यादातर गुरुद्वारों में भारतीय सिखों के जाने पर पाबंदी है। पाकिस्तान आने वाले सिखों को कुछ चुनिंदा गुरुद्वारों में ही जाने की इजाजत है। सैकड़ों गुरुद्वारों की हालत बेहद खराब है। नाजायज कब्जे किए हुए हैं, इसलिए वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती।

पाकिस्तानियों को उम्मीद, एक दिन जरूर सुधरेंगे दोनों मुल्कों के हालात : पन्नू ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें खासा सहयोग दिया। हर जगह स्वागत किया गया। वहां के स्थानीय लोग करतारपुर कॉरिडोर को लेकर खासे उत्साहित और उम्मीद में हैं। उनका मानना है कि किसी दिन दोनों मुल्क अच्छे दोस्त बनेंगे और पूरी सरहद खोलकर सभी को एक-दूसरे से मिलने और व्यापार करने की छूट मिलेगी।

चार चरणों में चलेगी सद्भावना यात्रा : गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आपसी भाईचारे व शांति की कामना के साथ चार चरणों में गुरुनानक सद्भावना यात्रा की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। यात्रा का प्रथम चरण संपन्न हो गया है। पहले चरण में यात्रियों ने पाकिस्तान में पांच दिन बीताए। यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत एक सितंबर को होगी जो 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसी तरह तीसरे चरण की शुरुआत 10 अक्टूबर तो चौथे चरण की शुरुआत तीन नवंबर को की जाएगी जो 12 नवंबर को संपन्न होगी। चारों चरणों में 40 हजार मील की दूरी तय कर 100 शहरों को कवर किया जाएगा और 55 हजार पौधे रोपे जाएंगे।

गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान से निकाले गए नगर कीर्तन का वाघा बॉर्डर जीरो लाइन से भारत में प्रवेश करने के बाद स्वागत करते सुखबीर सिंह बादल और अन्य। राघव शिकारपुरिया

साथ में लाए पवित्र स्थलों की मिट्टी

प्रथम चरण में यात्रा जहां-जहां भी पवित्र स्थानों पर पहुंची, वहां की कुछ मिट्टी एकत्र की गई। गुरुनानक देव जी द्वारा निकाले गए पानी के स्थान से पानी भी लाया गया है। उन्होंने बताया कि आज भी केवल उसी स्थान पर वहां पानी है और आस-पास सूखा पड़ा है। मिट्टी व पानी को गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के संत बाबा सुक्खा सिंह के हाथों निफा पदाधिकारियों को सौंपा। इस दौरान शिरोमणी गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी गुरुमीत सिंह, संत बाबा सुक्खा सिंह, नरेश बराना, प्रवेश गाबा, इंद्रपाल सिंह उपस्थित रहे।

सेब की लाली पर सिस्टम का 'पीलापन'

केदार दत्त, देहरादून

- उत्तराखंड में सेब की तुड़ाई शुरू, मगर अभी तक पेटियां मिली न एमएसपी ही घोषित
- परिणामस्वरूप, वर्तमान में हिमाचल एप्पल की पेटियों में बिक रहा उत्तराखंड का सेब

उत्तराखंड में सेब की लाली पर सिस्टम का 'पीलापन' भारी पड़ रहा है। सेब की तुड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सेब उत्पादकों को न तो खाली पेटियां मिलीं और न सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ही घोषित हुआ है। नतीजतन, उत्तराखंड का सेब आज भी 'हिमाचल एप्पल' की पेटियों में हिमाचल के नाम से बिक रहा है। यही नहीं, मंडियों में भी किसानों को औने-पौने दामों पर सेब बेचने को विवश होना पड़ रहा है।

प्रमुख नकदी फसलों में शुमार होने के बावजूद उत्तराखंड में सेब पिछले 18 साल से सिस्टम की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रदेश के 11 जिलों के पर्वतीय इलाकों में 25318 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब का उत्पादन होता है, मगर आज तक ब्रांडिंग को गंभीरता से पहल नहीं हो पाई है। हर बार ही सेब उत्पादकों को समय से उत्तराखंड एप्पल के नाम की खाली पेटियां मुहैया कराने की बात होती है, मगर ये शायद ही कभी वक्त पर मिल पाती हों।

इस मर्तबा भी सूरतेहाल कुछ ऐसा ही है। मौसम के साथ देने से इस बार सेब की अच्छी पैदावार है। तुड़ाई भी शुरू हो चुकी है, मगर सेब उत्पादकों को खाली पेटियां उपलब्ध कराने को अभी टेंडर ही हो पाए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि सेब उत्पादकों को एक लाख पेटियां मुहैया कराई जाएंगी, मगर ये कब तक मिलेंगी, यह भविष्य के गर्त में छिपा है।

सूरतेहाल किसानों को मजबूरी में हिमाचल से पेटियां मंगानी पड़ रही हैं। आलम ये है कि राज्य से मिलने वाली पेटियों का इंतजार किए बगैर तमाम सेब उत्पादक औने-पौने दामों पर सेब निकाल रहे हैं। साफ है कि अच्छी फसल के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सिस्टम की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

एमएसपी भी नहीं घोषित : हिमाचल सरकार ने पिछले वर्ष सी ग्रेड के सेब के लिए आठ रुपये प्रति किलो के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया था। इस बार यह अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो इसे लेकर फाइल शासन में इधर से उधर ही सरक रही है। फैसला कब होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई फैसला नहीं होने से व्यापारी मायूस हैं।

प्रति पेटी 50 फीसद अनुदान

उत्तराखंड सरकार की ओर से सेब उत्पादकों को मुहैया कराई जाने वाली खाली पेटियों की प्रति पेटी 99 .50 रुपये की लागत आती है। इस पर राज्य सरकार 50 फीसद अनुदान देती है। यानी किसान को प्रति पेटी 49 .75 रुपये की पड़ती है। दूसरी तरफ, हिमाचल की पेटियां भी करीब- करीब इतने की ही पड़ती हैं और ये वक्त पर मिल जाती हैं।

सेब उत्पादक जिले

जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उत्तरकाशी	8955.03
देहरादून	4894.54
टिहरी	3828.27
पिथौरागढ़	1615.00
अल्मोड़ा	1577.00
नैनीताल	1243.32
चमोली	1201.69
पौड़ी	1127.00
रुद्रप्रयाग	413.50
चंपावत	324.00
बागेश्वर	98.45

'सेब की पैदावार इस बार बहुत अच्छी है। पेटियां उपलब्ध कराने को टेंडर हो चुके हैं और दो सप्ताह के भीतर इन्हें उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। इस बार एक लाख पेटियां सेब उत्पादकों को दी जाएंगी। राज्य की पेटियां हिमाचल प्रदेश से बेहतर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी। जहां तक एमएसपी का प्रश्न है तो इसके लिए मंथन चल रहा है और जल्द ही यह घोषित कर दिया जाएगा।'

- सुबोध उनियाल, उद्यान मंत्री, उत्तराखंड

ऑक्सीजन की खातिर जंगल बनाने में जुटे चार डॉक्टर

विजय सिंह राठौर, ग्वालियर

- 31 बीघा जमीन खरीदी, अब जल्द से जल्द आबाद कर देना चाहते हैं घना जंगल
- पर्यावरण के प्रहरी बने दो चिकित्सक दंपतियों का प्रेरक प्रयास, हजारों पौधे रोपे

पर्यावरण संरक्षण

चंबल के ये चार डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाने की नौबत आए। वे भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। नहीं चाहते कि आने वाले समय में लोगों को बोतलबंद ऑक्सीजन का मोहताज होना पड़े। लिहाजा, जल्द से जल्द घना जंगल बसा देने में जुटे हुए हैं। ताकि प्राणवायु की कमी न होने पाए और जिंदगी हंसी-खुशी चलती रहे। आइये मिलवाते हैं ग्वालियर, मध्यप्रदेश के चिकित्सक दंपती डॉ. डॉ. रवींद्र और डॉ. ऋतिका बंसल व डॉ. अंशुमन और डॉ. सपना सोमानी से।

इन चारों ने 'जहां जगह मिले वहां पौधारोपण' करने का बीड़ा उठाया है। दोनों ही दंपतियों ने पहले अपने घर-आंगन में ही पौधारोपण कर शुरुआत की, लेकिन जब आंगन कम पड़ा तो पैसे जुटाए और टेकनपुर के पास भरतरी और मानपुर गांव से लगती 31 बीघा जमीन खरीदी। यह जमीन केवल और केवल घना जंगल बसाने के इरादे से ही खरीदी गई। वे कहते हैं, इस जमीन का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वीरान पड़ी इस पथरीली जमीन को घने जंगल में तब्दील कर देने की इन्हें इस कदर जल्दी है कि छोटे पौधों की जगह आदमकद हो चुके अपेक्षाकृत पौधे रोपे जा रहे हैं। इनमें आंवला, आम, नीम, पीपल, बरगद जैसे पौधे शामिल हैं, जो घने वृक्ष बन जाएंगे।

चिकित्सकों ने आमजन को भी जागरूक किया है। नतीजा, बीते कुछ ही समय में इस जमीन पर जनसहयोग से दो हजार पौधे रोपे जा चुके हैं। पौधारोपण केवल दिखावा और औपचारिकता न बने बल्कि पौधे पनप कर पेड़ भी बनें, इस बात का हरसंभव इंतजाम भी डॉक्टर दंपती ने किया है। 31 बीघा जमीन के तीन हिस्सों में वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए तीन बड़े गड्ढे कराए गए हैं। तीन बोरिंग भी कराई गई हैं। मोटर के माध्यम से नवरोपित पौधों की सिंचाई निरंतर की जाती है। इन चारों में से एक डॉक्टर रोजाना पौधों की मॉनीटरिंग करने पहुंचते हैं।

डॉ. अंशुमन सोमानी का कहना है कि हम कभी भी यह जमीन नहीं बेचेंगे। यह विचार भी हमारे मन में कतई नहीं आया। यही कारण है कि हम चारों डॉक्टरों के नाम संयुक्त रजिस्ट्री कराई गई है। हमें हमारे द्वारा बनाए गए जंगल से जैविक फल व ताजी सब्जियां मिल सकें, इसे आप हमारा लालच करार दे सकते हैं। वहीं, डॉक्टर बंसल का कहते हैं, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मेरा ख्वाब है कि मैं स्वनिर्मित जंगल में सुंदर चिड़ियों के फोटो खींच सकूं। इस वन में विदेशी पक्षी भी आएं, इसलिए कृत्रिम तालाब आदि बनाने की भी कोशिश करेंगे।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

ग्वालियर के चिकित्सक दंपती डॉ.अंशुमन सोमानी और डॉ.सपना सोमानी। नईदुनिया

डॉ.रवींद्र बंसल और डॉ. ऋतिका बंसल ने आमजन को भी जागरूक किया। नईदुनिया

कोई भी लगाए पौधे, हम करेंगे देखरेख

इस 31 बीघा जमीन को घने जंगल में तब्दील करने के लिए डॉक्टर दंपती ने सभी से अपील की है। डॉ. रवींद्र और डॉ. अंशुमन का कहना है कि कोई भी अपने मन में ये विचार न लाए कि किसी की निजी जमीन पर पौधारोपण क्यों करें। इस जमीन को लोग प्राकृतिक संपदा समझें। कोई भी आकर यहां पौधारोपण कर सकता है और हम वादा करते हैं कि हम उन पौधों को हर संभव सुरक्षा देंगे, उनकी देखरेख करेंगे।

ये है गौरांग महाप्रभु का बैंक, जिसे जरूरत हो ले ले पैसे

जागरण विशेष

गौतम ओझा, धनबाद

जी हां, न गारंटर की जरूरत, न ब्याज देने की बाध्यता। और ना ही पैसे लौटाने का दबाव। हां, दहेज लिया तो दंड के रूप में ली जाती है रकम। धनबाद, झारखंड के ओझाडीह गांव में चलता है यह सौ साल पुराना अनोखा बैंक। नाम है गौरांग महाप्रभु का बैंक।

धनबाद के टुंडी इलाके का ओझाडीह गांव। यहां गौरांग महाप्रभु के नाम पर चल रहे इस अनोखे बैंक का सारा लेन-देन आस्था और विश्वास के नियम-कायदों पर टिका है। न पासबुक की जरूरत, न चेकबुक और एटीएम की। इस बैंक में सारा कारोबार श्रद्धा, आस्था, मानवता और विश्वास के भरोसे ही चलता आया है। करीब 100 साल पहले शुरू हुए इस खास बैंक से इलाके का कोई भी जरूरतमंद लोन ले सकता है। गरीब जरूरतमंद लोग ही यहां से कर्ज लेते हैं। लौटाने की या ब्याज की कोई शर्त नहीं है। पर श्रद्धा के इस लेनदेन में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ने ऋण की रकम वापस न की हो। यही तो इस बैंक की खूबी है। जरूरत पड़ जाने पर गरीब इस दर पर आता है और झोली भर ले जाता है। आस्था और श्रद्धा अपना काम करती हैं। इनके बूते वह गरीब एक दिन अपना कर्ज उतारने में सफल हो ही जाता है। यही नहीं, कर्जदार व्यक्ति खुद ही मूलधन या मूलधन के साथ दान और सहयोग की राशि भी जोड़कर वापस कर देता है।

इस खास बैंक के वित्तीय प्रबंधन और संचालन की बागडोर भी ग्रामीणों के ही हाथ है। कर्ज लौटाने के लिए समयसीमा का भले ही कोई बंधन नहीं हो, लेकिन ऋण देने के लिए साल का एक ही दिन तय है। लगभग एक हजार की आबादी वाले गांव में प्रति वर्ष जेठ महीने में चार दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। इस आयोजन का सारा खर्च गांव वाले उठाते हैं। संकीर्तन संपन्न होते ही ग्रामीण बैठक करते हैं और इसी दिन कुछ घंटे के लिए यह बैंक चलता है। इस मौके पर गांव का हर व्यक्ति सहयोग राशि जमा करता है। इस चंदे की रकम से हरिनाम संकीर्तन का खर्च निकालकर बची रकम गांव के ही जरूरतमंदों को कर्ज के रूप में दी जाती है। किसी को बच्चों के स्कूल में नामांकन के लिए पैसों की जरूरत होती है तो किसी को बेटी की शादी के लिए। कोई घर बनाने के लिए मदद चाहता है तो कोई श्राद्ध कर्म या किसी अन्य जरूरत के लिए। जरूरत चाहे कोई भी हो हर किसी के आवेदन पर सहयोग और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कुछ न कुछ मदद राशि दी जाती है। ग्राम समिति इसका संचालन करती है। बैंक की खास बात ये भी है कि गांव में दहेज लेने और देने वाले से दंड स्वरूप एक निर्धारित राशि वसूलकर उसे नेक काम में लगाया जाता है। यहां दहेज लेने और देने वाले दोनों के लिए दंड निर्धारित है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/jagran-special

धनबाद, झारखंड में बैठक कर लेन-देन के बारे में निर्णय लेते ओझाडीह गांव के लोग। जागरण

गांव वालों ने संचालन के लिए ऐसी तय की है सहयोग राशि

- गांव के हर परिवार से- 350 रुपये
- सरकारी नौकरी करनेवाले-150 रुपये
- पेंशनभोगी कर्मचारी-100 रुपये
- लड़की की शादी के दौरान वर पक्ष को दहेज देने पर उसका एक फीसद राशि का दंड
- लड़के की शादी में दहेज लेने पर दो फीसद की राशि का दंड

अखंड हरिनाम संकीर्तन की परंपरा 100 साल से अधिक पुरानी है। उसके दस्तावेज मौजूद हैं। खुशी है कि पुरखों ने जो परंपरा विकसित की. उसे हम सब आगे बढ़ाकर एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं।

अनादि रक्षित, सचिव, ओझाडीह ग्राम समिति

पहले छकिए शाही लंगर, फिर कीजिए मां के दर्शन

हजारी लाल, होशियारपुर : मेला मैया दा, आउंदा है हर साल...भक्त नचदे ने... शाही लंगर लगदे ने..। जी हां, हर वर्ष सावन माह में लगने वाले मां चिंतपूर्णी के मेले में मिनी काशी होशियारपुर में आस्था का दरिया बहता है। पंजाब व पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की मेहमाननवाजी में मां के सेवादार पलके बिछा देते हैं। वे कदम-दर-कदम शाही लंगर से श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। शाही लंगर में लजीज पकवान मिलते हैं । आस्था का दरिया ऐसा बहता है कि होशियारपुर से लेकर चिंतपूर्णी जी तक दिन-रात मां के जयकारों से वातावरण गूंजता रहता है। मां के भक्त आवाज देते रहते हैं कि शाही लंगर का स्वाद चखना है तो आइए होशियारपुर।

50 किलोमीटर की दूरी में लगते हैं 100 से अधिक लंगर

पहली अगस्त से मां चिंतपूर्णी जी के मेले का आगाज हो गया है। भक्तों की सेवा के लिए पंजाब भर की सैकड़ों लंगर कमेटियां पहुंची हैं। होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी तक की 50 किलोमीटर की दूरी में 100 से अधिक लंगर लगते हैं। इनमें ढाई हजार से अधिक सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा करके पुण्य कमाते हैं। अधिकतर लंगर पूरे नौ दिनों तक चौबीस घंटे चलते हैं। सौ छोटे-बड़े चार से पांच करोड़ रुपये के शाही लंगर माता के दर्शन करने वालों की सेवा में लगते हैं। होशियारपुर के अलावा, मोगा, फरीदकोट, जालंधर, फगवाड़ा, फिल्लौर, अमृतसर व नवांशहर सहित अन्य जिलों की संस्थाएं भी लंगर लगाती हैं। होशियारपुर की हद के भीतर करीब 22 किलोमीटर की दूरी में 80-90 लंगर स्टाल लगते हैं। इनमें 40-50 शाही लंगर स्टाल तो होशियारपुर से ही संबंधित होते हैं।

हर स्टाल पर होते हैं लजीज पकवान : हर स्टाल पर लजीज पकवान होते हैं। रसमलाई, माल पूड़े, रबड़ी, जलेबियां, कढ़ी-चावल, राजमां-चावल, छोले-भटूरे, चने -नान, लच्छेदार नान, आइसक्रीम, पापकोर्न, कुल्फी, सोया चाप, पूड़ी-छोले, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, डोसा, टिक्की, गोलगप्पे, समोसे, चाय-पकौड़े आदि होते हैं।

दस टाइगर रिजर्व का मूल्य ₹6.0 लाख करोड़

देश के बाघों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि के पीछे बनाए गए बाघ रिजर्व का अहम योगदान है। इसके इतर देश के टाइगर रिजर्व के योगदान का आकलन करने के लिए भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनजमेंट के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेज मैनेजमेंट ने देश के दस सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया है। इनका मूल्य 5.96 लाख करोड़ रुपये है जो बीएसई सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से नौ के संयुक्त बाजार मूल्य से अधिक है। वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं।

बाघों के आवास से इतर अहम योगदान

रिजर्व में पेड़ों के रूप में मौजूद कीमती इमारती लकड़ी और उसमें जमा कार्बन (प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से) का भी आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में इनकी कीमत 13,746 करोड़ रुपये से 96,745 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है। यहीं नही भूमि का मूल्य भी 4 .08 लाख रुपये से 7 .41 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच है। वहीं रिजर्व से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ का मूल्य 11,014 करोड़ रुपये और 34,592 करोड़ रुपये के बीच है। इसके अलावा वातावरण से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का भी मूल्य शामिल है। इसका मूल्य 5,095 करोड़ रुपये से 16,202 करोड़ रुपये के बीच है।

लाभों की लंबी फेहरिस्त

रिजर्व के कारण स्वास्थ्य लाभ में न केवल बेहतर जलवायु और स्वच्छ हवा शामिल है, बल्कि अन्य लाभ भी हैं जैसे कि रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा में वृद्धि हुई है। 2016-19 से तीन साल की अवधि में किए गए इस अध्ययन में रोजगार सृजन, ईंधन लकड़ी, पानी और मिट्टी संरक्षण के साथ-साथ जीन पूल संरक्षण के लिए अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को भी ध्यान में रखा गया।

पांच सबसे मूल्यवान टाइगर रिजर्व (करोड़ में)

टाइगर रिजर्व	राज्य	मूल्य
पलामू	झारखंड	1,096,99
मेलघाट	महाराष्ट्र	87,083
नागार्जुन सागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	66,331
सिमलीपाल	ओडिशा	65,863
दुधवा	यूपी	61,202

स्वास्थ्य लाभ में शीर्ष टाइगर रिजर्व (करोड़ में)

रिजर्व	राज्य	मूल्य
नागार्जुन सागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	34,593
सिमलीपाल	ओडिशा	28,897
मेलघाट	महाराष्ट्र	25,380
पलामू	झारखंड	23,101
पाके	अरुणाचल प्रदेश	20,849

शीर्ष नौ कंपनियां

यस बैंक, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, वेदांता, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा)

मंहगा मगर खाली: दिलचस्प बात यह है कि सबसे मूल्यवान टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित पलामू रिजर्व है, जिसमें एक भी बाघ नहीं है। पलामू टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन 1,096,99 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में स्थित 47 बाघों के घर वाला पन्ना टाइगर रिजर्व का मूल्य 20,700 करोड़ रुपये है।

बदले नंबर के साथ पांच से दौड़ेगी गरीब रथ

जासं, लखनऊ : कानपुर-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्री पांच अगस्त से फिर से सस्ता सफर कर सकेंगे। रेलवे ने गरीब एक्सप्रेस को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। अब पांच अगस्त से रेलवे सुपरफास्ट ट्रेन को निरस्त कर उसकी जगह गरीब रथ एक्सप्रेस चलाएगी। इससे यात्रियों का एसी थर्ड का किराया 145 रुपये कम हो जाएगा। हालांकि, इसके लिए रेलवे ने ट्रेन का नंबर बदल दिया है। ट्रेन 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस पांच अगस्त से 18 नवंबर तक परिवर्तित नंबर 12256 गरीब रथ एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। इसी प्रकार 12209 कानपुर सेंट्रल-जम्मूतवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस छह अगस्त से 19 नवंबर तक परिवर्तित नंबर 12255 गरीब रथ बनकर चलेगी।

सुखद

राजकीय उच्च विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मी का सेवानिवृत्ति से सात महीने पहले देखा गया सपना आखिर पूरा हो गया

परी कथा जैसी है कूड़े राम के उड़न खटोले की सवारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

विद्वान कहते हैं कि सपने जरूर देखो और फिर उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से जुट जाओ। कुछ ऐसी ही परी कथा सरीखी है राजकीय उच्च विद्यालय से चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में सेवानिवृत हुए 'गंगा' पुत्र कूड़े राम की कहानी। कूड़े राम ने अपनी सेवानिवृत्ति से सात माह पूर्व जनवरी 2019 में सपना देखा था और जब उड़न खटोले (हेलीकॉप्टर) में बैठ कर विद्यालय से घर पहुंचने का सपना पूरा हो गया, तो आज हर किसी की जुबान पर उनके किस्से के चर्चे है। कहानी के पात्र का नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, पर इसके पीछे भी रोचक किस्सा है।

गंगा जी से जुड़ा है कूड़े राम की जिंदगी का फलसफा : तिगांव खंड के गांव सदपुरा निवासी सरपंच शिवराम के अनुसार उनके बड़े भाई कूड़े राम के जन्म लेने से पूर्व पिता मेदीराम-माता धनवंती की 12 संतान हुई, पर कोई भी लंबी उम्र तक जीवित न रह सका। किसी न किसी कारण से उनकी मौत होती रही। इस पर गांव के ही एक बुजुर्ग ने माता-पिता को सलाह दी थी कि अबकी जब कोई संतान हो, तो उसे एक बार गंगा जी ले जाना और नाम कुछ ऐसा रखना, जो अटपटा सा हो। कूड़े राम का जब जन्म हुआ, तो माता-पिता गंगा स्नान को हरिद्वार गए। वहां नवजात कूड़े राम का भी स्नान कराया गया और बुजुर्ग की सलाह अनुसार नाम कूड़े राम रखा, ताकि किसी की नजर न लगे। इसके बाद गंगा मां की कृपा हुई और कूड़े राम ने लंबी उम्र पाई और फिर शिवराम का भी स्वास्थ्य ठीक रहा।

कूड़े राम की 40 साल पहले 7 अगस्त-1979 को राजकीय मिडिल स्कूल नीमका में चपरासी एवं चौकीदार के रूप में नौकरी लगी थी। तब वेतन था मात्र 266 रुपये। शिवराम के अनुसार क्योंकि हम सब एक गरीब परिवार से थे और तब सस्ता जमाना था, इसलिए भाई की नौकरी से परिवार का भरण-पोषण ठीक तरीके से होने लगा। कूड़े राम के तीन पुत्र ठीक से पढ़ लिख गए, इनमें वीरपाल एक कंपनी में सुपरवाइजर, शीश पाल सर्विस स्टेशन चलाते हैं, तो किरनपाल का टैक्सी का काम है। एक बेटी आशा रानी भी होनहार निकली, शादी तक वो मात्र दसवीं ही पास थी, पर शादी के बाद कड़ी मेहनत कर एमए बीएड तक की पढ़ाई पूरी की।

कूड़े राम (बीच में) हेलीकॉप्टर में बैठने के अपने सपने पूरे होने की कहानी बयां करते हुए। जागरण

इस हेलीकॉप्टर में बैठकर की थी कूड़े राम ने सवारी। फोटो : सरपंच भाई शिवराम के सौजन्य से

मौसम विशेष

राजस्थान में गरज और तेज हवाओं के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति संभव है। दिल्ली सहित शेष मैदानी भागों में भी गरज के साथ अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में वर्षा होगी।

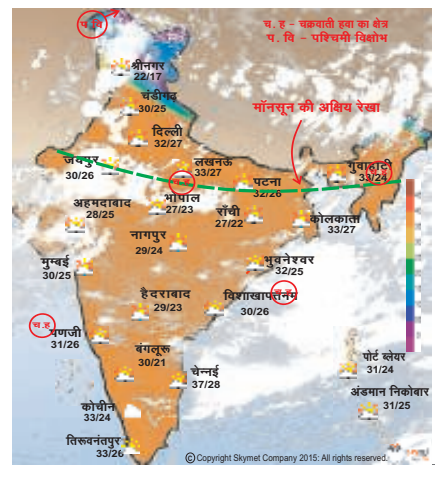

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/24/आंबा अहमदाबाद	34/25/आंबा	
कोलकाता	34/28/आंबा बड़ौदा	30/25/व	
चेन्नई	38/29/आंबा नागपुर	28/24/आंबा	
हैदराबाद	31/24/व इन्दौर	30/23/आंबा	
बंगलूरु	31/21/व रांची	32/26/व	
त्रिवेन्द्रम	33/26/आंबा पटना	38/30/व	
गुवाहाटी	34/28/व जमशेदपुर	35/28/आंबा	
गंगटोक	19/09/आंबा पुणे	23/22/व	

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

शुक्रवार 2 अगस्त 2019

14

www.jagran.com

इराक ने कुवैत पर हमला किया

1990 में आज ही इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद सात महीने तक कुवैत पर उसका कब्जा रहा। यह युद्ध आगे चलकर खाड़ी युद्ध की वजह बना। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों और इराकी सेना के बीच हुआ यह युद्ध 28 फरवरी, 1991 को समाप्त हुआ।

एक ट्रिलियन से अधिक मूल्य वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी एपल

2018 में आज ही दुनिया की चार सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एपल एक ट्रिलियन से अधिक मूल्य वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी थी। 1 अप्रैल, 1976 को स्थापित हुई कंपनी आइफोन, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे उत्पादों का निर्माण करती है।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजायनर थे पिंगली वेंकैया

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजायन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म 1876 में आज ही आंध्र प्रदेश में हुआ था। उर्दू और जापानी समेत कई तरह की भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वह एक प्राणि विज्ञानी, कृषि विद् और शिक्षाविद् थे जिन्होंने मछलीपटनम में कई शैक्षिक संस्थान खोले। हीरे के खनन में विशेषज्ञता हासिल थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में केसरिया और हरा झंडा सामने रखा। जालंधर के लाला हंसराज ने इसमें चर्खा जोड़ा और गांधीजी ने सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ।

इधर-उधर की

साथी नहीं मिला तो कुत्ते से कर ली शादी

लंदन, एजेंसी : ब्रिटेन में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 49 वर्षीय पूर्व स्विमसूट मॉडल एलिजाबेथ होड ने अपने कुत्ते से ही शादी कर ली है, जिसकी उम्र छह साल है। खास बात यह है कि टीवी पर प्रसारित इस शादी को दुनियाभर के लोगों ने देखा। एलिजाबेथ ने पिछले कुछ साल में 200 से भी ज्यादा लोगों को डेट किया, लेकिन उनको मनपंसद साथी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने कुत्ते को ही अपना हमसफर बना लिया। मॉडल एलिजाबेथ का एक 25 साल का बेटा भी है। उनका कहना है कि अब उन्हें किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, अब वो अपनी पूरी जिंदगी अपने कुत्ते लोगान के साथ ही बिताएंगी।

वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाएगा नया मॉडल

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ वर्षों से उत्तरी भारत के राज्यों में 'स्मॉग' बढ़ने से श्वास मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है। साथ ही इसके कारण होने वाले सड़क हादसे भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अब स्मॉग का सीजन आने में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, लेकिन इससे निपटना अभी भी एक चुनौती है। हालांकि, अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसा नया मॉडल विकसित किया है जो वायु प्रदूषण के स्तर का सटीक पूर्वानुमान लगा सकता है।

वैज्ञानिकों ने कहा कि यह मॉडल भारत समेत अन्य देशों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है जहां वायु प्रदूषण से स्थिति गंभीर हो जाती है। नए सांख्यिकी मॉडल (कंप्यूटर मॉडल) के बारे में शोध पत्रिका साइंस एडवांस में विस्तार से बताया गया है। इसमें महासागर से संबंधित कुछ विशेष जलवायु पैटर्न का उपयोग किया जाता है, जो उत्तरी भारत में सर्दियों में वायु प्रदूषण पर प्रभाव डालते हैं।

12 लाख लोगों की हुई मौत : पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सर्वाधिक

अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया सिस्टम। प्रतीकात्मक

प्रदूषित देशों के रूप में उभर रहा है। बीते दिनों यहां ज्यादातर शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) का स्तर 2.5 हो गया था। पिछले साल ही दिल्ली और कई अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में पीएम स्तर 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक था। इस साल की शुरुआत में प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 12 लाख से अधिक लोग मारे गए।

बनाई जा सकती हैं प्रभावी योजनाएं : शोधकर्ताओं ने कहा कि नया मॉडल सर्दियों में वायु प्रदूषण की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने में सरकार की मदद कर सकता है और इससे प्राप्त आंकड़ों मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी योजनाएं बना सकती है।

मॉडल बताएगा कैसी रहेगी हवा: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज मेंग गाओ ने कहा कि हमने प्रदूषण की भविष्यवाणी करने वाला एक सांख्यिकीय मॉडल विकसित किया है, जो सर्दियों के मौसम में तापमान में पाई जाने वाली विविधता का पता लगाकर अनुमान लगता है कि वायुमंडल में हवा की स्थिति कैसी रहेगी। गोओ ने कहा कि सर्दियों में समुद्र की सतह के तापमान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों आधार पर नए मॉडल के जरिये सूचकांकों की गणना की जाती है। इसी के आधार पर नया मॉडल यह बता सकता है कि सर्दियों का वायु प्रदूषण गंभीर होगा या नहीं।

अलनीनो का असर : अध्ययन में पाया है कि अल नीनो और प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव होने से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिकों की मानें तो अल नीनो की वजह से जंगलों की कार्बन डाई ऑक्साइड को सोखने की क्षमता प्रभावित हुई है। यही नहीं इससे पूरी दुनिया में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्र बढ़ती है। शोधकर्ता ने कहा कि भारत का पड़ोसी देश चीन वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों के रूप में उभर रहा है। हर साल यहां सर्दियों में स्मॉग बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है।

फिल्म रिव्यू

रोमांचित करते हैं एक्शन सीन

फास्ट ऐंड फ्यूरियस - हॉब्स ऐंड शॉ

निर्देशन : डेविड लीच
प्रमुख कलाकार : ड्वेन जॉनसन, जेसन स्टेथम, वैनेसा किर्बी, इरदिस अल्बा
अवधि : 2 घंटे 16मिनट

वर्ष 2001 में फिल्म 'फास्ट ऐंड फ्यूरियस' का आगाज हुआ था। उसकी कहानी गैरकानूनी कार रेसिंग, डकैती, पुलिस-चोर के बीच लुकाछुपी से लेकर भाई-बहन के आपसी प्यार के बैकग्राउंड में गढ़ी गई थी। अलग-अलग देशों की सैर कराने, हैरतअंगेज और रोमांचकारी एक्शन, इमोशन और ड्रामा के बीच गढ़ी कहानी हमेशा किरदारों के बीच जमीनी रिश्तों पर लौटती है। इस बार भी उसे कायम रखा गया है। हालांकि 'फास्ट ऐंड फ्यूरियस' की नौवीं किस्त में पहली बार 'स्पिन ऑफ' फिल्म आई है। स्पिन ऑफ में मूल फिल्म के सहयोगी किरदारों के इर्दगिर्द कहानी को गढ़ा जाता है। यह फिल्म सीरीज के चर्चित किरदार हॉब्स और शॉ के ईदगिर्द गढ़ी गई है। यह उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाती है। 'जॉन विक', 'डेडपूल 2' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके डेविड लीच की एंट्री उसे नए स्तर पर ले जाती है। कहानी के शीर्ष पात्र हॉब्स, डेकर्ड शॉ और खलनायक ब्रिक्सटन लार्जर दैन लाइफ हैं। फिल्म में ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टेथम की केमिस्ट्री जहां लुभाती है, वहीं वैनेसा किर्बी के जुड़ने से कहानी में नया मोड़ आता है। साइंस फिक्शन की अवधारणाओं को शामिल कर लेने से हॉब्स और शॉ का स्तर बढ़ा है।

हॉब्स (ड्वेन जॉनसन) अमेरिकी खुफिया एजेंट है, जबकि पूर्व ब्रिटिश सैन्य अधिकारी डेकार्ड शॉ (जेसन स्टेथम) बाद में कुख्यात चोर बन जाता हैं। यहां डेकार्ड नए अवतार में है। यह वह डेकार्ड नहीं है, जो ब्रायन, उसकी गर्भवती पत्नी मिया टोरेटो और उसके दो साल के बेटे को मारने की कोशिश करता है। डेकार्ड ने सरकारी कर्मचारी रहने के दौरान कई काम किए हैं और अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर उनसे दूर हो जाता है। पिछली सीरीज जिन्होंने नहीं देखी है, उन्हें यह समझते देर नहीं लगेगी कि हॉब्स और डेकार्ड एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। उनकी तकरार चलती रहती है। कहानी का सार यह है कि एक-दूसरे को नापसंद करने के बावजूद दोनों दुनिया को बचाने की खातिर टीम के तौर पर काम करना सीखते हैं।

फ्रेंचाइजी का खास आकर्षण हैटी शॉ (वैनेसा किर्बी) हैं, जो एमआइ 6 एजेंट और डेकार्ड की बहन हैं। वह एक घातक वायरस से बचाने के लिए उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती हैं। उसे शरीर से निकालने के लिए खास मशीन की जरूरत होती है। यह वायरस दुनिया को तबाह करने का माद्दा रखता है। साजिश के चलते हैटी को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। वह अपनी पहचान छुपाती घूमती है। हॉब्स उसकी तलाश करता है, वहीं उसका भाई डेकार्ड भी उसकी मदद के लिए आता है। बाद में हॉब्स और डेकार्ड दुनिया को बचाने के लिए एकसाथ आते हैं।

फिल्म में हॉब्स के भावनात्मक और पारिवारिक पक्ष पर फोकस किया गया है। सख्त पुलिस अधिकारी के तौर पर दिखने वाले हॉब्स के बेटी के संबंध को भी इस बार दिखाया गया है। वहीं डेकार्ड का नया अवतार आकर्षक है। किर्बी का किरदार अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नजर नहीं आता है। उन्हें सोलो एक्शन करने का भरपूर मौका मिला है। उसमें वह जंची भी हैं। ब्रिक्सटन की भूमिका में इरदिस अल्बा अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मध्यांतर के बाद के एक्शन दृश्य हैरतअंगेज और अविश्वसनीय हैं, जो रोमांचित भी करते हैं। हिंदी में डब फिल्म में फ्लाइट के दौरान हॉब्स और डेकार्ड के बीच बहस का सीन उबाऊ लगता है। सिनेमैटोग्राफी शानदार है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

विटामिन ए से कम हो सकता है त्वचा कैंसर का खतरा

कैंसर से बचाव में विटामिन ए की भूमिका सामने आई है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि इस विटामिन के सेवन से त्वचा कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष करीब सवा लाख लोगों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। उच्च स्तर पर विटामिन ए की खुराक लेने वालों में स्क्वैमस सेल स्किन कैंसर के खतरे में 15 फीसद तक की कमी पाई गई। स्क्वैमस सेल स्किन कैंसर त्वचा कैंसर का एक प्रकार है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर यूजुंग चो ने कहा, 'ये नतीजे इस वजह को और पुख्ता करते हैं कि फलों और सब्जियों से भरपूर आहार कितना जरूरी होता है। फल और सब्जी आधारित विटामिन ए सुरक्षित होता है।' अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, गाजर, पालक, दुग्ध उत्पाद, मछली और मीट को विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। -प्रेट्र

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने वाली दवा बढ़ाती हृदयरोग का खतरा

आप हृदयरोग से ग्रस्त रह चुके हैं और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है तो डॉक्टर आपको स्टेटिंस दवा लेने की सलाह देते हैं। यह दवा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करती है बल्कि हृदय संबंधी रोगों के खतरे को भी कम करती है। लेकिन बीच में ही स्टेटिंस छोड़ना घातक हो सकता है। ऐसा करने से हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 'यूरोपियन हार्ट जर्नल' में छपे शोध में यह दावा किया गया है। अध्ययन में शामिल डॉ फिलिप गिरल ने कहा, जो मरीज कई साल या महीने से लगातार स्टेटिंस का सेवन कर रहे हैं उन्हें उपचार तब नहीं छोड़ना चाहिए जब उनकी उम्र 75 हो गई है। इससे उनके हृदय पर उल्टा असर पड़ सकता है।' इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक लाख 20 हजार लोगों पर शोध किया गया। उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी और वह सभी स्टेटिंस का सेवन कर रहे थे। (एएनआइ)

कागज-पेंसिल से बनाया पोर्टेबल हीटर

तकनीक ▶ पुणे की सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया उपकरण

कम तापमान की जरूरत वाले कामों में होगा इस्तेमाल

वास्को-द-गामा (गोवा), आइएसडब्ल्यू : भारतीय वैज्ञानिकों ने कागज और पेंसिल की मदद से एक छोटा पोर्टेबल हीटर बनाया है। इसका उपयोग ऐसे कार्यों में किया जा सकेगा, जिनमें कम तापमान की जरूरत होती है। कागज-आधारित हीटर बनाने की यह तकनीक पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। यह अध्ययन 'करंट साइंस' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

कैसे बनाया हीटर : यह हीटर पेंसिल और नोटबुक के कागज के साथ एल्यूमीनियम फॉइल, तांबे के तार, ग्लास शीट, पेपर बाईंडिंग क्लिप और बैटरी को जोड़कर बनाया गया है। सबसे पहले, 75 माइक्रोमीटर मोटाई के सामान्य कागज के दो इंच लंबे और डेढ़ इंच चौड़े टुकड़े की एक सतह पर 9बी ग्रेड पेंसिल से गहरी शेडिंग की गई और फिर इस कागज को 0.2 सेंटीमीटर मोटी ग्लास शीटों के बीच रखा गया। फिर, इस प्लेट को एल्युमीनियम

हीटर से इस तरह होगी हाथ की सिकाई (बाएं), शोधकर्ता अमित मोरारका और डॉ. अदिति सी. जोशी।

फॉइल और तांबे के तार द्वारा 5 वोल्ट वाले बैटरी परिपथ से जोड़ा गया। इस हीटरनुमा संरचना को दो बाईंडिंग क्लिपों की मदद से कसकर स्थिर किया था, ताकि एल्युमिनियम फॉइल और तांबे के तार का पेंसिल से बनी ग्रेफाइट मिश्रित परतों के बीच सही संपर्क स्थापित हो सके। हीटर में लगा कागज उसमें लेपित पेंसिल की ग्रेफाइट परत के कारण विद्युत प्रवाहित होने से गर्म होने लगता है, जिससे ग्लास शीट गर्म हो जाती है। इस तरह यह संरचना हीटर की भांति काम करती है।

15 से ज्यादा बार इस्तेमाल होगी एक शीट : हीटर बनाने के लिए कागज और ग्लास शीट की जगह ओवरहेड प्रोजेक्टर की ट्रांसपेरेंसी शीट तथा धातु प्लेटों को भी उपयोगी पाया गया है। इस प्रकार बने पोर्टेबल हीटर में अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि, कागज से बने हीटर का अधिकतम तापमान 100 डिग्री तक पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, हीटर में एक कागज या ट्रांसपेरेंसी शीट का लगभग पंद्रह से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है।

नहीं लगेगा करंट : प्रमुख शोधकर्ता अमित मोरारका ने बताया कि लगभग 218-246 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कागज जलने लगता है। इस पोर्टेबल हीटर में अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच पाता है, जिसके कारण इसमें कागज जलता नहीं है। इस हीटर में कम वोल्टेज की बैटरी या डीसी विद्युतधारा का प्रयोग किया गया है, जिससे बिजली का झटका लगने का खतरा भी नहीं है।

मांसपेशियों की हो सकती है सिकाई : शोधकर्ताओं का कहना है कि इस हीटर का एक आसानी से मुड़ने वाला लचीला स्वरूप भी तैयार किया गया है, जिसका उपयोग शरीर में जोड़ों और मांसपेशियों की सिकाई में किया जा सकता है। बैटरी से संचालित होने के कारण इसका इस्तेमाल दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में विद्युत संबंधी नियमों को समझाने और प्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हीटर बनाने की यह नई तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ सुरक्षित, सस्ती और सरल है। शोधकर्ताओं में अमित मोरारका के अलावा डॉ. अदिति सी. जोशी शामिल हैं।

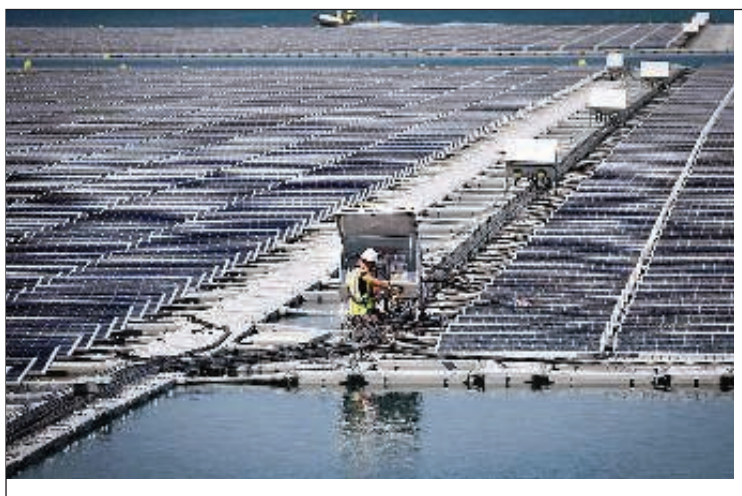

सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पॉवर प्लांट

फ्रांस के पायोलेंक इलाके में स्थित पॉवर प्लांट 'ओ मेगा 1' में फोटोवोल्टिक सोलर पैनल पर काम करता तकनीशियन। यह यूरोप का सबसे बड़ा और फ्रांस का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी फार्म है। आगामी सितंबर 2019 से यह काम करना शुरू कर देगा। इसकी क्षमता 17 मेगावाट है। इसमें 47 हजार फोटोवोल्टिक पैनल लगे हैं जो कि झील की सतह पर 17 हजार हेक्टेयर में है। इससे 4700 से ज्यादा घरों में बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। एएफपी

72 मीटर लंबा सैंडविच..

उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में पारंपरिक सैंडविच के सालाना उत्सव में एक बड़ा 'टोरटा' (सैंडविच) बनाया गया। आयोजकों के मुताबिक इसकी लंबाई 72 मीटर है। दावा किया गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 'टोरटा' है और एक विश्व रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के बाद इसके टुकड़े करके मौजूद लोगों में वितरित कर दिया गया। रायटर

स्क्रीन शॉट

शाह रुख की राह पर अनुष्का!

अभिनेत्री और क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली की जीवनसंगिनी अनुष्का शर्मा पिछली फिल्म 'जीरो' में दिखाई दी थीं, लेकिन फिल्म नहीं चली। उसके बाद से फिल्म के मुख्य कलाकार शाह रुख खान की तरह ही अनुष्का ने भी एक भी फिल्म के लिए हां नहीं कही। शाह रुख की तरह वे भी अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण में लगी रही हैं। हालांकि हाल ही में एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कहा, 'फिल्म 'जीरो' करने का मेरा निर्णय काफी सावधानी भरा था।' शादी के बाद अनुष्का ने तुरंत अपनी फिल्म 'सुई धागा' को पूरा करने में तत्परता दिखाई। उसके बाद उन्होंने 'जीरो' को पूरा किया। इस बीच वह विराट से भी मिलती रहीं। हालांकि अभिनेत्री ने अपनी टीम से यह भी कहा था कि मैं दो महीनों तक किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं चाहती हूं। ऐसे में जब अनुष्का से यह पूछा गया कि कैसे वह और विराट मिलने का समय निकाल पाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, 'हम दोनों में से कोई भी काम के नुकसान की कीमत पर आपस में मिलने का प्रयास नहीं करता है। शादी में कई बातों को सम्मान देने की जरूरत होती है और हम ऐसा करते हैं' अनुष्का ने विराट के मैदान में आक्रामक और मैदान के बाहर शांतचित्त होने की भी बात कही।

साल के अंत तक शुरू होगी पृथ्वीराज चौहान पर आधारित फिल्म की शूटिंग

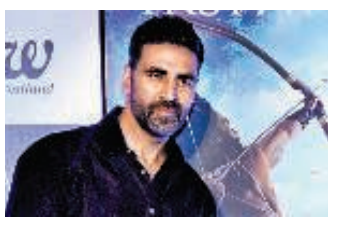

ऐतिहासिक फिल्में बॉलीवुड का हिट फॉर्मूला साबित हो रही हैं। एक ओर अर्जुन कपूर फिल्म 'पानीपत' और अजय देवगन 'तानाजी' फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहीं अब खबरें आ रही हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर आधारित फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। अक्षय शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के किरदार में होंगे। पिछले कुछ समय से अक्षय अपनी फिल्मों में लगातार व्यस्त रहे हैं। फिल्म 'केसरी' के बाद उनकी 'हाउसफुल 4', 'मिशन मंगल' और 'लक्ष्मी बॉम्ब' फिल्में आ रही हैं। उन्होंने 'बच्चन पांडे' का पोस्टर भी जारी कर दिया है। उनकी व्यस्तता के कारण पृथ्वीराज चौहान वाली फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी थी। खबरों के मुताबिक, साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। 'केसरी' के बाद अक्षय की यह तीसरी पीरियड फिल्म होगी। उनकी आगामी फिल्म 'हाउसफुल 4' भी पीरियड फिल्मों में शुमार है। इसकी पुनर्जन्म पर आधारित कहानी पिछले दौर में ले जाएगी। पृथ्वीराज चौहान फिल्म का निर्माण यशराज बैनर कर रहा है, जबकि फिल्म का निर्देशन 'पिंजर' के निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी करेंगे।

सनी देयोल ने 'गदर' की तुलना 'स्टार वार्स' से की!

बॉलीवुड में जबर्दस्त एक्शन और संवाद अदायगी के चलते दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले अभिनेता सनी देयोल की फिल्म 'गदर : एक प्रेम कथा' को आज भी बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल किया जाता है। इस फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला दृश्य हो या अशरफ अली के साथ संवाद करने का दृश्य, दर्शक आज भी उन दृश्यों को पूरे रोमांच के साथ देखते हैं। हिंदी सिनेमा में अपने संवाद ढाई किलो का हाथ... के लिए मशहूर सनी देयोल से जब यह पूछा गया कि क्या वह अपने बेटे करण देयोल को इस फिल्म की फ्रेंचाइजी में लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है, तो वह फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने 'गदर : एक प्रेम कथा' की तुलना हॉलीवुड की फ्रेंचाइजी फिल्म 'स्टार्स वार्स' के साथ की। 'गदर' की फ्रेंचाइजी के निर्माण के बारे में सनी ने कहा, 'गदर की अगली कड़ी में करण को लाने का काफी खूबसूरत आइडिया है, पर यदि अच्छा विषय मिला तभी यह संभव हो पाएगा। हॉलीवुड फिल्म 'स्टार्स वार्स' की तरह इस फिल्म को भी पूरे देश के लोगों ने देखा था। इसमें लोगों ने भारत-पाक का ड्रामा देखा और यह एक रोमांटिक कहानी भी थी। इसका विषय इतना अच्छा था कि इसे लोगों ने सिर-आंखों पर लिया।' सनी ने कहा, 'ऐसा ही विषय मिला, तभी अगली कड़ी बनाई जानी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि फिल्म को फास्ट फूड में परिणत नहीं करना चाहिए। हर किसी को हिट की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं परोसा जाना चाहिए।'

अध्ययन

'जियोफिजिकल रिसर्च' में प्रकाशित हुआ टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का अध्ययन, बर्फीले ग्रहों की भूमध्य रेखाओं के पास के क्षेत्रों में हो सकता है रहने योग्य तापमान...

बर्फीले ग्रहों पर भी संभव हो सकता है जीवन

टोरंटो, प्रेट्र : सौरमंडल में जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह हमारी पृथ्वी है। वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि पृथ्वी के आकार वाले बर्फीले ग्रहों पर भी कुछ क्षेत्र रहने योग्य हो सकते हैं। काफी समय तक वैज्ञानिक यह सोचते आए हैं कि पृथ्वी जैसे आकार वाले जमे हुए ग्रहों पर जीवन मुमकिन ही नहीं हो सकता है क्योंकि इन ग्रहों पर मौजूद महासागर जमे हुए हैं और अत्यधिक ठंड जीवन की संभावनाओं को खत्म कर देती है। लेकिन नया अध्ययन हमारी उस सोच को चुनौती देता है जिसमें हमें यह लगता है कि अत्यधिक ठंडे और गर्म ग्रहों में जीवन संभव ही नहीं हो सकता।

जियोफिजिकल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुए नए अध्ययन के अनुसार, बर्फीले ग्रहों की भूमध्य रेखाओं के पास के क्षेत्रों में रहने योग्य तापमान भी मौजूद हो सकता है। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में खगोल और भौतिक विज्ञानी एडिव पैराडाइस ने बताया कि हमारी खोज में कुछ ऐसे ग्रह मिले हैं जो बर्फीले हैं। परंपरागत रूप से इनको रहने योग्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन नया अध्ययन हमें यह सुझाव देता है कि शायद वे ग्रह रहने योग्य हो सकते

पृथ्वी दो बार हिमयुग के दौर से गुजरी है। प्रतीकात्मक

हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये रहने योग्य क्षेत्र एक तारे की विशिष्ट दूरी से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से वहां का तापमान सामान्य और पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है।

बर्फीली अवस्था से गुजरी है पृथ्वी : शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारी पृथ्वी भी दो से तीन बार हिम युग (आइस एज) से गुजरी है, लेकिन फिर भी यहां जीवन बच गया। हिम युग में भी सूक्ष्म जीव बचे रहे। अध्ययन के प्रमुख लेखक पैराडाइस ने बताया कि पृथ्वी अपने हिमयुग के दौरान भी रहने योग्य थी। यहां जीवन हिमयुग से पहले पनपा था। यह हिमयुग और उसके बाद भी बरकरार रहा।

कंप्यूटर मॉडल से किया अध्ययन : वैज्ञानिकों ने बर्फीले ग्रहों में रहने योग्य कारणों का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का सहारा लिया, जिसमें सूर्य की रोशनी की मौजूदगी और क्षेत्रों के आकार के आधार पर मॉडल बनाए गए। सबसे विशेष चीज जिस पर वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया वह कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रहों में गर्मी रहती है और जलवायु परिवर्तन भी होता है।

इसके बिना ग्रहों के महासागर जम जाते हैं वे बेजान हो जाते हैं। जब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है तो ग्रह स्नोबॉल यानी बर्फीले हो जाते हैं। लेकिन जब इन ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनकी भूमध्य रेखाओं के आसपास के क्षेत्रों में बर्फ के पानी बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि बर्फीले ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है।